FOCUS NEWS
फोकस न्यूज

facebook.com/fnind
x.com/fnind
focusnewsindia.blogspot.in

www.focusnews.co.in
@FocusnewsIn

...आपका अपना अखबार

राष्ट्रीय संस्करण। नई दिल्ली। शुक्रवार 13 जून 2025। तृतीया, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष। 2081 विक्रम संवत । पेज – 12 । मूल्य 2 रु । वर्ष : 12। अंक : 330

दिल्ली के चिड़ियाघर ने पशु देखभाल और कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए वनतारा के साथ साझेदारी की

दिल्ली में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, पशु कल्याण संगठन 'वनतारा' के साथ साझेदारी में चिड़ियाघर में पशुओं की देखभाल, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और समग्र प्रबंधन में सुधार की दिशा में काम करेगा।

आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में तिलक वर्मा तीसरे स्थान पर पहुंचे

तिलक वर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में एक स्थान के फायदे से तीसरे स्थान पर हैं जबकि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई गेंदबाजी रैंकिंग में क्रमशः तीसरे और सातवें स्थान पर बने हुए हैं।

उप्र वन बल को एआई तकनीक एवं सेंसर युक्त कैमरों से लैस करेगी सरकार

प्रदेश सरकार वन संरक्षण और वन्यजीव अपराधों की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश वन बल को कृत्रिम मेधा (एआई) तकनीक एवं सेंसर युक्त कैमरों से लैस कर आधुनिक करने की योजना पर काम कर रही है।

डिजिटल भारत से आत्मनिर्भर भारत तक: नई शक्ति, नई सोच

9 जून 2025 को केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 11 वर्ष पूरे हुए। यह केवल एक राजनीतिक सफर नहीं, बल्कि "न्यू इंडिया" की वो विकास यात्रा है, जिसमें तकनीक, आत्मनिर्भरता, सुशासन और सुरक्षा– सब एक साथ कदमताल करते दिखाई देते हैं।

हाउसफुल फ्रेंचाइजी बनी सुपरहिट, कर डाली तगड़ी कमाई, छू लिया 963 करोड़ का मुकाम

'हाउसफुल 5' वैसे तो कमाई में गोली की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग्स के मामले में फिसड्डी साबित हुई है। 'हाउसफुल 5' में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, ऋतिश देशमुख, संजय दत्त, नाना पाटेकर, फरदीन खान, सोनम बाजवा और जैकलीन फर्नांडिस जैसी कास्ट मौजूद है।

पायलट के साथ संबंधों पर बोले गहलोत: 'हम लोग दूर कब थे'

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के साथ अपने रिश्तों में किसी तरह की खटास की अटकलों को खारिज करते हुए बुधवार को कहा, "दूर कब थे हम लोग? हम कभी दूर थे ही नहीं।"

प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाकर लोगों को अनगिनत फायदे पहुंचाए गए : मोदी

। कृष्णा अग्रवाल ।

नयी दिल्ली, फोकस न्यूज, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार ने अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाकर लोगों को अनगिनत फायदे पहुंचाए हैं। मोदी ने 'एक्स' पर कहा, ''भारत के युवाओं की मदद से हम नवाचार और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं। इससे आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनने के हमारे प्रयासों को भी मजबूती मिल रही है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग ने सेवा प्रदान करने और पारदर्शिता को बहुत बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी गरीब से गरीब लोगों के जीवन को सशक्त बनाने का एक साधन बन गई है। सरकार के हैंडल से जारी किए गए और प्रधानमंत्री द्वारा रेखांकित पोस्ट की एक श्रृंखला में कहा गया है कि भारत ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से बड़े पैमाने पर पारदर्शिता सुनिश्चित की है, जिसमें कहा गया है कि 56 मंत्रालयों द्वारा विनियमित 322 से अधिक योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में 44 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा की गई। इसमें कहा गया है कि लीकेज को समाप्त करके 3.48 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत की गई। एक अन्य 'थ्रेड' में कहा गया है कि पिछले 11 वर्षों में भारत की तकनीकी यात्रा क्रांति से कम नहीं है। इसमें कहा गया है कि मोदी के नेतृत्व में भारत डिजिटल नवाचार, तकनीक आधारित शासन और वैश्विक विश्वास का केंद्र बन गया है। (शेष पेज दो पर)

मोदी सरकार ने 11 साल के शासन में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को लोकतांत्रिक बनाया: अमित शाह

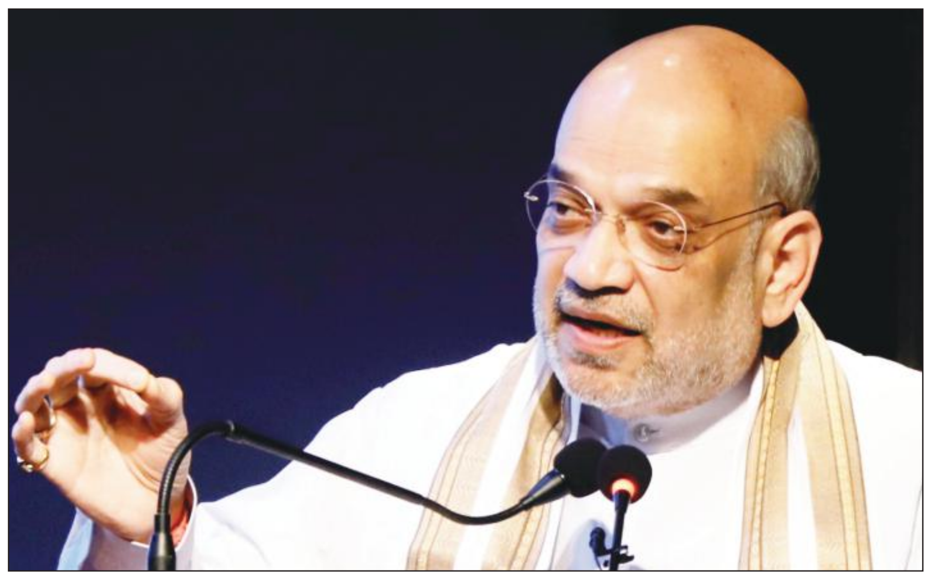

नयी दिल्ली, फोकस न्यूज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि मोदी सरकार ने प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाया है और व्यापार क्षेत्र के लिए इसकी शक्ति का इस्तेमाल किया है, जिससे भारत पिछले 11 वर्षों में दुनिया में एक अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के नौ जून को 11 साल पूरे हो गए। शाह ने 'एक्स' पर लिखा, "मोदी सरकार ने प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाया है और व्यापार क्षेत्र के लिए इसकी शक्ति का दोहन किया है, जिससे भारत बीते 11 साल में दुनिया में एक अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्था बन गया है।" गृह मंत्री ने कहा कि चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो, व्यापार हो या वाणिज्य, प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल क्रांति के माध्यम से अर्थव्यवस्था और समाज के हर क्षेत्र को बदल दिया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पिछले 11 वर्षों में, भारत ने डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाने की दिशा में अपनी यात्रा में उल्लेखनीय प्रगति की है। बयान में कहा गया है कि देश ने दूरदराज के गांवों में इंटरनेट पहुंच का विस्तार करने से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में क्रांति लाकर शहरी–ग्रामीण विभाजन को पाट दिया है। बयान में कहा गया है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024–25 तक बढ़कर 13.42 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रगति से प्रेरित है। बयान के अनुसार, डिजिटल (शेष पेज दो पर)

तालकटोरा का नाम बदलने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास लंबित : प्रवेश वर्मा

नयी दिल्ली, (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम का नाम बदल कर 'महर्षि बाल्मीकि स्टेडियम' करने का प्रस्ताव मंजूरी के लिये केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित है। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को एनडीएमसी की अगली बैठक में पारित कर दिया जायेगा। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने इसकी जानकारी दी। एनडीएमसी परिषद की बैठक के बाद वर्मा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ''मैने केंद्रीय गृह मंत्री से बात की है। यह मामला उनके पास लंबित है। वहां से जब भी इसे स्वीकृति मिल जायेगी, हम इसे एनडीएमसी परिषद (शेष पेज दो पर)

मेरा एकमात्र लक्ष्य ओडिशा के लोगों की सेवा करना है: माझी

भुवनेश्वर, फोकस न्यूज, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि राज्य के लोगों की सेवा करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार के शासन का एक वर्ष पूरा होने अवसर पर माझी ने यह बात कही। माझी ने 12 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "आज से एक वर्ष पूर्व, भगवान जगन्नाथ की कृपा और आप सभी के विश्वास एवं समर्थन से हमने सरकार बनाई थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मैंने ओडिशा की इस पावन भूमि पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।" उन्होंने लिखा, "जनसेवा (शेष पेज दो पर)

छात्र सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें : योगी आदित्यनाथ

लखनऊ, फोकस न्यूज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों से सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने का आग्रह करते हुए कहा कि ऐसी संपत्ति सामूहिक प्रयास का परिणाम है और किसी भी परिस्थिति में इसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। मेधावी छात्रों को सम्मानित करने और स्कूल खेल पुरस्कार वितरित करने के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ''सार्वजनिक संपत्ति निजी संपत्ति नहीं है – यह पूरे समाज के योगदान से बनी है। अगर कोई इसे नुकसान पहुंचाता है तो वह देश को नुकसान पहुंचा रहा है। इस तरह के कृत्यों को रोका जाना चाहिए, सूचना दी जानी चाहिए और उजागर किया जाना चाहिए।'' आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों से सार्वजनिक (शेष पेज दो पर)

बांके बिहारी कॉरिडोर : प्रभावित सेवायतों को रुक्मिणी विहार में बसाएगी सरकार

मथुरा (उप्र), मथुरा जिले में वृन्दावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के आसपास साढ़े पांच एकड़ क्षेत्र में कॉरिडोर बनाने की योजना के क्रियान्वयन से प्रभावित होने वाले सेवायतों, गोस्वामियों और स्थानीय निवासियों को रुक्मिणी विहार और सुनरख बांगर में बसाने का निर्णय लिया गया है। एक आधिकाारिक बयान में यह जानकारी दी गई। जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने बताया कि कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वास हेतु मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा रुक्मिणी विहार और सुनरख बांगर में 275 परिवारों के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है जहां उनकी मांग के अनुसार फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इनमें वे 200 दुकानदार भी शामिल हैं जिनकी दुकानें कॉरिडोर के दायरे में आ रही हैं। सिंह ने बताया कि सभी प्रभावित दुकानदारों को कॉरिडोर में बनने वाली दुकानें आवंटित की जाएंगी और इसी प्रकार गोस्वामियों को सुनरख बांगर अथवा रुक्मिणी विहार में से किसी एक जगह बसने का विकल्प दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी प्रभावित लोगों को जमीन और भवन के अनुसार मुआवजा भी दिया जाएगा। (शेष पेज दो पर)

टैक्स जमा करने वालों के लिए 15 जून की डेडलाइन आखिर क्यों है खास, चूके तो पड़ेगा महंगा

अगर आप एक टैक्सपेयर हैं और आप पर एडवांस टैक्स देयता बनती है तो आपको 15 जून का खास ध्यान रखना चाहिए। यह एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख है। अगर आप समय पर अपना यह टैक्स जमा नहीं करते हैं तो यह आपको महंगा पड़ सकता है। एडवांस टैक्स इनकम टैक्स की वह राशि है जो साल के आखिर में एकमुश्त भुगतान के बजाय अग्रिम रूप से चुकाई जाती है। इसे आयकर के रूप में भी जाना जाता है। एडवांस टैक्स का पेमेंट आयकर विभाग द्वारा तय की गई नियत तारीखों के मुताबिक किस्तों में किया जाता है।

किसको करना होता है एडवांस टैक्स जमा : एक वित्तीय वर्ष में ₹ 10,000 या उससे ज्यादा की अनुमानित कर देयता वाले हर करदाता को एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है। आईसीआईसीआई बैंक के मुताबिक, वेतनभोगी व्यक्ति अपनी नौकरी से अर्जित आय पर एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। फ्रीलांसर सालभर में हासिल की गई अपनी विभिन्न आय के स्रोतों पर एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। व्यवसायी अपनी कंपनी के जरिये हासिल इनकम पर धारा 44एडी की टैक्सेशन योजना के तहत एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते (शेष पेज दो पर)

दूर करना चाहते हैं विटामिन डी की कमी, तो पिएं औषधीय गुणों से भरपूर ये जूस

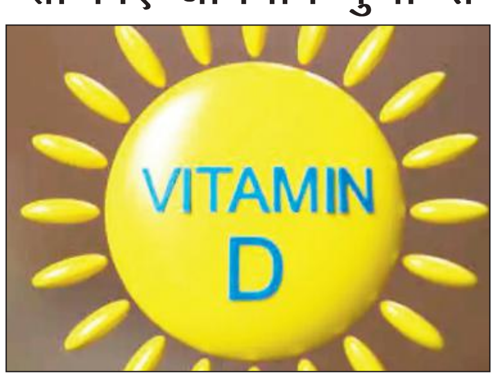

अगर आपने विटामिन डी की कमी को समय रहते दूर नहीं किया, तो आप सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का शिकार बन सकते हैं। हेल्थ एक्सपट्र्स के मुताबिक विटामिन डी की कमी से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ धूप में बैठना काफी नहीं है। इस जरूरी विटामिन की कमी को दूर करने के लिए आपको अपने डाइट प्लान में थोड़े बहुत बदलाव करने की जरूरत है। आइए जानते हैं कैसे...

फायदेमंद साबित होगा संतरे का जूस : क्या आप जानते हैं कि संतरे के जूस में विटामिन डी समेत कई पोषक तत्वों की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है? हेल्थ एक्सपट्र्स विटामिन डी की कमी से जूझ रहे लोगों को अक्सर फोर्टिफाइड संतरे का जूस पीने की सलाह देते हैं। संतरे के जूस में विटामिन डी (शेष पेज दो पर)

तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्थापित किए गए कैलाश मानसरोवर भवन, जानें इसमें क्या–क्या हैं फैसिलिटी?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच साल पहले कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण किया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कई श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्सुकता देखी जाती है। तीर्थ यात्री इंदिरापुरम के कैलाश मानसरोवर भवन में पहुंचने लगे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 जून को यात्रियों का पहला जत्था कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए रवाना होने वाला है।

सुधारी गईं व्यवस्थाएं : नगर निगम और पर्यटन निगम पिछले कई दिनों से कैलाश मानसरोवर भवन की व्यवस्थाओं को ठीक करने में जुटे हुए थे। यात्रियों के पहुंचने से पहले कैलाश मानसरोवर भवन की व्यवस्थाओं (शेष पेज दो पर)

प्रौद्योगिकी की... (पेज एक का शेष) विनिर्माण से लेकर अंतरिक्ष तकनीक तक, डिजिटल भुगतान से लेकर ग्रामीण संपर्क तक यह परिवर्तन स्पष्ट, प्रभावशाली और स्थायी है। उसने कहा, ''लेकिन यह केवल उपकरणों और प्लेटफार्मों के बारे में नहीं है। यह निर्बाध शासन, नागरिक सशक्तीकरण और विकसित भारत के निर्माण के बारे में है।'' इसमें लिखा गया है कि यूपीआई के भारत की 'वित्तीय धड़कन' बनने से लेकर देश, दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डेटा प्रदाता भी है, जो डिजिटल समावेश को बढ़ावा देता है। 'थ्रेड' के अनुसार 94 करोड़ से अधिक ब्रॉडबैंड कनेक्शन और 120 करोड़ टेलीफोन ग्राहकों के साथ, टेली–डेंसिटी 2014 में 75 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 85 प्रतिशत हो गई है। इसमें कहा गया कि इसरो द्वारा 393 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की अविश्वसनीय उपलब्धि हमारी क्षमता को दर्शाती है। एक पोस्ट में कहा गया है, ''11 साल पहले, एक खामोश डिजिटल क्रांति शुरू हुई – जिसने भारत के जुड़ने, शासन करने और बढ़ने के तरीके को नया आकार दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, डिजिटल इंडिया पहल ने प्रौद्योगिकी को सशक्तिकरण के एक उपकरण में बदल दिया है – अंतराल को पाटना, अवसरों को खोलना और प्रत्येक नागरिक के लिए शासन को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाना।'' इसमें कहा गया है, ''दूरदराज के गांवों में इंटरनेट की पहुंच से लेकर दुनिया में अग्रणी वास्तविक समय के डिजिटल भुगतान तक, यह परिवर्तन केवल संख्याओं के बारे में नहीं है – यह लोगों, प्रगति और संभावना के बारे में है।'' इसके अनुसार तकनीकी पहलों ने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक रुपया लक्षित लाभार्थी तक पहुंचे, डीबीटी में 10 वर्षों में 90 गुना वृद्धि देखी गई, जिससे गति और पारदर्शिता के साथ कल्याणकारी आपूर्ति तंत्र में बदलाव आया। इसमें सरकारी खरीद के लिए डिजिटल मार्केटप्लेस, पासपोर्ट वितरण सेवा, कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के लिए कोविन प्लेटफॉर्म की शुरुआत और नागरिकों को लाभ और सेवाएं प्रदान करने में तकनीक द्वारा संचालित अन्य उपायों के अलावा स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पर प्रकाश डाला गया।

मोदी सरकार... (पेज एक का शेष) अर्थव्यवस्था ने 2022–23 में राष्ट्रीय आय में 11.74 प्रतिशत का योगदान दिया। आगे बयान में कहा गया है कि मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और पिछले 11 वर्षों में भारत ने मोबाइल नेटवर्क का काफी विस्तार किया है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार किया है। बयान के अनुसार, प्रौद्योगिकी आधारित भविष्य के लिए सरकार ने पिछले 11 वर्षों में डिजिटल क्षितिज का विस्तार किया है, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने से लेकर डिजिटल कौशल को बढ़ाने तक, भारत अधिक डिजिटल रूप से सक्षम हुआ है। बयान में कहा गया है कि इंटरनेट कनेक्शन मार्च 2014 में 25.15 करोड़ थे, जो जून 2024 में बढ़कर 96.96 करोड़ हो गए। इसके अलावा मई 2025 तक, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरित कुल राशि 44 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है।

तालकटोरा का... (पेज एक का शेष) की अगली बैठक में पारित कर देंगे।'' वर्मा ने इस साल दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्टेडियम का नाम रखने का वादा किया था। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। तालकटोरा स्टेडियम, राजधानी का एक प्रमुख इनडोर खेल स्थल है, जिसका नाम पास के मुगलकालीन उद्यान से लिया गया है।

मेरा एकमात्र... (पेज एक का शेष) ही मेरा एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य है... मैंने स्वयंसेवक, शिक्षक, सरपंच, विधायक और अब मुख्यमंत्री के रूप में लगातार आपकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किया है और करता रहूंगा।" माझी ने कहा कि 12 जून ओडिशा के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि लोगों ने बीजू जनता दल की प्रचार प्रसार वाली सरकार को हटाकर भाजपा को जनादेश दिया है। उन्होंने कहा, ''सरकार बनने के एक साल के भीतर हमने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह उम्मीद है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाला एक साधारण परिवार का बच्चा भी एक दिन मुख्यमंत्री बन सकता है।" माझी ने कहा, "मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने सबसे पहले कहा कि हमारी सरकार जनता की सरकार है। इसलिए मैं हमेशा आप तक पहुंचने, आपसे जुड़ने, जमीनी स्तर पर आपकी समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने की पूरी कोशिश करता हूं।"

बांके बिहारी... (पेज एक का शेष) प्रस्तावित आवासीय योजना की जानकारी देते हुए मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह ने बताया कि रुक्मिणी विहार आवासीय योजना हेतु चार बड़े भूखंड चयनित किए गए हैं जहां एक और दो कक्ष वाले 325–350 फ्लैट तैयार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर आसपास के क्षेत्र में जमीन चिह्नित कर फ्लैट की संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। सिंह ने बताया कि सेवायत गोस्वामियों को कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए सहमत किए जाने के साथ पूरे इलाके में सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी जोर–शोर से जारी है और अब तक अधिकांश प्रभावित परिवार, व्यापारी व सामाजिक संगठन कॉरिडोर निर्माण के लिए सहमति दे चुके हैं।

अहमदाबाद विमान हादसा: गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रुपाणी सहित कम से कम 265 लोगों की मौत

अहमदाबाद, (भाषा) एअर इंडिया का लंदन जा रहा विमान बृहस्पतिवार दोपहर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद यहां एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कम से कम 265 लोग मारे गए। विमान में दो पायलट और चालक दल के 10 सदस्य सहित 242 लोग सवार थे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सीआर पाटिल के अनुसार, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी भी मृतकों में शामिल हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि विश्वाश कुमार रमेश नामक एक यात्री, जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर (एआई171) की 11ए सीट पर बैठा था, चमत्कारिक रूप से बच गया। सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास शहर के सिविल अस्पताल और बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना देश के सबसे घातक हवाई हादसों में से एक है। पुलिस उपायुक्त कानन देसाई ने संवाददाताओं से कहा, ''हमें प्राप्त संदेश के अनुसार 265 शव शहर सिविल अस्पताल पहुंचाए जा चुके हैं।'' एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मरने वालों में चार एमबीबीएस छात्र और एक चिकित्सक की पत्नी शामिल है। बहुमंजिला छात्रावास भवन में दोपहर के भोजन के समय विमान के कुछ हिस्से के भोजन कक्ष से टकराने के कारण कई छात्र प्रभावित हुए। एअर इंडिया के मुताबिक, विमान में सवार 230 यात्रियों में से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, एक कनाडाई और सात पुर्तगाली नागरिक थे। विमान में सवार अन्य 12 लोगों में दो पायलट और चालक दल के 10 सदस्य थे। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में कार्यरत डॉ. शरीक एम ने 'पीटीआई–भाषा' को बताया कि हादसे में जीवित बचे रमेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह अपने भाई के साथ लंदन जा रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एअर इंडिया के विमान का तापमान ईंधन जलने के कारण इतना अधिक था कि किसी को बचा पाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। शाह ने संवाददाताओं से कहा, ''विमान के अंदर 1.25 लाख लीटर ईंधन था। विमान गर्म हो गया था, इसलिए किसी को भी बचाने की गुंजाइश नहीं थी।'' उन्होंने कहा कि इस त्रासदी के बाद पूरा देश गहरे सदमे में है। शाह ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, ''अधिकारी मृतकों की संख्या डीएनए जांच और पीड़ितों की पहचान के बाद आधिकारिक तौर पर जारी करेंगे।'' शाह ने कहा, ''अच्छी खबर यह है कि दुर्घटना में एक व्यक्ति बच गया है और मैं उससे मिलने के बाद यहां आया हूं।'' उन्होंने कहा, ''विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के शवों से डीएनए नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला और गुजरात में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय पीड़ितों के डीएनए की जांच करेंगे।'' अहमदाबाद में हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) ने बताया कि विमान के पायलट ने अपराह्न 1.39 बजे उड़ान भरने के तुरंत बाद 'मेडे' (आपातकालीन संदेश देने के लिए) कॉल किया, जो पूर्ण आपात स्थिति का संकेत था। विमान के 'ब्लैक बॉक्स' (फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर) की भी तलाश जारी है, ताकि यह पता चल सके कि अंतिम पलों में क्या हुआ था। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद एकदम तेजी से नीचे आया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनास्थल पर काले धुएं का गुबार उठता देखा गया। यह विमान 11 साल पुराना था। लंबी यात्रा के लिए ईंधन टंकी पूरी तरह से भरी रहने का उल्लेख करते हुए विमानन विशेषज्ञों ने बताया कि विमान नीचे गिरने से पहले महज 600 से 800 फुट की ऊंचाई पर गया था। उन्होंने कहा कि उपलब्ध वीडियो फुटेज के अनुसार, दोनों इंजन का पूरी क्षमता से काम न करना या पक्षी का टकराना दुर्घटना के संभावित कारणों में से एक हो सकता है। टेलीविजन पर प्रसारित फुटेज में देखा जा सकता है कि विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद नीचे की ओर आया, जबकि उसका लैंडिंग गियर (पहिया) अब भी बाहर निकला हुआ था। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक बयान के मुताबिक, ''विमान ने अहमदाबाद से अपराह्न 1.39 बजे रनवे 23 से उड़ान भरी। इसने एटीसी (हवाई यातायात नियंत्रण) को 'मेडे' (आपातकालीन संदेश देने के लिए) कॉल किया, लेकिन उसके बाद एटीसी द्वारा की गई कॉल का विमान से कोई जवाब नहीं मिला।''

टैक्स जमा... (पेज एक का शेष) हैं। वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने किसी वित्तीय वर्ष में व्यवसाय से आय अर्जित की है, उन्हें एडवांस का भुगतान करना होगा।

एडवांस टैक्स जमा करने की जरूरी तारीखें : एडवांस टैक्स को साल भर में तय तारीखों तक में चुका देना होता है। 15 जून या उससे पहले 15%, 15 सितंबर या उससे पहले 45%, 15 दिसंबर या उससे पहले 75% और 15 मार्च या उससे पहले 100% तक एडवांस टैक्स चुका देना होता है।

एडवांस टैक्स चुकाना क्यों है अहम: आईसीआईसीआई बैंक के मुताबिक, एडवांस टैक्स एक विशेष वित्तीय वर्ष में अर्जित आय के लिए अग्रिम रूप से चुकाया जाने वाला आयकर है। आम तौर पर, टैक्स का भुगतान तब किया जाना चाहिए जब आय हासिल की गई हो। फिर भी, एडवांस टैक्स के टैक्स प्रावधानों के तहत, भुगतानकर्ता को पूरे वर्ष के लिए आय का अनुमान लगाना होता है। और इस अनुमान के आधार पर टैक्स का भुगतान निश्चित समय अंतराल पर किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि करदाता आय का अनुमान लगाए और फिर उस पर अनुमानित कर की गणना करे ताकि यह पता चल सके कि उसे अग्रिम कर का भुगतान करने की आवश्यकता है या नहीं और कितना। आयकर की धारा 234बी के मुताबिक, आपको 31 मार्च तक अपने कुल टैक्स का कम से कम 90% एडवांस टैक्स या स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रह (टीडीएस / टीसीएस) के माध्यम से चुकाना होता है। अगर आप एडवांस टैक्स का भुगतान करने में विफल होते हैं तो आपको धारा 234बी के तहत अवैतनिक राशि पर 1% की ब्याज दर से ब्याज देना होगा।

छात्र सार्वजनिक... (पेज एक का शेष) संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की रिकॉर्डिंग करने और सूचना देकर कार्रवाई करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, ''आप सभी के पास मोबाइल फोन हैं। अगर आप किसी को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते देखें तो उसका वीडियो बनाएं और उसे वायरल करें। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पोस्टर के जरिए उस व्यक्ति की पहचान की जाए और उससे वसूली की जाए।'' उन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नकल–मुक्त परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए प्रशंसा की और 2017 से राज्य की शिक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ''पहले, शिक्षा के नाम पर सामूहिक नकल एक धंधा बन गया था। लोग परीक्षा फॉर्म भरते थे और परीक्षा देने के लिए किसी और को नियुक्त करते थे। परिणाम प्रमाणपत्र के साथ घर भेजे जाते थे। यह पूरी तरह से धोखाधड़ी थी।'' उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए आदित्यनाथ ने इस तरह की अवैध गतिविधियों को बंद करने और एक पारदर्शी, निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली बनाने के लिए खुद की सरकार को श्रेय दिया। उन्होंने बताया कि पहले जिन परीक्षाओं को आयोजित करने में दो से तीन माह लगते थे वे अब सिर्फ 13 दिन में समाप्त हो जाती हैं। उन्होंने छात्रों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पुस्तक ''एग्जाम वॉरियर्स'' पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा, ''परीक्षाएं छात्रों को परेशान करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनका मूल्यांकन करने और उन्हें प्रतिस्पर्धी भावना के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने का माध्यम होना चाहिए।'' सरकारी रोजगार में राज्य की प्रगति की भी सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी भर्ती के माध्यम से आठ लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा, ''हम अब बीमारू राज्य नहीं रहे। उत्तर प्रदेश नए भारत के नए चेहरे में तब्दील हो गया है।'' मुख्यमंत्री ने मूल्य आधारित शिक्षा का आह्वान करते हुए कहा, ''शिक्षा के साथ–साथ छात्रों में बड़ों, माता–पिता, शिक्षकों, समाज और राष्ट्र के प्रति सम्मान विकसित करना चाहिए। यही सच्चा चरित्र है।''

तीर्थ यात्रियों... (पेज एक का शेष) को सही कर दिया गया। भवन के रिसेप्शन पर पंजीकरण चेक किया जाता है और फिर यात्रियों को कमरा अलॉट किया जाता है। रिसेप्शन से लेकर वेटिंग हॉल तक, सभी जगहों पर गर्मी से बचने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। **क्या–क्या सुविधाएं मिलती हैं?** : कैलाश मानसरोवर भवन में यात्रियों को कई सुविधाएं मिलती हैं। अखबार से लेकर पुस्तकों और मैगजीन तक, आप अपनी बोरियत मिटाने के लिए कुछ भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैलाश मानसरोवर भवन में जेनरेटर भी लगा हुआ है। यात्रियों को गर्मी से बचाने के लिए एसी और कूलर मौजूद हैं। यात्रियों के लिए रहने से लेकर खाने–पीने तक, सभी तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। **गौर करने वाली बात** : कैलाश मानसरोवर भवन में 50 यात्रियों का पहला जत्था तीन दिन तक ठहरने वाला है। यात्रियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन की टीम इस भवन में मौजूद रहेगी। इस टीम से हर रोज रिपोर्ट भी ली जाएगी कि किसी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि कैलाश मानसरोवर भवन से सभी श्रद्धालु एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे।

दूर करना.... (पेज एक का शेष) के साथ–साथ विटामिन सी भी मौजूद होता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में कारगर साबित हो सकता है। **पिएं विटामिन डी से भरपूर मशरूम का सूप** : मशरूम आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। विटामिन डी रिच मशरूम का सेवन करके आपको इस विटामिन की कमी से छुटकारा मिल सकता है। विटामिन डी की कमी से जूझ रहे लोगों को मशरूम का सूप पीने की सलाह दी जाती है। हालांकि, बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए सही मात्रा में और सही तरीके से मशरूम का सूप पीना बेहद जरूरी है। **डाइट प्लान में शामिल करें दूध** : दूध में विटामिन डी की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। अगर आप विटामिन डी की कमी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको दूध को अपने डेली डाइट प्लान का हिस्सा बना लेना चाहिए। हर रोज एक से दो गिलास दूध पिएं और महज कुछ ही हफ्तों के अंदर आपके शरीर में पैदा हुई विटामिन डी की कमी दूर हो जाएगी। इसके अलावा दूध आपकी मसल और बोन हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है।

Although every possible care and caution has been taken to avoid errors or omissions, this publication is being sold on the condition and understanding that information given in this publication is merely for reference and must not be taken as having the authority of or binding in any way on the writers, editors, publishers, and printers and sellers who do not owe any responsibility for any damage or loss to any person, a purchaser of this publication or not for the result of any action taken on the basis of this work. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent court and forums in Delhi/New Delhi only

Published, Printed, Edited and Owned by Krishna Aggarwal Published from New Delhi, Tel- 011-43560023 E-mail- info@focusnews.co.in, focusnews9@gmail.com
RNI NUMBER - DELBIL/2013/56173, Printed from Vibha Publication Pvt Ltd- D-160 B, Noida Phase - I, Uttar Pradesh - 201301

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने राज्य में नए सिरे से जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का फैसला किया : सिद्धरमैया

बेंगलुरु, (भाषा) कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को सर्व सम्मति से नया सामाजिक–शैक्षणिक सर्वेक्षण कराने का फैसला किया जिसे राज्य में आम बोलचाल की भाषा में 'जातिगत गणना' कहा जाता है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, " ...हमने मंत्रिमंडल में फैसला लिया है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नया सर्वेक्षण कराया जाए।" उन्होंने कहा, " सरकार कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से विचार विमर्श करेगी...हम नया सर्वेक्षण करने और रिपोर्ट देने के लिए 90 दिन का समय देने जा रहे हैं।" राज्य मंत्रिमंडल का यह निर्णय मंगलवार को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा राज्य सरकार को कर्नाटक में नए सिरे से जाति आधारित सर्वेक्षण कराने के निर्देश के बाद आया है ताकि कुछ समुदायों की चिंताओं का समाधान किया जा सके। इन समुदायों ने शिकायत की थी कि 10 साल पहले किए गए सर्वेक्षण में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब मंत्रिमंडल पहले से ही सरकार को सौंपी गई सामाजिक–शैक्षणिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार कर रहा था, जो 2015 में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित थी।

दिल्लीः भाजपा पार्षद सत्य शर्मा एमसीडी की स्थायी समिति के अध्यक्ष चुने गए

नयी दिल्ली, भाजपा के सत्य शर्मा दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष चुने गए और पार्टी के ही सुंदर सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया। एमसीडी की स्थायी समिति का गठन ढाई साल के अंतराल के बाद किया गया और चुनाव के बाद समिति के गठन से, प्रमुख विकास और प्रशासनिक पहलों में तेजी आने की उम्मीद है। यह 18 सदस्यों वाली स्थायी समिति, निगम की वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली प्रमुख पैनल है और पांच करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली किसी भी परियोजना को समिति से मंजूरी लेनी होगी।

ओडिशाः भुवनेश्वर से अबू धाबी के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू, मुख्यमंत्री माझी ने किया उद्घाटन

भुवनेश्वर, फोकस न्यूज, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बृहस्पतिवार को भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अबू धाबी के लिए सीधी उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री माझी ने बताया कि इंडिगो का एक विमान 180 यात्रियों को लेकर भुवनेश्वर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी के लिए रवाना हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 50 टन आम भी अबू धाबी भेजे गए हैं जिनका उत्पादन ओडिशा में हुआ है। यह उड़ान सेवा ओडिशा की 'बिल्डिंग मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट्स एंड नेटवर्क (बी–एमएएन)' पहल के तहत शुरू की गई। एक अधिकारी ने बताया कि विमानन कंपनी सप्ताह में हर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को अबू धाबी और भुवनेश्वर के बीच उड़ान संचालित करेगी। हवाई अड्डे पर मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान माझी ने कहा, "आज राज्य के लिए गर्व का दिन है क्योंकि ओडिशा के लोगों की अबू धाबी के लिए सीधी उड़ान सेवा की आकांक्षा पूरी हो गई है।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य की नई गंतव्य नीति के तहत संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी के लिए उड़ान सेवाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान सेवाएं ओडिशा के लिए पश्चिम एशियाई देशों से सीधे जुड़ने का अवसर पैदा करेंगी। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान–प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। बृहस्पतिवार को भुवनेश्वर से विशाखापत्तनम के लिए उड़ान सेवाएं भी पुनः शुरू कर दी गईं। मुख्यमंत्री ने कहा, "बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा, हमारी सरकार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए औद्योगीकरण और सड़क, हवाई एवं रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है।" उन्होंने बताया कि हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने भुवनेश्वर से देहरादून, गाजियाबाद, गोवा, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ और पोर्ट ब्लेयर तथा झारसुगुड़ा से हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई और रायपुर के लिए उड़ान सेवाएं शुरू की हैं।

दिल्ली के चिड़ियाघर ने पशु देखभाल और कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए वनतारा के साथ साझेदारी की

नयी दिल्ली, (भाषा) दिल्ली में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, पशु कल्याण संगठन 'वनतारा' के साथ साझेदारी में चिड़ियाघर में पशुओं की देखभाल, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और समग्र प्रबंधन में सुधार की दिशा में काम करेगा। वनतारा के सीईओ विवान करणी ने कहा, "इस पहल का उद्देश्य चिड़ियाघर के संचालन को मजबूत करना और इसे दिल्ली के लोगों के लिए अधिक सार्थक और समृद्ध अनुभव में बदलना है।" अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि सहयोग का उद्देश्य साझा संसाधनों, वैज्ञानिक विशेषज्ञता और आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से पशु देखभाल का समर्थन करना है। इसमें कहा गया है कि इसे चिड़ियाघर को पशु कल्याण में वनतारा के विशेष ज्ञान के साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है इस समझौते को लेकर कुछ वर्गों ने आलोचना की है, तो कुछ ने आरोप लगाया है कि यह निजीकरण की ओर एक कदम है। हालांकि, वनतारा के एक बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी में किसी भी स्वामित्व या प्रशासनिक नियंत्रण को हस्तांतरित नहीं किया जा रहा और यह पूरी तरह सहयोगात्मक प्रयासों पर केंद्रित है। करणी ने कहा, "यह दिल्ली सरकार द्वारा प्राणी विज्ञान और पशु कल्याण में विशेषज्ञता लाने के लिए एक दूरदर्शी कदम को दर्शाता है, ऐसे क्षेत्र जिनके लिए समर्पित, प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता होती है।" उन्होंने कहा, "यह सहयोग भारत में पशु देखभाल के लिए एक नया मानक स्थापित करने की आकांक्षा रखता है, साथ ही राजधानी को ज्ञान, करुणा और देखभाल पर आधारित विश्व स्तरीय वन्यजीव पर्यावरण तक पहुंच प्रदान करता है।" बयान में कहा गया है कि समझौते के तहत दिल्ली चिड़ियाघर के कर्मचारियों को पशु देखभाल में अपने तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होगा। इसमें कहा गया है कि चिड़ियाघर के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए उनके समग्र कल्याण का समर्थन करने के लिए बीमा कवरेज भी प्रदान किया जाएगा। संगठन ने कहा, "जानवरों को संरक्षित स्थान देने के साथ–साथ, वनतारा का लक्ष्य चिड़ियाघर के कर्मचारियों को पशु कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञ बनाना है।" वनतारा ने कहा, "दिल्ली चिड़ियाघर के साथ इस साझेदारी के माध्यम से, वनतारा एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां विशेषज्ञता, करुणा और सह–अस्तित्व भारत को पशु संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक रूप से अग्रणी बनने में मदद करता है।"

स्याही से उकेरी गई शांत क्रांति है संविधानः प्रधान न्यायाधीश ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में कहा

नयी दिल्ली, (भाषा) भारत के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने संविधान को 'स्याही से उकेरी गई एक शांत क्रांति' और एक परिवर्तनकारी शक्ति बताया, जो न केवल अधिकारों की गारंटी देती है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित लोगों का सक्रिय रूप से उत्थान करती है। भारत के सर्वोच्च न्यायिक पद पर आसीन होने वाले दूसरे दलित और पहले बौद्ध न्यायमूर्ति गवई ने मंगलवार को ऑक्सफोर्ड यूनियन में 'प्रतिनिधित्व से लेकर कार्यान्वयन तकः संविधान के वादे को मूर्त रूप देना' विषय पर अपने संबोधन में हाशिए पर पड़े समुदायों पर संविधान के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला और इस बात को स्पष्ट करने के लिए अपना स्वयं का उदाहरण दिया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "कई दशक पहले, भारत के लाखों नागरिकों को 'अछूत' कहा जाता था। उन्हें बताया जाता था कि वे अशुद्ध हैं। उन्हें बताया जाता था कि वे अपने लिए नहीं बोल सकते। लेकिन आज हम यहां हैं, जहां उन्हीं लोगों से संबंधित एक व्यक्ति देश की न्यायपालिका में सर्वोच्च पद धारक के रूप में खुलकर बोल रहा है।"

उन्होंने कहा कि संविधान नागरिकों को बताता है कि "वे अपने लिए बोल सकते हैं, समाज और सत्ता के हर क्षेत्र में उनका समान स्थान है"। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, "आज ऑक्सफोर्ड यूनियन में, मैं आपके सामने यह कहने के लिए खड़ा हूं: भारत के सबसे कमजोर नागरिकों के लिए, संविधान केवल एक कानूनी चार्टर या राजनीतिक ढांचा नहीं है। यह एक भावना है, एक जीवन रेखा है, स्याही से उकेरी गई एक शांत क्रांति है।" उन्होंने कहा, "नगरपालिका के स्कूल से लेकर भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद तक मेरी अपनी यात्रा में, यह एक मार्गदर्शक शक्ति रही है।" डॉ. बी.आर. आंबेडकर की विरासत का जिक्र करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने जातिगत भेदभाव के अपने अनुभव को न्याय की वैश्विक समझ में बदल दिया।

महायुति स्थानीय निकाय चुनाव गठबंधन से मिलकर लड़ेगी : फडणवीस

अकोला (महाराष्ट्र), (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत महायुति गठबंधन राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव मिलकर लड़ेगा, लेकिन जहां गठबंधन नहीं हो पाया, वहां दोस्ताना मुकाबला होगा। सिंचाई और बिजली उत्पादन परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद फडणवीस यहां पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुंबई के बृहन्मुंबई नगर निगम सहित विभिन्न नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव पिछले तीन वर्षों से लंबित हैं। फडणवीस ने कहा कि भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और पार्टी की चुनाव समिति स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। उन्होंने कहा, "हमने गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और जहां भी गठबंधन कारगर नहीं होगा, वहां दोस्ताना मुकाबला होगा।" अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गठबंधन के दो अन्य पार्टियां हैं। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू की भूख हड़ताल के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा कि जिला संरक्षक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले उनसे बात करेंगे। किसानों से जुड़ी मांगों को लेकर कडू चार दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पक्ष रखने के लिए विदेशों में गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक के दौरान पवार की बेटी व सांसद सुप्रिया सुले से मिले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शरद पवार के स्वास्थ्य के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा, "राजनीति में मानवता और संवेदनशीलता होती है। हम वैचारिक रूप से विरोधी हैं, दुश्मन नहीं।" मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मजबूत लोकतंत्र का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हालांकि राजनीति बदलती रहती है, लेकिन राज्य सरकार स्थिर है और महायुति के तीनों सहयोगी एक साथ रहेंगे। बाद में शहर में भाजपा द्वारा आयोजित एक रैली में बोलते हुए फडणवीस ने लोगों से स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन करने का आग्रह किया।

दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब स्तर पर, अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना

नयी दिल्ली, (भाषा) दिल्ली में बुधवार की सुबह गर्म रही और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को राजधानी में बुधवार तक का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया और लोगों को भीषण गर्मी की चेतावनी देते हुए बचाव के उपाय करने को कहा। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में कम से कम 12 जून तक बहुत गर्म मौसम रहेगा। सुबह 8:30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 39 प्रतिशत रही और अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह नौ बजे दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 227 रहा। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।

निर्धारित प्रारूप के बिना भ्रष्टाचार की शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगाः लोकपाल

नयी दिल्ली, (भाषा) भारत के भ्रष्टाचार रोधी निकाय लोकपाल ने हाल में कहा कि निर्धारित प्रारूप के बिना भ्रष्टाचार की शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा। उसने पांच जून के परिपत्र में कहा कि लोकपाल के पास अपने आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। उसने इस बात का संज्ञान लेते हुए यह बात कही कि "उसके द्वारा दिए गए फैसले पर पुनर्विचार की इच्छा रखने वाले शिकायतकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है।" भ्रष्टाचार की शिकायत भारत के लोकपाल कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से, कार्यालय के रिसेप्शन/रजिस्ट्री में स्वयं उपस्थित होकर, डाक द्वारा या ऑनलाइन की जा सकती है। परिपत्र में कहा गया कि लोकपाल में निर्धारित प्रारूप के बिना किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायतें किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएंगी। इसमें कहा गया, "भारत के लोकपाल द्वारा पारित आदेशों पर पुनर्विचार या समीक्षा की इच्छा रखने वाले शिकायतकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है।" परिपत्र में कहा गया, "कानून की यह स्थापित स्थिति है कि समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किसी वैधानिक निकाय द्वारा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि कानून में स्पष्ट रूप से ऐसी शक्ति प्रदान न की गई हो। 2013 का कानून (लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम) लोकपाल को समीक्षा की ऐसी स्पष्ट शक्ति प्रदान नहीं करता है।" शिकायतें प्राप्त होने पर लोकपाल के पास दो विकल्प होते हैं। इनमें से एक विकल्प के तहत प्रारंभिक जांच का आदेश होता है, ताकि यह पता चल सके कि मामले में कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। वहीं, दूसरे विकल्प के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) सहित किसी एजेंसी से आरोपों की जांच कराने का निर्देश देना शामिल है। लोकपाल ने जांच एजेंसियों या संबद्ध विभागों सहित अधिकारियों से गोपनीयता बनाए रखने को भी कहा। उसने कहा, "अध्यक्ष (लोकपाल) की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रेस के सदस्यों को कोई भी सूचना नहीं दी जानी चाहिए। केवल लोकपाल के प्रवक्ता के रूप में नामित अधिकृत अधिकारी ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार प्रेस और मीडिया से बातचीत कर सकता है।" लोकपाल ने कहा कि पंजीकृत शिकायत के निपटारे संबंधी अंतिम आदेश को कार्यवाही के भाग के रूप में संबंधित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद यथाशीघ्र वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए, जब तक कि दिए गए मामले में आदेश में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान न हो कि 2013 के अधिनियम के अनुसार गोपनीयता बनाए रखने के लिए इसे अपलोड नहीं किया जाएगा। इसने कहा, "उपरोक्त अपवाद श्रेणी के संबंध में आदेश, जिन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाना है, उनमें आदेश के शीर्ष दाईं ओर मोटे अक्षरों में 'अपलोड नहीं किया जाना है' शीर्षक लिखा होना चाहिए।"

महाराष्ट्र सरकार ने वार्ड परिसीमन आदेश के साथ 29 नगर निकायों के चुनाव का मंच तैयार

मुंबई, (भाषा) बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) सहित महाराष्ट्र भर के 29 नगर निगमों के लिए काफी समय से लंबित चुनाव कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने वार्ड की सीमाओं को अंतिम रूप देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, बीएमसी के लिए चुने जाने वाले पार्षदों की संख्या 227 तक सीमित कर दी गई है। मुंबई के प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद चुना जाएगा। इसके विपरीत अन्य नगर निगमों में हर वार्ड से चार पार्षद चुने जाएंगे, लेकिन यह संख्या तीन से पांच के बीच भी हो सकती है। वार्ड परिसीमन प्रक्रिया राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) की मंजूरी के साथ आगे बढ़ेगी। मुंबई के लिए बीएमसी के आयुक्त को मसौदा परिसीमन योजना तैयार करने का काम सौंपा गया है। अधिसूचना में निर्देश दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहर की आबादी को प्रति वार्ड औसत जनसंख्या निर्धारित करने के लिए पार्षदों की संख्या से विभाजित किया जाएगा। मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले, नगर निकाय को जनता की आपत्तियों और सुझावों पर विचार करना चाहिए। अंतिम योजना, एक बार संशोधित होने के बाद, अनुमोदन के लिए राज्य चुनाव आयोग को प्रस्तुत की जाएगी और बाद में नगर निकाय के आयुक्त द्वारा प्रकाशित की जाएगी। आगामी चुनाव महाराष्ट्र में 2022 से बदले राजनीतिक समीकरण के संदर्भ में होंगे। मुख्य चुनावी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), शिवसेना और राकांपा के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी गठबंधन 'महा विकास आघाडी' के बीच होने की उम्मीद है, जिसमें शिवसेना (उबाठा), राकांपा (शरदचंद्र पवार) और कांग्रेस शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल के दीघा और महेश में स्थित मंदिरों में भगवान जगन्नाथ के स्नान की रस्में शुरू

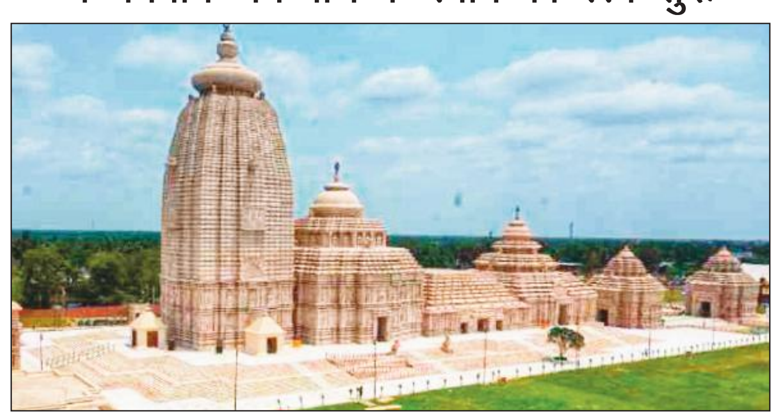

कोलकाता, पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा और हुगली जिले के महेश में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर में बुधवार को पवित्र 'स्नान यात्रा' उत्सव शुरू हुआ जो वार्षिक रथ यात्रा से पहले अनुष्ठानों की शुरुआत का प्रतीक है। इस वर्ष रथयात्रा 27 जून को शुरू होगी। दीघा के जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था। राज्य के सबसे पुराने जगन्नाथ मंदिर स्थल महेश में भी 'स्नान यात्रा' शुरू हो गई। भगवान जगन्नाथ के स्नान अनुष्ठान को देखने के लिए दोनों स्थानों पर सैकड़ों भक्त एकत्रित हुए। कोलकाता स्थित अंतरराष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कॉन) के प्रवक्ता राधारमण दास ने बताया कि दीघा में श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की मूर्तियों को 108 पवित्र तीर्थ स्थलों से एकत्रित जल और अन्य पवित्र पदार्थों से स्नान कराया जाएगा। राज्य सरकार ने दीघा स्थित जगन्नाथ मंदिर के संचालन की जिम्मेदारी इस्कॉन को दी है। दास ने कहा कि बनर्जी ने इस अवसर पर प्रसाद के रूप में अपने कोलकाता स्थित आवास के पेड़ों से आम और कटहल भेजे हैं।

जीआरएसई ने जीएसआई के लिए दो तटीय अनुसंधान पोत बनाने के लिए समझौता किया

कोलकाता, (भाषा) रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लिमिटेड ने बुधवार को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के लिए दो तटीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किये। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यहां जारी एक बयान में अधिकारी ने कहा कि इन विशेष पोत में अपतटीय भूवैज्ञानिक मानचित्रण, खनिज अन्वेषण, समुद्री पर्यावरण निगरानी और अनुसंधान करने की क्षमता होगी। अधिकारी ने बताया कि इन पोतों पर आंकड़ा प्रसंस्करण और नमूना विश्लेषण के लिए आधुनिक, सुसज्जित वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं होंगी। जीआरएसई अधिकारी ने बताया कि युद्धपोत निर्माता कंपनी को अनुसंधान पोत के निर्माण में भी महारत हासिल है। उन्होंने बताया कि पोत की लंबाई 64 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर होगी।

फीस विनियमन पर दिल्ली सरकार के अध्यादेश से निजी स्कूलों को फायदा होगाः आप

नयी दिल्ली, (भाषा) आम आदमी पार्टी (आप) ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत दिल्ली सरकार का फीस वृद्धि विनियमन संबंधी अध्यादेश निजी स्कूलों के पक्ष में है। आप ने इसे अभिभावकों को 'मूर्ख' बनाने का प्रयास बताया। सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दिल्ली मंत्रिमंडल ने निजी स्कूलों में फीस संरचना को विनियमित करने के लिए मंगलवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दी, जो मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिल्ली सरकार को ऐसे स्कूलों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने और उनसे फीस संशोधन का प्रस्ताव करने के अधिकार को भी छीन लेने की शक्ति देता है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 पर आधारित अध्यादेश को मंजूरी दी। अध्यादेश को उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। आप की दिल्ली इकाई के संयोजक सौरभ भारद्वाज ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि निजी स्कूलों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार पिछले दरवाजे से अध्यादेश लेकर आई है। उन्होंने इस शासन का "खुला और खुलेआम आत्मसमर्पण" बताते हुए कहा कि यह कानून पूरी तरह से स्कूल मालिकों के पक्ष में बनाया गया है। उन्होंने कहा, "जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, निजी स्कूलों का पहला सत्र फीस बढ़ोतरी के साथ शुरू हुआ है। अभिभावकों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, उन्हें बढ़ी हुई फीस चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।"

एक जुलाई से सिर्फ आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही 'तत्काल' टिकट बुक कर सकेंगेः रेल मंत्रालय

नयी दिल्ली, (भाषा) रेल मंत्रालय ने कहा है कि एक जुलाई 2025 से 'तत्काल' योजना के तहत वह उपयोगकर्ता ही टिकट बुक कर सकेंगे जिन्होंने आधार के जरिये सत्यापन कराया हो। मंत्रालय ने 10 जून 2025 को एक परिपत्र में सभी जोन को सूचित किया कि यह निर्णय "यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि 'तत्काल' योजना का लाभ आम उपयोगकर्ताओं को मिले।" मंत्रालय ने कहा, "01 जुलाई 2025 से 'तत्काल' योजना के तहत टिकट भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की वेबसाइट/इसके ऐप के माध्यम से केवल वह उपयोगकर्ता ही बुक कर सकेंगे, जिन्होंने आधार के जरिये सत्यापन कराया हो।" इसके बाद, 15 जुलाई 2025 से 'तत्काल' बुकिंग के लिए आधार–आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। परिपत्र में कहा गया है, " 'तत्काल' टिकट भारतीय रेलवे के कम्प्यूटरीकृत पीआरएस (यात्री आरक्षण प्रणाली) काउंटरों/अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुकिंग के लिए तभी उपलब्ध होंगे, जब सिस्टम द्वारा उत्पन्न ओटीपी का सत्यापन होगा, जो बुकिंग के समय उपयोगकर्ताओं द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इसे भी 15 जुलाई 2025 तक लागू कर दिया जाएगा।" परिपत्र में यह भी कहा गया है कि भारतीय रेलवे के अधिकृत टिकटिंग एजेंट को 'तत्काल' बुकिंग की खिड़की खुलने के पहले 30 मिनट के दौरान "ओपनिंग डे तत्काल" टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। खास तौर पर, उन्हें सुबह 10 बजे से 10.30 बजे तक वातानुकूलित श्रेणियों के लिए और सुबह 11 बजे से 11.30 बजे तक गैर–वातानुकूलित श्रेणियों के लिए 'तत्काल' टिकट बुक करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।" मंत्रालय ने रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (सीआरआईएस) और आईआरसीटीसी को निर्देश दिया है कि वे प्रणाली में आवश्यक संशोधन करें तथा इन परिवर्तनों के बारे में सभी जोनल रेलवे को सूचित करें।

महिला वनडे विश्व कपः एलओसी के गठन में देरी से बीसीसीआई की हो रही है किरकिरी

नयी दिल्ली, (भाषा) महिला वनडे विश्व कप के आयोजन में अब ज्यादा समय नहीं बचा है लेकिन मेजबान भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने अभी तक आईसीसी की इस प्रतियोगिता के सुचारू संचालन के लिए स्थानीय आयोजन समिति (एलओसी) का गठन नहीं किया है। मार्च में हुई बीसीसीआई की शीर्ष परिषद की बैठक में एलओसी गठन का मुद्दा एजेंडे में था लेकिन उस समय कोई निर्णय नहीं लिया गया था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने इस महीने के शुरू में 30 सितंबर से दो नवंबर तक पांच स्थानों पर खेले जाने वाले टूर्नामेंट के शुरुआती कार्यक्रम की घोषणा की थी। आईसीसी की 2027 तक होने वाली सभी प्रतियोगिताओं के लिए बीसीसीआई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और आईसीसी की सहमति से हाइब्रिड मॉडल के अनुसार कोलंबो पाकिस्तान की भागीदारी वाले मैचों के लिए तटस्थ स्थल होगा। बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारी तीन जून तक आईपीएल के आयोजन में व्यस्त थे और शीर्ष परिषद की जल्द ही बैठक होने की उम्मीद है, जिसके बाद एलओसी का गठन हो सकता है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई से कहा, ''एलओसी गठित करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन अगर ये चीजें पहले ही कर ली जाती तो बेहतर होता। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में आमतौर पर आयोजन से एक साल पहले एलओसी का गठन कर लिया जाता है। यहां तक कि कार्यक्रम भी पहले से ही घोषित कर दिया जाता है ताकि प्रशंसक योजना बना सकें।'' उन्होंने कहा, ''जहां तक टूर्नामेंट के आयोजन की बात है तो एलओसी मुख्य निकाय है जो भाग लेने वाली टीमों के लिए व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। कहने की जरूरत नहीं है कि इसकी भूमिका बहुत बड़ी है।'' भारत 2016 के बाद पहली बार किसी महिला आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। तब उसने पुरुषों के टूर्नामेंट के साथ महिला टी20 विश्व कप का भी आयोजन किया था। उल्लेखनीय है कि भारत में खेले गए 2023 पुरुष वनडे विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा को लेकर काफी देरी हुई थी। एकदिवसीय महिला विश्व कप का आयोजन चार स्थानों बेंगलुरु, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम और इंदौर में किया जाएगा। भारत ने इससे पहले 2013 में महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी की थी।

सैमी ने पूरन के चौंकाने वाले संन्यास पर कहा, और खिलाड़ी ऐसा कर सकते हैं

नयी दिल्ली, (भाषा) वेस्टइंडीज के मुख्य कोच डैरन सैमी का मानना है कि निकोलस पूरन का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अचानक संन्यास लेना खिलाड़ियों को अपनी राष्ट्रीय टीमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रेरित रखने की बढ़ती चुनौती को रेखांकित करता है और उन्होंने चेतावनी दी कि और भी खिलाड़ी ऐसा कर सकते हैं। पूरन ने 29 साल की उम्र में टी20 विश्व कप से ठीक आठ महीने पहले सोमवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। यह आक्रामक विकेटकीपर–बल्लेबाज ना केवल वेस्टइंडीज का टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल बल्लेबाज है बल्कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बेहद लोकप्रिय खिलाड़ी भी है। इंग्लैंड दौरे पर वेस्टइंडीज की सीमित ओवरों के प्रारूप में लगातार छठी हार के बाद 'ईएसपीएनक्रिकइन्फो' ने सैमी के हवाले से कहा, ''मेरी अंतरात्मा की आवाज कल रही थी कि ऐसा कुछ होगा।'' सैमी ने कहा कि उन्होंने इस क्रिकेटर और उनके एजेंट के साथ पहले हुई बातचीत के बाद पूरन के बिना योजना बनाना शुरू कर दिया था। सैमी ने कहा, ''आदर्श रूप से ऐसी प्रतिभा को मैं टीम में रखना पसंद करूंगा। लेकिन मैं किसी के करियर को नियंत्रित नहीं कर सकता। मैंने उसे शुभकामनाएं दी, उसने टीम को शुभकामनाएं दीं। अब निकोलस पूरन के बिना रणनीति पर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है।'' उन्होंने कहा, ''विश्व कप आने वाला है, मैं इस तथ्य का सम्मान करता हूं कि उसने हमें काफी पहले बताया ताकि हमारे पास उसके बिना योजना बनाने के लिए अधिक समय हो।'' वर्ष 2012 और 2016 में दो बार टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज को खिताब दिलाने वाले सैमी ने आधुनिक क्रिकेट में जल्दी संन्यास लेने की व्यापक प्रवृत्ति की ओर इशारा किया और चेतावनी दी कि और अधिक खिलाड़ी पूरन की राह का अनुसरण कर सकते हैं। सैमी ने कहा, ''मुझे पूरा यकीन है कि और भी खिलाड़ी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे।'' उन्होंने कहा, ''अब टी20 क्रिकेट ऐसा ही है और विशेष रूप से वेस्टइंडीज से जुड़े होने के कारण, हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के साथ हमारे खिलाड़ियों को शिखर पर खेलने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करते रहना, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होगा।''

आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में तिलक वर्मा तीसरे स्थान पर पहुंचे

दुबई, (भाषा) भारत के तिलक वर्मा बुधवार को जारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में एक स्थान के फायदे से तीसरे स्थान पर हैं जबकि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई गेंदबाजी रैंकिंग में क्रमशः तीसरे और सातवें स्थान पर बने हुए हैं। तिलक के 804 रेटिंग अंक हैं और वह दूसरे स्थान पर मौजूद हमवतन अभिषेक शर्मा से पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार हैं। भारत के सूर्यकुमार यादव एक स्थान के नुकसान से छठे स्थान के साथ शीर्ष 10 में शामिल हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में चक्रवर्ती (706) और बिश्नोई (674) के अलावा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (653) भी शीर्ष 10 में शामिल भारतीय गेंदबाज हैं। हार्दिक पंड्या 252 रेटिंग अंक के साथ ऑलराउंडर की सूची में शीर्ष पर हैं। इंग्लैंड के आदिल राशिद गेंदबाजी रैंकिंग में एक स्थान के फायदे से दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज पर इंग्लैंड की 3–0 की जीत के दौरान चार विकेट चटकाए। राशिद के 710 अंक हैं और वह शीर्ष पर चल रहे न्यूजीलैंड के जैकब डफी (723) से सिर्फ 13 अंक पीछे हैं। राशिद के टीम के साथी ब्राइडन कार्स दो मैच में दो विकेट की बदौलत 16 स्थान की छलांग लगाकर 52वें स्थान पर पहुंच गए। अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय में 46 गेंद में 84 रन की तूफानी पारी खेलने वाले इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट 48 स्थान के फायदे से 16वें पायदान पर हैं। श्रृंखला में नाबाद 35 और 34 रन की पारी खेलने वाले हैरी ब्रूक छह स्थान के फायदे से संयुक्त 38वें स्थान पर हैं। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप दो बार 40 रन से अधिक की पारियां खेलने के बाद 14 स्थान की छलांग लगाकर 15वें स्थान पर हैं। अंतिम मैच में 45 गेंद में नाबाद 79 रन की पारी खेलने वाले रोवमैन पावेल शीर्ष 20 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। ऑलराउंडर जेसन होल्डर भी श्रृंखला में 70 रन और एक विकेट चटकाने के बाद ऑलराउंडर की सूची में 16 स्थान के फायदे से 26वें स्थान पर हैं।

मनु भाकर, चैन सिंह फाइनल में पहुंचे, लेकिन पदक से चूके

म्यूनिख, (भाषा) पेरिस ओलंपिक की पदक विजेता मनु भाकर और सीनियर निशानेबाज चैन सिंह ने यहां चल रहे आईएसएसएफ विश्व कप में अपनी–अपनी स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बनाई लेकिन पोडियम स्थान हासिल नहीं कर सके जिससे भारत बुधवार को एक भी पदक नहीं जीत पाया। ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर 25 मीटर पिस्टल में आठ निशानेबाजों के फाइनल में छठे स्थान पर रहीं। इससे पहले क्वालीफाइंग दौर में उन्होंने 588 के कुल स्कोर के साथ पांचवां स्थान हासिल किया था। चैन सिंह ने क्वालिफिकेशन राउंड में अच्छे स्कोर के आधार पर पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3–पोजिशन स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई, लेकिन आठ निशानेबाजों के पदक राउंड में सातवें स्थान पर रहे। मंगलवार को प्रतियोगिता के पहले दिन भारत ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। उसे यह पदक एलावेनिल वलारिवान ने दिलाया था। मनु भाकर ने प्रिसिशन में 290 और रैपिड फायर राउंड में शानदार प्रदर्शन करके 298 अंक हासिल किए थे लेकिन फाइनल में उनका प्रदर्शन अपेक्षानुरूप नहीं रहा। चीन की सुन युजी ने 38 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि कोरिया की ओह येजिन और यांग जिन ने क्रमशः 36 और 32 अंकों के साथ रजत और कांस्य पदक हासिल किया। भाकर तीसरे एलिमिनेशन राउंड से आगे नहीं बढ़ सकीं और उन्होंने 20 अंकों के साथ अपने अभियान का समापन किया। एशियाई खेलों में कई बार पदक जीतने वाली ईशा सिंह 585 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रहीं और आठ निशानेबाजों के फाइनल में जगह नहीं बना सकीं। एक अन्य भारतीय सिमरनप्रीत कौर बरार 577 अंक के साथ 32वें स्थान पर रहीं। एशियाई खेलों के पदक विजेता और हाल ही में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आईएसएसएफ विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाले चैन सिंह ने 592 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। लेकिन फाइनल में वह शुरू में ही लड़खड़ा गए और बाहर होने वाले दूसरे प्रतियोगी बने। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले अन्य भारतीय, पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और अंकुश जाधव 587 और 580 अंक लेकर क्रमशः 38वें और 67वें स्थान पर रहे। नॉर्वे के जॉन–हरमन हेग ने 464.1 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक, व्यक्तिगत तटस्थ खिलाड़ी इलिया मार्साव ने 462 अंकों के साथ रजत पदक और चेक गणराज्य के जिरी प्रिवरात्स्की (452) ने कांस्य पदक जीता। गुरुवार को पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा शुरू होगी जिसमें भारत के ओलंपियन अर्जुन बाबूता और संदीप सिंह को पेरिस ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता शेंग लिहाओ की कड़ी चुनौती का सामना करना होगा।

इंग्लैंड दौरे को यादगार बनाने के लिए हर गेंद पर चुनौती पेश करें: गंभीर

बेकेनहैम (इंग्लैंड), (भाषा) भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने अपनी टीम से अपने 'कम्फर्ट जोन' (सहज स्थिति) से बाहर निकलने और संन्यास ले चुके स्टार खिलाड़ियों विराट कोहली, रोहित शर्मा तथा आर अश्विन की अनुपस्थिति में इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला को 'यादगार' बनाने को कहा। भारत 2007 के बाद इंग्लैंड में अपनी पहली श्रृंखला जीतने के इरादे से उतरेगा। दोनों टीम के बीच पांच मैच की टेस्ट श्रृंखला 20 जून को लीड्स में पहले टेस्ट के साथ शुरू होगी। गंभीर ने 'बीसीसीआई.टीवी' से अश्विन, रोहित और कोहली के हाल ही में संन्यास का जिक्र करते हुए कहा, ''इस दौरे को देखने के दो तरीके हैं। एक तो यह कि हम अपने तीन सबसे अनुभवी खिलाड़ियों के बिना हैं या हमें देश के लिए कुछ खास करने का यह अभूतपूर्व अवसर मिला है।'' भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा कि वह शुभमन गिल की अगुआई वाली मौजूदा टीम में कुछ खास हासिल करने के लिए 'जुनून और प्रतिबद्धता' महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ''जब मैं इस समूह को देखता हूं तो मुझे कुछ खास करने की भूख, जुनून और प्रतिबद्धता दिखती है। अगर हम त्याग करते हैं, अगर हम अपनी सहज स्थिति से बाहर आते हैं, अगर हम हर दिन नहीं बल्कि हर सत्र, हर घंटे और हर गेंद पर चुनौती पेश करना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि हम इसे एक यादगार दौरा बना सकते हैं।'' गंभीर ने इंग्लैंड दौरे पर पूरी टीम का स्वागत किया और बी साई सुदर्शन से शुरूआत करते हुए कुछ सदस्यों की विशेष सराहना की। भारतीय कोच ने कहा, ''पहली बार टेस्ट टीम में बुलाया जाना हमेशा खास होता है इसलिए मैं साई का स्वागत करना चाहता हूं जिनके लिए बल्ले से तीन महीने शानदार रहे हैं और सुनिश्चित कीजिए कि आपका लाल गेंद का करियर बेहद सफल हो।'' गंभीर ने उम्मीद जताई कि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह टेस्ट क्रिकेट में भी अपना प्रभाव छोड़ेंगे। उन्होंने कहा, ''मैं अर्शदीप सिंह का स्वागत करना चाहता हूं। आपने सफेद गेंद से शानदार प्रदर्शन किया है और मुझे यकीन है कि आप लाल गेंद से भी अपना जलवा बिखेरेंगे।'' इस 43 वर्षीय कोच ने इसके बाद गिल और उपकप्तान ऋषभ पंत की पीठ भी थपथपाई। गंभीर ने कहा, ''मैं शुभमन को भी बधाई देना चाहता हूं जो पहली बार कप्तानी कर रहे हैं। अपने देश की टेस्ट टीम का नेतृत्व करने से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। बधाई हो। ऋषभ पंत को भी जो अब नेतृत्व समूह का हिस्सा हैं।'' गंभीर ने करुण नायर की भी तारीफ की जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में वापसी की। भारतीय कोच ने कहा, ''वापसी कभी आसान नहीं होती, जिसने सात साल बाद वापसी की हो, उसका पिछला साल शानदार रहा।'' उन्होंने कहा, ''आपने जितने रन बनाए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कभी हार ना मानने का जज्बा है जिसने आपको टीम में वापस ला दिया है और यह इस समूह में सभी के लिए प्रेरणादायक है। करुण नायर का स्वागत है।'' नायर ने कहा कि वह भारत के लिए खेलने का दूसरा मौका मिलने पर 'आभारी' हैं। उन्होंने कहा, ''इस अवसर फिर से मिलने के लिए आभारी हूं। मैं इस अवसर का पूरा फायदा उठाने के लिए उत्सुक हूं। मुझे यकीन है कि एक बार जब मैं मैदान पर उतरूंगा तो मेरे अंदर बहुत सारी भावनाएं होंगी लेकिन अभी मैं उन्हें व्यक्त नहीं कर सकता।'' कप्तान गिल ने अपने साथियों से खुद को थोड़ा दबाव में रखने का आग्रह किया जिससे कि श्रृंखला शुरू होने पर वे परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हों। गिल ने कहा, ''आइए प्रत्येक नेट सत्र को सार्थक बनाएं। आइए खुद को थोड़ा दबाव में रखें।

भूटिया और अन्य ने भारतीय फुटबॉल में आमूलचूल बदलाव की मांग की

कोलकाता, (भाषा) फुटबॉल के मैदान पर भारत के गिरते प्रदर्शन से नाराज करिश्माई पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया ने राष्ट्रीय महासंघ पर खेल को नष्ट करने का आरोप लगाया है जबकि कुछ अन्य दिग्गजों ने मौजूदा प्रणाली को 'सड़ी हुई' और 'अहंकार' से भरी बताया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) और उसके अध्यक्ष कल्याण चौबे पर भूटिया का तीखा हमला एएफसी एशियाई कप क्वालीफायर के तीसरे दौर में निचली रैंकिंग वाली हांगकांग के खिलाफ 0–1 की चौंकाने वाली हार के एक दिन बाद आया है। भूटिया ने पीटीआई से कहा, ''यह देखना बहुत दुखद है कि हम अब एशिया कप के लिए भी क्वालीफाई करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिसके लिए हम नियमित रूप से क्वालीफाई करते रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया और जोर्डन जैसे देश विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं और हम अब भी एशिया कप के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।'' मंगलवार को मिली हार से भारत की 2027 एशियाई कप के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीदों को झटका लगा है जबकि टीम इससे पहले लगातार दो एशियाई कप में खेली थी। पूर्व भारतीय कप्तान ने चौबे के इस्तीफे और भारतीय फुटबॉल में संरचनात्मक बदलाव की मांग की। उन्होंने मैदान पर लचर प्रदर्शन और मैदान के बाहर की अराजकता को गहरी सड़न के लक्षण बताया। मौजूदा भारतीय मुख्य कोच मनोलो मारक्वेज इंडियन सुपर लीग की टीम एफसी गोवा के भी कोच हैं। उन्होंने पिछले साल जुलाई में क्रोएशियाई दिग्गज इगोर स्टिमक की जगह पदभार संभाला था। गुवाहाटी में विश्व कप क्वालीफायर में अफगानिस्तान से हार सहित कई निराशाजनक परिणामों के बाद स्टिमक को बर्खास्त कर दिया गया था। मंगलवार हुए अहम मैच से पहले भारत ने कोलकाता में करीब तीन सप्ताह तक अभ्यास किया था लेकिन उसे विश्व रैंकिंग में अपने से 26 पायदान नीचे की टीम (भारतः 127, हांगकांगः 153) से हार का सामना करना पड़ा। इस हार से फीफा रैंकिंग में देश के 133वें स्थान पर खिसकने की संभावना है। भूटिया को सितंबर 2022 में एआईएफएफ के अध्यक्ष पद के चुनाव में चौबे ने हराया था। उन्होंने मौजूदा नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और मनोलो की नियुक्ति सहित अहम निर्णयों में प्रमुख फुटबॉल समितियों को दरकिनार करने का आरोप लगाया। भूटिया ने कहा, ''कल्याण चौबे ने भारतीय फुटबॉल को बर्बाद कर दिया है। चौबे को इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। उन्होंने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ढाई साल में तीन महासचिव – पूरी संरचना, व्यवस्था को बदलना होगा।'' भूटिया ने इंटर काशी और चर्चिल ब्रदर्स के बीच चैंपियनशिप के लिए चल रहे कानूनी झगड़े का जिक्र करते हुए कहा, ''एक के बाद एक विवाद, भ्रष्टाचार के आरोप... महीनों बाद भी हमें नहीं पता कि आईलीग विजेता कौन है।'' उन्होंने चौबे पर तकनीकी समिति को दरकिनार कर मनोलो को नियुक्त करने का आरोप लगाया और स्पेन के इस कोच को एक साथ एफसी गोवा और राष्ट्रीय टीम का कोच बनाने के फैसले की आलोचना की। भूटिया ने करिश्माई स्ट्राइकर सुनील छेत्री की अंतरराष्ट्रीय संन्यास से वापसी कराने के फैसले की भी आलोचना की और कहा कि यह योजना बनाने से ज्यादा हताशा से प्रेरित एक खराब फैसला था। भूटिया ने एआईएफएफ के उस फैसले की भी आलोचना की जिसमें उसने क्वालिफिकेशन से जुड़े इनाम के बजाय हांगकांग मैच के लिए 50,000 अमेरिकी डॉलर का मैच बोनस देने का फैसला किया था। उन्होंने कहा, ''आप एक मैच के लिए 42 लाख रुपये दे रहे हैं। इसे क्वालिफिकेशन से क्यों नहीं जोड़ा गया? यह दिखाता है कि प्रबंधन कितना अनजान है।'' भारत के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी गौतम सरकार ने भूटिया का समर्थन करते हुए टीम के खराब प्रदर्शन और महासंघ की विफलताओं पर निराशा व्यक्त की। सरकार ने कहा, ''हमने एक इंच भी प्रगति नहीं की है। अगर आपके पास सुनील छेत्री का विकल्प नहीं है तो क्या इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है?'' उन्होंने कहा, ''बेशक, महासंघ पूरी तरह से जिम्मेदार है। वे पूरी तरह से विफल रहे हैं।'' दिग्गज डिफेंडर और कोच सुब्रत भट्टाचार्य ने विदेशी कोचों के प्रति जुनून की आलोचना की और भारतीय प्रतिभाओं पर अधिक भरोसा करने की बात कही। भट्टाचार्य ने कहा, ''इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि विदेशी कोच आपको सफलता दिलाएंगे। पीके बनर्जी और अमल दत्ता जैसे घरेलू कोचों ने गौरव दिलाया।'' उन्होंने कहा, ''आईएसएल ने विदेशी खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों के विकास में मदद नहीं करेंगे। केवल भारतीय कोच ही हमारे खिलाड़ियों को जानते हैं और उन्हें विकसित कर सकते हैं।'' छेत्री के ससुर भट्टाचार्य ने उनकी वापसी पर कहा, ''यह उनका निजी फैसला है लेकिन अगर यह किसी के निजी हित को पूरा करने के लिए किया गया है तो यह गलत है।'' भारतीय फुटबॉल के दो प्रमुख क्लब हितधारकों बेंगलुरु एफसी के मालिक पार्थ जिंदल और एफसी गोवा के सीईओ रवि पुष्कर ने भी एआईएफएफ और व्यापक फुटबॉल पारिस्थितिकी तंत्र पर तीखा हमला किया और अपमानजनक हार के मद्देनजर गहन आत्मनिरीक्षण और संरचनात्मक सुधार का आह्वान किया। रवि ने व्यवस्था को इस तरह से सड़ा हुआ बताया कि कोई इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, ''सब कुछ प्रभाव, पक्षपात और अहंकार पर चलता है। हमारे पास उस पारिस्थितिकी तंत्र को प्रबंधित करने की परिपक्वता नहीं है जिसे हम बनाने का दावा करते हैं। हम असहज सच्चाइयों का सामना करने से पहले ही एक–दूसरे पर हमला कर देते हैं।'' बेंगलुरु एफसी के मालिक पार्थ जिंदल ने भी सोशल मीडिया पर एआईएफएफ पर निशाना साधा और तत्काल सुधार की मांग की। उन्होंने कहा, ''यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है– किसी भी परिस्थिति में यह पर्याप्त नहीं है – एआईएफएफ को गहन आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। यह वह नहीं है जिसे देखने के लिए हम सभी भारतीय फुटबॉल प्रेमियों और समर्थकों ने अपनी मेहनत की कमाई और प्रयास खर्च किए हैं। समय आ गया है कि एक प्रबंधक और एक ऐसी प्रणाली लागू हो जो काम करे।''

एनएफएल से बराबरी करने के लिए आईपीएल के लिए भी 12 से 16 सप्ताह की विंडो होनी चाहियेः बर्मन

नयी दिल्ली, (भाषा) पंजाब किंग्स के सह–मालिक मोहित बर्मन का मानना है कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को एनएफएल (नेशनल फुटबॉल लीग, अमेरिका), एनबीए (नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, अमेरिका) और यूरोपीय देशों की बड़ी फुटबॉल लीग सहित दुनिया की शीर्ष खेल लीगों के ब्रांड मूल्य से मेल खाने के लिए 12 से 16 सप्ताह की विंडो (टूर्नामेंट के आयोजन का समय) की आवश्यकता है। आईपीएल के प्रति मैच का मूल्य लगभग 16.8 मिलियन डॉलर है जो दुनिया भर के विभिन्न खेलों की शीर्ष लीग में सिर्फ एनएफएल (36.8 मिलियन डालर) से पीछे है, लेकिन जब समग्र ब्रांड मूल्य की बात आती है तो यह एनएफएल और यूरोप की शीर्ष फुटबॉल लीग से काफी पीछे है। प्रमुख निवेश बैंक हौलिहान लॉकी के अनुसार आईपीएल का ब्रांड मूल्य लगभग 16 बिलियन डॉलर है, जबकि एक एनएफएल फ्रेंचाइजी डलास काउबॉय की कीमत ही नौ बिलियन डॉलर है, इसके बाद न्यूयॉर्क यांकीस की कीमत 7.1 बिलियन डॉलर है। एनबीए फ्रेंचाइजी न्यूयॉर्क निक्स का मूल्य सात बिलियन डॉलर है, जबकि शीर्ष फुटबॉल क्लब रियाल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने का मूल्य लगभग छह बिलियन डॉलर है। आईपीएल की मौजूदा आठ सप्ताह के तुलना में प्रीमियर लीग (अगस्त से मई), एनबीए (सात महीने) और एनएफएल (4.5 महीने) की बहुत लंबी विंडो भी उनके मूल्य को बढ़ाती है। बर्मन ने आईपीएल के आगे की राह और पंजाब किंग्स के उल्लेखनीय बदलाव के बारे में पीटीआई से बात की। पंजाब की टीम 11 साल के लंबे अंतराल के बाद आईपीएल फाइनल में पहुंची। 'डाबर इंडिया' के प्रमुख बर्मन ने कहा, '' हम प्रति मैच मूल्य के मामले में पहले से ही एनएफएल के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं। लेकिन जब बात ब्रांड मूल्य की आती है तो आंकड़े कुछ और होता है। यह एक अलग पहलू है। मुझे लगता है कि हमें वहां पहुंचने के लिए अगर इस लीग का आयोजन 12 से 16 सप्ताह तक कराने की जरूरत है।'' उन्होंने कहा, '' इससे हमें बेहतर माहौल बनाने, प्रतिद्वंद्विता बनाने और सभी (प्रशंसक, प्रायोजक, प्रसारक) के लिए अधिक मूल्य बनाने का मौका मिलता है। लेकिन यह सिर्फ आयोजन का समय बढ़ाने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि हम उस समय में क्या करते हैं । हम किस तरह की सामग्री पेश करते हैं, हम साल भर प्रशंसकों को कैसे जोड़ते हैं, हम सत्र से परे लीग का निर्माण कैसे करते हैं। '' पंजाब किंग्स ने इस सत्र में अपना दूसरा फाइनल खेला और 2014 के बाद से लीग तालिका में शीर्ष पर रहने के बाद यह टीम का पहला फाइनल था। पिछले कुछ साल से खराब प्रदर्शन करने वाली इस टीम की सफलता का श्रेय कोच रिकी पोंटिंग और कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर को दिया जा रहा है। बर्मन ने कहा, '' रिकी पोंटिंग को टीम का कोच बनाना हमारे बदलाव का पहला कदम था। उनके आने से ऊर्जा और मानसिकता दोनों ही बदल गई।'' इस 56 साल के कारोबारी ने कहा, '' इसके बाद हमने तैयारी के साथ बड़ी नीलामी में उतरे। हम वहां संतुलित और अपनी रणनीति के मुताबिक विकल्प हासिल करने में सफल रहे। श्रेयस को कप्तान के रूप में समर्थन देना एक और बड़ा पल था। वह टीम में संयम, दूरदर्शिता और एकता की भावना लाने में सफल रहे।''

काउंटी चैंपियनशिप में हैंपशर के लिए खेलेंगे तिलक वर्मा

हैदराबाद, (भाषा) हैदराबाद क्रिकेट संघ (एचसीए) ने बुधवार को कहा कि बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा काउंटी चैंपियनशिप में हैंपशर का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। हैदराबाद के रहने वाले और इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व करने वाले 22 वर्षीय तिलक ने भारत के लिए 25 टी20 और चार एकदिवसीय मैच में क्रमशः 749 और 68 रन बनाए हैं। एचसीए ने एक विज्ञप्ति में कहा, ''हैदराबाद क्रिकेट संघ को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हैदराबाद के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एन ठाकुर तिलक वर्मा से ब्रिटेन काउंटी चैंपियनशिप में खेलने के लिए हैंपशर काउंटी टीम ने संपर्क किया है।'' विज्ञप्ति के अनुसार, ''हैदराबाद क्रिकेट संघ उन्हें हैंपशर काउंटी के साथ शानदार जुड़ाव के लिए शुभकामनाएं देता है।'' तिलक ने 18 प्रथम श्रेणी मैच में 50.16 की औसत से 121 के उच्चतम स्कोर के साथ 1,204 रन बनाए हैं।

योगी आदित्यनाथ ने 11 साल के परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर मोदी की सराहना की

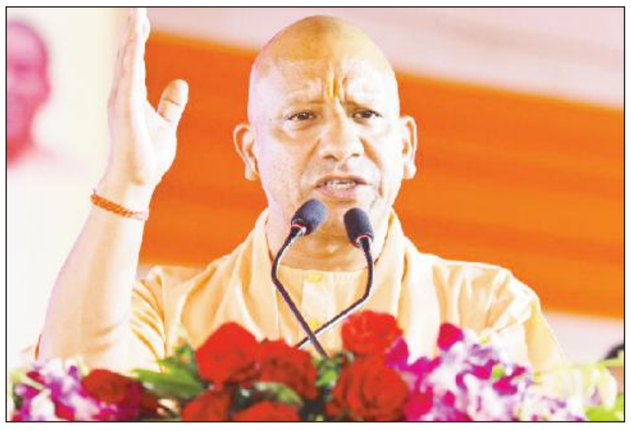

लखनऊ, (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दशक को ''बुनियादी ढांचे में क्रांति'' का वह दशक करार दिया, जिसने देश को नया आकार दिया और एक विकसित भारत की नींव रखी। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में विगत 11 वर्षों में भारत के बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व विकास हमें गर्व और आत्मविश्वास से भर देता है।'' उन्होंने कहा, ''विगत एक दशक में हमने विश्व स्तरीय सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे और अत्याधुनिक स्मार्ट शहर बनाए हैं। भारतमाला, वंदे भारत ट्रेन, अटल सुरंग और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी परियोजनाएं सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की एक बुलंद झांकी हैं।'' उन्होंने कहा,'' नागरिक सुविधाओं में क्रांतिकारी वृद्धि के वाहक इन सृजनकारी वर्षों में न केवल देश की तस्वीर बदली है, बल्कि 'विकसित भारत' की आधारशिला भी मजबूत हुई है। 'समृद्ध भारत–सशक्त भारत' के निर्माण में अनेक स्वर्णिम अध्यायों को जोड़ने वाले 11 क्रांतिकारी वर्षों के शिल्पकार प्रधानमंत्री का हार्दिक अभिनंदन!''

आंध्र : नायडू ने पहले कार्यकाल की वर्षगांठ पर और अधिक कल्याणकारी एवं विकास पहल का वादा किया

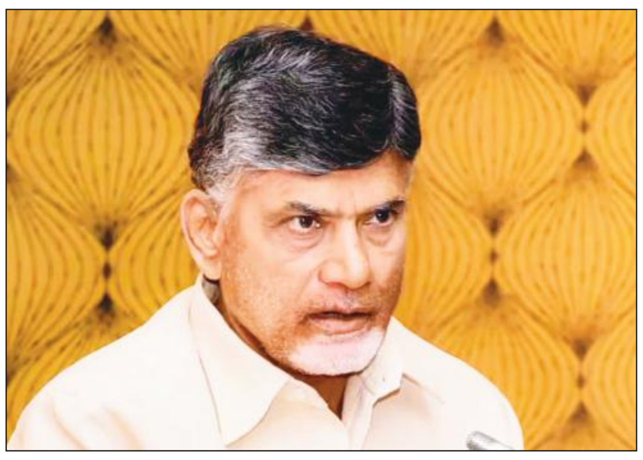

अमरावती, (भाषा) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार के शासन का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बृहस्पतिवार को कहा कि लोगों के निरंतर समर्थन से राज्य सरकार कई और कल्याणकारी एवं विकास पहल शुरू करेगी। नायडू ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''इस अवसर पर, मैं वादा करना चाहता हूं कि हम लोगों के आशीर्वाद से कई और कल्याणकारी एवं विकास कार्यक्रम लागू करेंगे।'' उन्होंने कहा कि राजग सरकार को लोगों का जनादेश इसीलिए मिला था ताकि वह आंध्र प्रदेश को फिर से कल्याण, विकास और अच्छे शासन के साथ आगे बढ़ा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की लगातार कोशिश कर रही है। वित्तीय चुनौतियों के बावजूद एक साल में पेंशन, अन्ना कैंटीन जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए निवेश आकर्षित करने के साथ–साथ सरकार ने किसानों से 55 टन धान खरीदा है और उनके कल्याण के लिए कई फैसले भी लिए हैं। इसके अलावा, तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार जून महीने में 'अन्नदाता सुखी भव' योजना लागू करेगी, जिसके तहत किसानों को सालाना 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नायडू ने कहा कि सरकार ने हर एक खेत तक पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने सरकार के शासन का एक साल सफलतापूर्वक पूरा होने में सहयोग देने वाले हर व्यक्ति का धन्यवाद किया।

कोविड–19: कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिका अस्पतालों में पृथकवास के लिए बिस्तरों की व्यवस्था

ठाणे, महाराष्ट्र में कोविड–19 के मामलों में हाल में हुई वृद्धि के बीच ठाणे जिले में कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिका ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए महानगरपालिका द्वारा संचालित अस्पतालों में पृथकवास के लिए 15 बिस्तर तैयार रखे हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, महाराष्ट्र में बुधवार को कोविड–19 के 107 नए मामले सामने आए, जिससे इस वर्ष अब तक राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,700 हो गई। बुधवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि पिछले कुछ दिनों में कोविड–19 के दो और मरीजों की मौत भी दर्ज की गई, जिससे जनवरी से अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 21 हो गई। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, नए मामलों में से मुंबई में 34, ठाणे जिले में एक, ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र में सात, नवी मुंबई में पांच, कल्याण महानगरपालिका क्षेत्र में एक, पुणे जिले में चार, पुणे महानगरपालिका क्षेत्र में 44, पिंपरी चिंचवड़ में सात, सांगली में एक, सांगली महानगरपालिका में दो और नागपुर महानगरपालिका क्षेत्र में एक मामला दर्ज किया गया है। कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिका के आयुक्त अभिनव गोयल ने संवाददाताओं को बताया कि कोविड–19 की तैयारियों के तहत पृथकवास के लिए बाई रुक्मिणीबाई अस्पताल में 10 और शास्त्री नगर अस्पताल में पांच बिस्तर तैयार रखे गए हैं। उन्होंने कहा, ''लोगों को लक्षणों के बारे में तुरंत सूचना देनी चाहिए और घबराना नहीं चाहिए।'' मानसून से निपटने की तैयारियों को लेकर गोयल ने बताया कि नगर मुख्यालय में सातों दिन, 24 घंटे आपातकालीन नियंत्रण कक्ष सक्रिय है जिसमें उपायुक्त स्तर के अधिकारी रात्रिकालीन ड्यूटी पर तैनात हैं।

उप्र वन बल को एआई तकनीक एवं सेंसर युक्त कैमरों से लैस करेगी सरकार

लखनऊ, (भाषा) प्रदेश सरकार वन संरक्षण और वन्यजीव अपराधों की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश वन बल को कृत्रिम मेधा (एआई) तकनीक एवं सेंसर युक्त कैमरों से लैस कर आधुनिक करने की योजना पर काम कर रही है। बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक, उत्तर प्रदेश लंबे समय से अवैध कटाई, वन्यजीव तस्करी और मानव–वन्यजीव संघर्ष जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है और इन समस्याओं से निपटने के लिए प्रदेश के वन एवं वन्यजीव विभाग ने आधुनिक तकनीकों और उपकरणों के प्रयोग से वन बल को अधिक सतर्क और सुदृढ़ बनाने की कार्य योजना तैयार की है। बयान में बताया गया है कि प्रदेश में वन संरक्षण, प्रबंधन, और वन्यजीव अपराधों की रोकथाम के लिए उप्र वन बल को सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) और एआई तकनीक एवं सेंसर युक्त कैमरे, ट्रैकिंग डिवाइस के प्रयोग से आधुनिकृत किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि यह पहल न केवल प्रदेश में वन संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देगी, बल्कि डेटा–आधारित निर्णय और त्वरित कार्रवाई से वन अपराधों में कमी को भी सुनिश्चित करेगी। वक्तव्य में कहा गया है कि इसके तहत वन एवं वन्य जीव विभाग ने एकीकृत वन प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की योजना तैयार की है जिसके तहत ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, और सेंसर–आधारित निगरानी जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों का उपयोग कर निगरानी और वन संरक्षण की प्रक्रिया को अधिक उपयुक्त बनाया जा सकता है। बयान के मुताबिक, वन एवं वन्य जीव विभाग प्रदेश के जंगलों, बाघ अभयारण्यों, सफारी और राष्ट्रीय उद्यानों में रीयल–टाइम निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत कमांड सेंटर की स्थापना करने जा रहा है।

लालू से रिश्ता सिर्फ राजनीति तक समिति नहीं, सामाजिक न्याय के संघर्ष पर आधारित है : राहुल

नयी दिल्ली (भाषा) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दीं और कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उनका रिश्ता सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि समान मूल्यों और सामाजिक न्याय के संघर्ष पर आधारित है। लालू प्रसाद बुधवार को 77 साल के हो गए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा – यह एक गहरा मानवीय जुड़ाव है, जो समान मूल्यों और सामाजिक न्याय के संघर्ष पर आधारित है।'' उन्होंने कहा, ''आपका जीवन संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन आपने हमेशा मजबूती और हौसले के साथ उन लोगों की आवाज़ उठाई है, जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है।'' राहुल गांधी ने कहा, ''आज आपके जन्मदिन पर मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं।'' कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर पोस्ट किया, ''राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री, लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। ''

राव के कार्यकाल में सुधार 'गुपचुप' रूप से किये गए: मोंटेक सिंह अहलूवालिया

नयी दिल्ली, (भाषा) योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में 1991 में किए गए आर्थिक सुधारों की विशेषता स्पष्टतावादी दृष्टिकोण अपनाने की तुलना में 'गुपचुप सुधार' करना अधिक थी। उन्होंने कहा कि न तो राव और न ही तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह 'बड़े धमाकेदार' बदलाव करने के समर्थक थे। लेखक डेविड सी एंगरमैन की पुस्तक 'एपोस्टल्स ऑफ डेवलपमेंट: सिक्स इकोनॉमिस्ट्स एंड द वर्ल्ड दे मेड' के विमोचन के अवसर पर मंगलवार को अहलूवालिया ने राव और मनमोहन दोनों को 'क्रमिक' दृष्टिकोण अपनाने वालों की श्रेणी में रखा, जैसा रुख उन्होंने खुद अपनाया था। हालांकि, उन्होंने दो प्रकार के क्रमिक बदलाव के बीच अंतर किया जिसे उन्होंने 'क्रमिकता' और 'गुपचुप सुधार' का नाम दिया। अहलूवालिया ने कहा, ''मुझे नहीं पता कि मैंने 'गुपचुप सुधार' वाक्यांश गढ़ा है या नहीं, लेकिन मैंने निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल किया है और शायद सबसे पहले। मैंने इसका इस्तेमाल सुधारों को लाने के लिए राव द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए किया। मनमोहन सिंह इसके निर्माता थे, उन्हें वास्तव में पता था कि क्या करना है।'' उन्होंने कहा, ''लेकिन, जैसा कि वे खुद अक्सर कहते थे, वे प्रधानमंत्री के समर्थन के बिना ऐसा नहीं कर सकते थे। न तो राव और न ही मनमोहन सिंह बड़े और धमाकेदार सुधारों में बहुत विश्वास करते थे। वे दोनों इस अर्थ में, क्रमिकतावादी थे।'' अर्थशास्त्री अहलूवालिया (81) 1991 के सुधारों को लागू करने वाली टीम के एक प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने अपनी बात समझाने के लिए शिपिंग उद्योग से जुड़े सादृश्य का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि उनके एक मित्र, जो शिपिंग उद्योग से जुड़े थे, ने एक बार कहा था: एक छोटी नाव के घूमने का घेरा बड़ी नाव की तुलना में बहुत छोटा होता है। उन्होंने कहा कि यह स्वीकार करना होगा कि यदि आप एक बहुत बड़े जहाज को चला रहे हैं, तो उसे मुड़ने में समय लगेगा। उन्होंने कहा, ''भारत में 'गुपचुप सुधार' का वास्तव में मतलब यह था कि हम दिशा बदलने जा रहे हैं, लेकिन हम खुले तौर पर ऐसा नहीं कहने जा रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि इसका मतलब अक्सर यह होता है कि सुधार की घोषणाएं स्पष्ट समयसीमा या प्रतिबद्धताओं के बिना की जाती हैं, जो कि अधिक पूर्वानुमानित और योजनाबद्ध मार्ग के विपरीत हैं।

निगरानी का दायरा बढ़ाने की जरूरत: एयर मार्शल दीक्षित

नयी दिल्ली, (भाषा) सीमा तक पहुंचने से पहले ही संभावित खतरों का पता लगाने के लिए 'हमारे निगरानी दायरे का विस्तार' करने की आवश्यकता है। एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने बुधवार को यहां यह बात कही। सुब्रतो पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में चीफ आफ इंटीग्रेटिड डिफेंस स्टाफ (सीआईएससी), एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखाया है कि स्वदेशी नवाचार को अगर उचित तरीके से उपयोग में लाया जाए तो ये अंतरराष्ट्रीय मानदंडों की बराबरी कर सकता है और उनसे आगे भी निकल सकता है। उन्होंने कहा कि निगरानी और ईओ (इलेक्ट्रो–ऑप्टिक्स) प्रणाली का क्षेत्र विकसित हो चुका है जो बल बढ़ाने वाला है और अब यह धीरे–धीरे एक आधार बन रहा है जिस पर आधुनिक सैन्य अभियान चलाए जा सकेंगे। एयर मार्शल दीक्षित ने कहा, ''मैंने अपने पूरे करियर में इस परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप से देखा है और आज हम एक क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं, जो यह परिभाषित करेगी कि 21वीं सदी में हम शक्ति को कैसे समझते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं और उसे कैसे पेश करते हैं।'' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हाल के महीनों में इसके पुख्ता सबूत सामने आए हैं। अपने संबोधन में उन्होंने समकालीन युद्ध में 'गहन निगरानी' के महत्व पर जोर दिया। अधिकारी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से सबक मिला है कि 'आधुनिक युद्ध में प्रौद्योगिकी के कारण दूरी और संवेदनशीलता के बीच के संबंध में मूलभूत परिवर्तन आ गया है।' इस सबक को सैन्य रणनीतिकार शायद अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। उन्होंने कहा कि इसने समकालिकता को एक नया अर्थ दिया है, पहले क्षितिज तत्काल खतरे की सीमा को चिह्नित करता था, लेकिन आज स्कैल्प, ब्रह्मोस आदि जैसे सटीक–निर्देशित हथियारों ने 'भौगोलिक बाधाओं को लगभग निरर्थक बना दिया है'। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने के मकसद से पाकिस्तान की सीमा में काफी अंदर तक हमला करने के लिए लंबी दूरी की हथियार प्रणालियों आदि का इस्तेमाल किया था। एयर मार्शल दीक्षित ने कहा कि जब हथियार सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों पर सटीक निशाना साध सकते हैं, तो सामने, आगे–पीछे, युद्ध क्षेत्र, गहराई वाले क्षेत्र जैसी पारंपरिक अवधारणाएं अप्रासंगिक हो जाती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह नयी वास्तविकता मांग करती है कि हम अपनी निगरानी का दायरा उससे कहीं अधिक बढ़ाएं जिसकी पिछली पीढ़ियां कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। वह थिंक–टैंक 'सेंटर फॉर एयर पॉवर स्टडीज' (सीएपीएस) और 'इंडियन मिलिट्री रिव्यूज' (आईएमआर) द्वारा 'सर्विलांस एंड इलेक्ट्रो–ऑप्टिक्स' विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।

केसीआर परिवार को कांग्रेस में नहीं मिलेगा प्रवेश: मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी

नयी दिल्ली, (भाषा) तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बुधवार को कांग्रेस द्वारा बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव के परिवार के किसी भी सदस्य को पार्टी में शामिल करने की संभावना को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया और उन्हें 'राज्य का दुश्मन' करार दिया। केसीआर परिवार में आंतरिक कलह के सार्वजनिक रूप से सामने आने के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''केसीआर परिवार के सदस्यों को कांग्रेस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जब तक रेवंत रेड्डी हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है।'' रेड्डी का यह बयान केसीआर परिवार में गहराते विवाद की पृष्ठभूमि में आया है जो अब राजनीतिक क्षेत्र तक फैल गया है। इससे भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) में अशांति फैल गई है, जिसे 10 साल के शासन के बाद दिसंबर 2023 में राज्य की सत्ता से बाहर कर दिया गया था। केसीआर की बेटी के. कविता ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को जताया है और सामाजिक न्याय और पार्टी की आंतरिक गतिविधियों के बारे में चिंता जताई है, जिससे बीआरएस के प्रथम परिवार के मतभेद उजागर हो गए हैं। पारिवारिक कलह को खारिज करते हुए रेड्डी ने इसे राज्य की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने का एक हताश प्रयास बताया। उन्होंने कहा, ''केसीआर परिवार में दरार कुछ और नहीं बल्कि राज्य में पार्टी की प्रासंगिकता खत्म होने के बाद लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश है।'' मुख्यमंत्री ने राज्य भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी पर भी निशाना साधा और उन पर मोदी कैबिनेट में दो बार केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद तेलंगाना के विकास के लिए केंद्रीय निधि हासिल करने में विफल रहने का आरोप लगाया। रेड्डी ने आरोप लगाया, ''किशन रेड्डी मोदी कैबिनेट में दो बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए केंद्र से कभी कोई बात नहीं की। उन्होंने कभी अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और राज्य के लिए केंद्र से धन प्राप्त करने की कोशिश नहीं की।'' उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रह्लाद जोशी तमिलनाडु और कर्नाटक में मेट्रो विकास सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन किशन रेड्डी मेट्रो परियोजना का विरोध कर रहे हैं।

संसदीय समिति ने हरियाणा की अनुसूचित जातियों के लिए कल्याणकारी उपायों की समीक्षा की

चंडीगढ़, (भाषा) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित एक संसदीय समिति ने एक अध्ययन के तहत बुधवार को यहां का दौरा किया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। लोकसभा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में समिति ने हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य में अनुसूचित जातियों की सामाजिक–आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के बारे में चर्चा की।

केरल में मानसून हुआ फिर सक्रिय: आईएमडी ने चार जिलों के लिए जारी किया 'ऑरेंज अलर्ट'

तिरुवनंतपुरम, केरल में मानसून की अति सक्रियता की वजह से बुधवार को कई इलाकों में भारी बारिश हुई और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) को चार जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करना पड़ा। आईएमडी ने बुधवार के लिए राज्य के एर्णाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर और कासरगोड जिलों में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया।इसके अलावा उसने राज्य के आठ अन्य जिलों में बुधवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया। आईएमडी ने इसी के साथ बृहस्पतिवार को दो जिलों के लिए, शुक्रवार को चार जिलों के लिए, शनिवार को नौ जिलों के लिए और रविवार को 14 जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। 'ऑरेंज अलर्ट' का अभिप्राय है कि 24 घंटे के भीतर 11 सेमी से 20 सेमी तक मूसलाधार बारिश हो सकती है जबकि 'येलो अलर्ट' का मतलब है छह सेमी से 11 सेमी के बीच भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने तटीय क्षेत्र में तेज हवाओं और खराब मौसम की स्थिति की आशंका के मद्देनजर मछुआरों को बुधवार से रविवार तक केरल–कर्नाटक–लक्षद्वीप तटों पर मछली पकड़ने के लिए नहीं जाने की भी सलाह दी है। केरल में मानसून ने 24 मई को दस्तक दी थी और भारी बारिश तथा तेज हवाओं के कारण पूरे राज्य में सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचा, सड़कें तथा निचले इलाके जलमग्न हो गए, पेड़ तथा बिजली के खंभे उखड़ गए। मानसून के दस्तक देने के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में 31 मई तक मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद इसमें कमी आई थी।

रेलवे का परीक्षण, प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को टिकट की स्थिति के बारे में 24 घंटे पहले सूचना दी

नयी दिल्ली, (भाषा) रेल मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि एक परीक्षण शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रतीक्षा सूची में शामिल यात्रियों के टिकटों की स्थिति के बारे में ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे पहले सूचना दी गई, जबकि फिलहाल यात्रियों को केवल चार घंटे पहले सूचित किया जाता है। मंत्रालय के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि यात्रियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद ही प्रायोगिक परियोजना को नीति का हिस्सा बनाया जाएगा। रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने कहा, ''हमने बीकानेर डिवीजन में यह प्रायोगिक परियोजना शुरू की, जिसके तहत ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे पहले चार्ट तैयार किए गए। फिलहाल यह काम चार घंटे पहले किया जाता है।'' उन्होंने कहा कि यह परीक्षण उन यात्रियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है जो 'वेटिंग टिकट' के कारण अपनी यात्रा के बारे में अनिश्चित रहते हैं। उन्होंने कहा, ''अब अगर उन्हें 24 घंटे पहले पता चल जाए कि उनका टिकट कन्फर्म हो गया है, तो वे अपनी यात्रा की बेहतर योजना बना सकते हैं।'' हालांकि, एक बार टिकट कंफर्म हो जाने पर इसे कैंसिल करने पर यात्रियों को जुर्माने के रूप में टिकट की राशि का एक बड़ा हिस्सा नहीं मिलेगा। टिकट कैंसिल नीति के अनुसार, अगर कंफर्म टिकट प्रस्थान से 48 घंटे से 12 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो यात्रियों को टिकट राशि का 25 प्रतिशत वापस मिलेगा। यदि प्रस्थान से 12 घंटे से चार घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो उन्हें केवल 50 प्रतिशत राशि ही वापस मिलेगी। अधिकारियों ने कहा, ''टिकट रद्द होने के कारण खाली होने वाली सीट वर्तमान बुकिंग प्रणाली के माध्यम से भरी जाएंगी।''

उप्र के 44 जिलों में नए तरीके से खेती करेंगे किसान, मौसम नहीं होने पर भी मिलेंगी पौष्टिक सब्जियां

लखनऊ, (भाषा) उत्तर प्रदेश के किसानों को 'ग्रीन हाउस' और 'पॉली हाउस' जैसी खेती की सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किया जा रहे हैं, जिससे वे सीजन नहीं होने के बावजूद पौष्टिक सब्जियां और अनाज उगा सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा बुधवार को यहां जारी एक बयान के मुताबिक लखनऊ, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर और अमेठी समेत 44 जिलों में यह सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। बयान में कहा गया है कि इनमें से 24 जिलों में ग्रीन हाउस बनकर तैयार हो चुके हैं जबकि 20 जिलों में तेजी से इनका निर्माण किया जा रहा है। बयान के अनुसार ये सभी विकास कार्य कृषि अवसंरचना निधि योजना के तहत कराए जा रहे हैं और इसके साथ ही एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत सब्सिडी भी दी जा रही है। बयान में कहा गया है कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और किसानों की आय को दोगुना करने के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी में समय के साथ बदलाव करके किसानों को आधुनिक खेती के लिए तैयार किया है। बयान के अनुसार अब ग्रीन हाउस और पॉली हाउस जैसी तकनीकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे किसान सीजन न होने पर भी पौष्टिक सब्जियां और अनाज की फसलें उगा सकें। बयान में कहा गया है कि लखनऊ, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, अमेठी समेत 44 जिलों के किसान अब इस तरह का बदलाव लाने जा रहे हैं। बयान के मुताबिक प्रदेश के 44 जिलों में किसानों को ग्रीन हाउस और पॉली हाउस जैसी संरक्षित खेती की सुविधा प्रदान की जा रही है, इनमें से 24 जिलों में ग्रीन हाउस बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 20 जिलों में तेजी से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। बयान में कहा गया है कि सरकार का उद्देश्य है कि हर मौसम में किसान बेहतर उत्पादन कर सकें और बाजार में ताजे उत्पाद उपलब्ध करा सकें।

संपादकीय

पीएम मोदी सरकार के 11 वर्ष – जनकल्याणकारी योजनाओं से बदलता भारत

...... प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे लाखों युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिला। इसके तहत तीन स्तरों पर ऋण दिया गया – शिशु, किशोर और तरुण – ताकि व्यवसाय की हर अवस्था में सहायता सुनिश्चित हो सके। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया अभियानों ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया। इसके तहत स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट, फंडिंग, बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रशिक्षण की सुविधाएं दी गईं। आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसे कोविड–19 महामारी के दौरान आरंभ किया गया, ने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। इसके तहत किसानों, छोटे व्यापारियों, एमएसएमई सेक्टर और प्रवासी श्रमिकों को राहत पहुंचाई गई। आत्मनिर्भर भारत पैकेज ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया, रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बल दिया और विदेशों पर निर्भरता कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष ₹6000 की सहायता सीधे उनके खाते में दी गई, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिली। इसके अतिरिक्त, ई–नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) जैसे नवाचारों से कृषि विपणन में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से राहत दिलाई और जोखिम को कम किया। किसान रेल और कृषि उड़ान जैसी पहलों ने कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ किया। सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के जरिए न्यूनतम प्रीमियम पर बीमा कवच उपलब्ध कराया। ये योजनाएं गरीब और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हुईं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव–गांव में पाइप द्वारा स्वच्छ जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई, जिससे महिलाओं के श्रम की बचत हुई और स्वास्थ्य में सुधार आया। इस योजना ने ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता को उच्च स्तर पर पहुंचाया। शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई, जिससे स्कूली शिक्षा की संरचना, भाषा नीति और कौशल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार किए गए। इस नीति ने भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया। डिजिटल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा जैसी व्यवस्थाएं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर रही हैं। डिजिटल विश्वविद्यालयों, स्किल इंडिया और ई–विद्या जैसे प्लेटफॉर्म्स ने गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के जरिए प्रवासी मजदूरों को कहीं भी राशन पाने की सुविधा मिली, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। इस योजना ने खासकर कोरोना महामारी के समय श्रमिकों को राहत प्रदान की। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में गति शक्ति, भारतमाला, सागरमाला और बुलेट ट्रेन परियोजनाओं ने भारत को भविष्य के अनुकूल बना दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार हुआ और दूरदराज के गांवों को मुख्यधारा से जोड़ा गया। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी परियोजनाएं आधुनिक परिवहन का प्रतीक बन गई हैं, जो न केवल तेज रफ्तार यात्रा का अनुभव देती हैं, बल्कि 'मेक इन इंडिया' की सफलता को भी प्रदर्शित करती हैं। डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत डिजीलॉकर, भीम एप, कोविन पोर्टल, ई–गवर्नेंस जैसे नवाचारों से शासन पारदर्शी और कुशल बना। कोविन पोर्टल ने कोरोना वैक्सीनेशन को सफल और सुव्यवस्थित बनाया, जिससे भारत ने रिकॉर्ड समय में वैक्सीन वितरण सुनिश्चित किया। भीम एप और UPI ने डिजिटल भुगतान को जन–जन तक पहुंचाया और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल लेनदेन मंच बना दिया। आज देश में करोड़ों लोग बिना नकदी लेनदेन कर पा रहे हैं, जिससे काले धन पर अंकुश लगाने में सहायता मिली है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, मातृत्व वंदना योजना, महिला हेल्पलाइन और कार्यस्थल सुरक्षा जैसे कदम उठाए गए, जिससे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी बढ़ी।. आत्मनिर्भर नारी योजना, महिला स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और SHGs को वित्तीय सहायता जैसे कार्यक्रमों ने ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार और सम्मान प्रदान किया। सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से बेटियों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई। हाल के वर्षों में लिंगानुपात में सुधार आया है और महिलाओं की शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत ने ळ20 की सफल अध्यक्षता, ब्रिक्स, क्वाड और ग्लोबल साउथ जैसे मंचों पर प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई। भारत की विदेश नीति बहुपक्षीयता, रणनीतिक संतुलन और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में अग्रसर हुई है। चंद्रयान–3, आदित्य एल–1 और गगनयान जैसे अंतरिक्ष मिशनों ने भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया। क्त्क् और पैत्ट जैसे संस्थानों को नई ऊर्जा मिली है और अब भारत रक्षा व अंतरिक्ष उपकरणों का निर्यातक बनने की दिशा में अग्रसर है। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने सीमाओं की रक्षा से लेकर सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण तक कई बड़े कदम उठाए। ब्वै की नियुक्ति, अग्निपथ योजना, और रक्षा क्षेत्र में थ्क्प् में वृद्धि जैसे निर्णयों ने भारतीय सेना को और आधुनिक व आत्मनिर्भर बनाया। सीमा सड़क संगठन (ठत्व्) और रणनीतिक टनल परियोजनाओं ने सीमावर्ती इलाकों में गतिशीलता को बढ़ाया है। आतंकवाद विरोधी कदमों, जैसे बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक और जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 का निष्कासन, ने सुरक्षा नीति में निर्णायक बदलाव को दर्शाया।

मन की बात और हर घर तिरंगा जैसे अभियानों ने सरकार और आम जनता के बीच संवाद का सेतु मजबूत किया। स्वच्छता ही सेवा, फिट इंडिया मूवमेंट, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कार्यक्रमों ने जनभागीदारी के साथ राष्ट्र निर्माण की अवधारणा को मजबूत किया। योग दिवस को वैश्विक मान्यता दिलाना, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की संस्कृति को समर्पण का प्रमाण बन गया है। अमृत महोत्सव और डिजिटल गैलरियों जैसे सांस्कृतिक अभियानों ने देश के युवाओं को अपनी विरासत से जोड़ने का कार्य किया है। इन 11 वर्षों में मोदी सरकार ने शासन को योजनाबद्ध, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाया है। डिजिटल परिवर्तन, अवसंरचना विकास, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य सुरक्षा, महिला सम्मान, किसान सहायता, युवा सशक्तिकरण और वैश्विक नेतृत्व– हर क्षेत्र में भारत ने एक नई ऊंचाई प्राप्त की है। यह कार्यकाल न केवल योजनाओं के कार्यान्वयन का रहा है, बल्कि यह भारतीय समाज के हर तबके तक बदलाव पहुंचाने की ईमानदार कोशिश का प्रतीक भी है। आज भारत आत्मनिर्भरता, नवाचार और विकास की राह पर पूरी मजबूती से खड़ा है और यह सब 11 वर्षों की सशक्त, संवेदनशील और दूरदर्शी नेतृत्व की देन है।

कृष्णा अग्रवाल
focusnews9@gmail.com

भारतीय जनता पार्टी सरकार के 11 वर्ष

डिजिटल भारत से आत्मनिर्भर भारत तक: नई शक्ति, नई सोच

डॉ अनिल जैन
पूर्व संसद सदस्य, राज्य सभा

9 जून 2025 को केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 11 वर्ष पूरे हुए। यह केवल एक राजनीतिक सफर नहीं, बल्कि "न्यू इंडिया" की वो विकास यात्रा है, जिसमें तकनीक, आत्मनिर्भरता, सुशासन और सुरक्षा– सब एक साथ कदमताल करते दिखाई देते हैं। 2014 से पहले का भारत एक ऐसा देश था, जो अपने ही संसाधनों का कुशल प्रयोग नहीं कर पा रहा था। योजनाएं काग़ज़ों पर बनती थीं और बंद कमरों में दम तोड़ देती थीं। लेकिन बीते 11 वर्षों में भारत ने खुद को एक सशक्त, तेज़, आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर राष्ट्र में बदल दिया है।

डिजिटल क्रांति का उदय: तकनीक से जनता का सशक्तिकरण: वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 'डिजिटल इंडिया' अभियान की नींव रखी– एक ऐसा ऐतिहासिक संकल्प, जिसका उद्देश्य केवल तकनीकी विस्तार नहीं, बल्कि "भारत को एक ज्ञान–आधारित, पारदर्शी, उत्तरदायी और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में रूपांतरित करने का था।" इस पहल के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की, जहां सरकार की सेवाएं तकनीक के माध्यम से सीधे नागरिकों तक पहुँचें, डिजिटल साक्षरता गांव–गांव तक फैले, और हर नागरिक एक 'डिजिटल नागरिक' बनकर आधुनिक भारत के निर्माण में भागीदार बने। यह एक दूरदर्शी राष्ट्रनायक का सपना था– एक ऐसा भारत बनाने का, जहां तकनीक केवल सुविधा न रहे, बल्कि सशक्तिकरण का साधन बन जाए।

प्रमुख उपलब्धियाँ:

- **UPI (Unified Payments Interface):** आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान तंत्र है। सितंबर 2024 तक यूपीआई पर औसत दैनिक लेनदेन बढ़कर 500 मिलियन से अधिक हो गया। NPCI "भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम" के रिपोर्ट के आधर पर केवल मई 2025 की बात करें तो UPI के माध्यम से कुल 25,14297 करोड़ रु का लेनदेन दर्ज हुआ।

वर्ष 2024 में, भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस लेनदेन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें मात्रा के साथ इसके मूल्य में भी काफी वृद्धि हुई। प्लेटफ़ॉर्म ने लगभग 172 बिलियन लेनदेन संसाधित किया, जो साल–दर–साल 46% की वृद्धि है। कुल लेनदेन की बात हो तो यह मूल्य भी 35% बढ़कर रु 247 ट्रिलियन दर्ज किया गया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा जारी किए गए आंकड़े इस वृद्धि की पुष्टि करते हैं।

फत् कोड अब गांव के हलवाई से लेकर महानगर के मॉल तक आम दृश्य बन चुका है। यहां तक की एक सब्जी बेचने वाला भी जब मात्र 15 रु की सब्जी का भुगतान करने के लिए QR कोड आगे बढ़ाता है, तब हमें इस बात का एहसास होता है कि 2014 का पहले हम कतार में कितने पीछे खड़े थें।

आज अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर जैसे कई देश अब भारत की भुगतान प्रणाली को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं– यह डिजिटल नेतृत्व का प्रमाण है।

- **डिजिटल पहचान :** 140 करोड़ नागरिकों को आधार से जोड़कर सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल बना दिया गया। इससे फर्जीवाड़ा रुका, बिचौलिए हटे, और इससे सरकारी योजना का सीधा लाभ जनता को मिल रहा है।
- **DigiLocker and e-Governance:** स्कूल सर्टिफिकेट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक अब डिजिटल हो चुके हैं। सरकारी कार्यालयों में फाइल नहीं, फोल्डर ऑनलाइन चलते हैं। अब हमें किसी फाइल को अपने साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं, बल्कि केवल क्पहपस्वबामत के माध्यम से हम अपने से जुड़े सारे दस्तावेज लेकर चलते हैं।
- **भारतनेट परियोजना:** भारतनेट परियोजना के अंतर्गत अब तक देश के 6 लाख से अधिक गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है– एक ऐसा क्रांतिकारी कदम, जिसने डिजिटल इंडिया की रोशनी को गांव–गांव तक पहुंचाया है। आज भारत का ग्रामीण नागरिक भी वैश्विक सूचना–तंत्र से सीधा जुड़ चुका है –वह अब सिर्फ खेत–खलिहान तक सीमित नहीं, बल्कि तकनीकी सशक्तिकरण का हिस्सा बन चुका है।

"जो भारत कभी कतारों में खड़ा रहता था,
आज वही भारत QR कोड स्कैन कर के आगे बढ़ रहा है।"

आत्मनिर्भर भारत: वैश्विक चुनौतियों में स्वदेशी समाधान: वर्ष 2020, जब दुनिया कोरोना महामारी से कांप रही थी, भारत ने उस संकटकाल को अवसर में बदला और 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा की। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीति थी– आर्थिक पुनरुद्धार, स्वदेशी निर्माण, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के संकल्प की।

प्रमुख स्तंभ:

- **Make in India:** मोबाइल फोन, रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर सेमीकंडक्टर जैसे उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों तक– भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक सशक्त उत्पादक राष्ट्र के रूप में उभर चुका है। 'मेक इन इंडिया' के संकल्प ने देश को विनिर्माण की वैश्विक दौड़ में अग्रणी बना दिया है। आज भारत मोबाइल निर्माण में चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है– यह न सिर्फ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम है, बल्कि विश्व को भारत की उत्पादन शक्ति का स्पष्ट संदेश भी है।
- **Startup India & Innovation:** आज भारत नवाचार की भूमि बन चुका है– जहां विचार सिर्फ कल्पनाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि व्यवसाय और समाधान में बदलते हैं। देश में अब तक 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 125 से अधिक ने यूनिकॉर्न (एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन) का दर्जा प्राप्त कर लिया है। यह अभूतपूर्व वृद्धि भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाती है।

इस परिवर्तन के केंद्र में है– भारत का युवा, जिसकी कल्पनाशक्ति, साहस और आत्मविश्वास ने 'नौकरी मांगने' की सोच को 'नौकरी देने' के अभियान में बदल दिया है।

लेकिन भारत का नवाचार केवल डिजिटल या टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, यह तो विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य और उन्नत निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी अपनी छाप छोड़ रहा है।

- **API (Active Pharmaceutical Ingredients):** एक समय था जब भारत अपनी दवाओं के लिए अन्य देशों पर निर्भर था। लेकिन आज भारत ने API निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं। अब हम अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को सशक्त बना रहे हैं और दुनिया के लिए एक भरोसेमंद मेडिकल सप्लायर बन चुके हैं।
- **Nano Urea और Nano DAP:** पारंपरिक उर्वरकों की जगह अब Nano Urea और Nano DAP जैसे अभिनव समाधान ला रहे हैं। IFFCO द्वारा विकसित Nano Urea ने खेती को अधिक टिकाऊ, सस्ता और पर्यावरण–अनुकूल बनाने में मदद की है। अब किसान कम उर्वरक में ज्यादा उत्पादन पा रहे हैं– ये सच में भारत की कृषि क्रांति का अगला चरण है।
- **Semiconductor क्रांति:** भारत अब केवल एक डिजिटल उपभोक्ता नहीं रहा, बल्कि डिजिटल निर्माता बनने की ओर अग्रसर है। भारत ने पहली बार अपनी खुद की सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाइयाँ स्थापित करनी शुरू कर दी हैं– जो भविष्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, AI, और क्लाउड कंप्यूटिंग दुनिया के लिए बुनियाद तैयार करेंगी। इससे भारत वैश्विक सप्लाई चेन का एक अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है।

यह है नया भारत– जहां आत्मनिर्भरता केवल एक सपना नहीं, बल्कि रोज़ की हकीकत बन रही है। जहां इनोवेशन सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि जीवनशैली बन चुका है।

और इस परिवर्तन का श्रेय जाता है– हमारे नवोन्मेषी युवाओं, वैज्ञानिकों, किसानों, उद्यमियों और हमारे देश के यशश्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को।

- **Vocal for Local to Global:** प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से एक आत्मीय आह्वान किया– 'लोकल के लिए वोकल बनिए और लोकल को ग्लोबल बनाइए।' यह कोई साधारण नारा नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की आत्मा थी। उनके इस आव्हान ने न केवल देश के छोटे कारीगर, बुनकर, कुम्हार और शिल्पकारों को सम्मान दिया, बल्कि उनके उत्पादों को वैश्विक बाज़ारों में नई पहचान भी दिलाई। परिणामस्वरूप खादी, हस्तशिल्प, और GI टैग प्राप्त उत्पादों की मांग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेज़ी से बढ़ी है– जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को वैश्विक मंच मिला और भारत की सांस्कृतिक धरोहर एक बार फिर दुनिया के सामने गौरव से खड़ी है।

राष्ट्रीय सुरक्षा: जब भारत ने चुप्पी तोड़ी और जवाब देना सीखा– 2014 के बाद का भारत– केवल कूटनीतिक शालीनता का हीं नहीं, रणनीतिक स्पष्टता और सैन्य निर्णायकता का परिचायक बन गया है।

ऐतिहासिक निर्णय–

सर्जिकल स्ट्राइक (2016): अब भारत चुप नहीं बैठता: 18 सितम्बर 2016 को जम्मू–कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के एक ब्रिगेड मुख्यालय पर तड़के आतंकियों ने हमला कर दिया। इस कायरतापूर्ण हमले में भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हो गए और यह घटना देशभर को झकझोर देने वाली थी। यह हमला केवल सेना पर नहीं, भारत की सहनशीलता और सुरक्षा नीति पर भी एक चुनौती थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी समय स्पष्ट कर दिया था: "पीछे से वार करने वालों को अब दुनिया के सामने जवाब मिलेगा।" और इसी संकल्प के साथ, 28–29 सितम्बर 2016 की रात, भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज ने पहली बार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। यह कार्रवाई सीमा पार सात से अधिक आतंकी लॉन्च पैड्स पर की गई, जिसमें दर्जनों आतंकी मारे गए, कई ठिकाने पूरी तरह नष्ट किए गए और, भारतीय सेना का एक भी जवान हताहत नहीं हुआ। यह ऑपरेशन भारत के लिए मात्र सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक नई रणनीतिक सोच का प्रतीक बन गया कृ जिसमें अब "शांति की चाह के साथ प्रतिकार की पूरी तैयारी" का संदेश छिपा था।

यह कार्रवाई तीन बड़े बदलावों की घोषणा थी:

1. भारत अब सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद को सहन नहीं करेगा।
2. रणनीतिक चुप्पी के युग का अंत हो गया है।
3. भारत की सेना और नेतृत्व में साहस, संकल्प और क्षमताओं का नया युग आरंभ हो चुका है।

"अब भारत की नीति साफ है– वार होगा तो जवाब ज़रूर होगा, और वह भी दुश्मन के घर में घुसकर।"

"अब भारत चुप नहीं बैठता– वो गिनता भी है, और घुसकर मारता भी है।"

एयर स्ट्राइक (2019):

- 14 फरवरी 2019 को पुलवामा, जम्मू–कश्मीर में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल के काफिले पर हुए कायरतापूर्ण आत्मघाती हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। यह हमला भारत के दिल पर था कृ और पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। देश की जनता ने इस बार केवल मोमबत्तियाँ नहीं जलाईं, बल्कि निर्णायक कार्रवाई की अपेक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि – **"नई नीति, नया भारत–अब चुप नहीं बैठेगा।"**

26 फरवरी 2019 की सुबह भारतीय वायुसेना के मिराज–2000 विमानों ने नियंत्रण रेखा पार करते हुए पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश–ए–मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। यह ऑपरेशन लगभग 300 किलो बम गिराकर आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने वाला था– और यह पहला मौका था जब भारत ने आतंक के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार जाकर की।

यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह था– "नए भारत" का संदेश: अब हम आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जवाब घर में घुसकर देंगे।

ऑपरेशन सिंदूर (2025): हमले का निर्णायक उत्तर

एक ऐसा अभियान, जो न केवल प्रभावी था, बल्कि मानवीय मूल्यों और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का प्रतीक भी बन गया।

22 अप्रैल 2025 कृ यह तारीख भारत के हृदय में गहरे घाव छोड़ गई।

जम्मू–कश्मीर के पहलगाम में हुए एक क्रूरतम आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई।

यह हमला सिर्फ लोगों की जान लेने वाला नहीं था, बल्कि यह भारत की आस्था, अखंडता और आत्मसम्मान पर हमला था।

इस हमले के बाद देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने तत्काल और निर्णायक प्रतिकार की रणनीति बनाई। और इसी के तहत भारत ने 6–7 मई 2025 को **"ऑपरेशन सिंदूर" की शुरुआत की–** एक गोपनीय, तीव्र और सर्जिकल सैन्य अभियान, जिसने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों को लक्ष्य बनाया।

6 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को सटीकता से नष्ट किया। 100 से अधिक आतंकवादी मार गिराए गए, जिनमें कई शीर्ष कमांडर शामिल थे। 11 पाकिस्तानी एयरबेस भारत की सटीक मिसाइल और ड्रोन हमलों में पूरी तरह बर्बाद हो गए।

पाकिस्तान को भारी सैन्य व मनोवैज्ञानिक क्षति उठानी पड़ी।

इतना सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने अपने आधिकारिक डोज़ियर में इस ऑपरेशन को "इतिहास में पहली बार इतने घातक और एकतरफा हमले" के रूप में स्वीकार किया– यह भारत की रणनीतिक क्षमता और वैश्विक सैन्य हैसियत की पुष्टि थी।

'ऑपरेशन सिंदूर' एक संदेश था– और संकल्प भी

यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी। **यह भारत की ओर से एक घोषणा थी कि–**

"अब अगर भारत पर वार होगा, तो जवाब सीमाओं में नहीं बंधेगा।"

जहां एक ओर इस ऑपरेशन ने दुश्मनों के हौसले तोड़े, वहीं दूसरी ओर इसने भारतवासियों के मन में विश्वास जगाया कि–

हर भारतीय की सुरक्षा, हमारे सरकार की ज़िम्मेदारी है– चाहे वह किसी भी सीमा के भीतर या बाहर क्यों न हो। "अब नया भारत घर में नहीं घुसने देता, दुश्मन के घर में घुसकर मारता है। शांति की इच्छा हमारी नीति है, पर सटीक जवाब देना अब हमारी रणनीति है।"

LAC पर मज़बूती: लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर अरुणाचल की हरियाली तक, भारत अब केवल चौकसी नहीं कर रहा, बल्कि निर्णायक तैयारी और संरचना के साथ खड़ा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन जैसे देश की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए, मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार किया है। आज LAC पर न केवल सड़कें, पुल, एयरस्ट्रिप और सुरंगें तेज़ी से विकसित की जा रही हैं, बल्कि सेना की तैनाती, हथियारों की उपलब्धता और जवाबी रणनीति में भी एक नया आत्मविश्वास झलकता है। बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन के माध्यम से हजारों किलोमीटर की नई सड़कें बनाई जा चुकी हैं, जो न केवल सैनिकों की तेज़ आवाजाही सुनिश्चित करती हैं, बल्कि आम नागरिकों को भी जोड़ती हैं।

यह बदलाव सिर्फ बुनियादी ढांचे का नहीं, बल्कि सोच का है–

अब भारत LAC पर न तो झुकेगा, न रुकेगा कृ जवाब भी देगा, और ज़मीन पर मौजूद भी रहेगा।

जन–जन की सरकार: योजनाएं जो हर घर तक पहुँचीं

"जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता तक।"

यह केवल लोकतंत्र की परिभाषा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की कार्यशैली बन चुकी है– जिसमें हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचना ही असली सफलता मानी जाती है।

पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने "Antyodaya"– पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाने के संकल्प को सिर्फ सिद्धांत नहीं, व्यवहारिक धरातल पर उतारा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना:

"हर गरीब का सपना–अपना पक्का घर" : अब तक 3.22 करोड़ से अधिक जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं। ये महज़ घर नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास की नींव हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:

"अब रसोई से धुआं नहीं, मुस्कान उठती है।"

11 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर उन्हें धुएं से मुक्ति और स्वच्छ जीवनशैली का अधिकार दिया गया है।

PM-Kisan सम्मान निधि योजना: "सीधे खाते में मदद– बिना बिचौलिए, बिना भ्रष्टाचार।"

अब तक 10 करोड़ किसानों को सालाना ₹6,000 की सीधी वित्तीय सहायता दी जा रही है– जिससे कृषि आधारित परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।

आयुष्मान भारत– जन आरोग्य योजना: "बीमारी अब गरीबी का कारण नहीं बनेगी।"

अब तक 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को ₹5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिल चुका है– यह दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना बन चुकी है।

जल जीवन मिशन:

"हर घर जल– हर जीवन सुखद।"

2019 में शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक 13 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से शुद्ध जल की सुविधा दी जा चुकी है।

इन सभी योजनाओं को समय पर, पारदर्शिता के साथ और प्रभावी तरीके से लागू करने में "JAM Trinity"– Jan Dhan (बैंक अकाउंट), Aadhaar और Mobile की भूमिका क्रांतिकारी रही है। यही है डिजिटल इंडिया का असली चेहरा, जिसने गरीब को सशक्त किया, योजनाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाया और "सुनवाई से आगे, पहुंचाई तक" का विश्वास कायम किया।

11 वर्ष, एक विचार– सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास

आज का भारत केवल एक भूगोलिक सीमाओं वाला राष्ट्र नहीं, बल्कि दुनिया भर के लिए एक जीवंत प्रेरणा बन चुका है कृ जो डिजिटल क्रांति से लेकर अंतरिक्ष की ऊँचाइयों तक, सैन्य ताकत से लेकर सामाजिक न्याय और समावेशन तक, हर क्षेत्र में नए युग की शुरुआत का अग्रदूत बन रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त, दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व ने यह सिद्ध कर दिया है कि

"अगर नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो और नीयत में राष्ट्रहित हो– तो इतिहास बदला जा सकता है।"

बीते 11 वर्षों में भारत ने सपनों को संकल्प में, और संकल्पों को सिद्धि में बदला है। आज भारत न सिर्फ तेजी से बदल रहा है– बल्कि बदलाव की परिभाषा बन चुका है।

"जहां अंधेरों को उजाले से हराया गया है, जहां तकनीक ने गांवों को शहरों से जोड़ा है,

जहां विकास केवल आकड़ों में नहीं, बल्कि जन–जन की मुस्कान में दिखता है–

वह भारत अब थमता नहीं, रुकता नहीं –निरंतर चलता रहता है,

इसकी गति मापना अब किसी के बस में नहीं, यह चंद्रयान–3 और फाइटर जेट तेजस से भी तीव्र गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर है !"

यही है 'नया भारत'– जो तप, त्याग और 11 वर्षों की विकास–यात्रा से निखरकर सामने आया है।

एक ऐसा भारत, जो अब न केवल खुद को बदल रहा है, बल्कि दुनिया को नई दिशा देने की क्षमता भी रखता है।

इन 11 वर्षों की गाथा को केवल कुछ पन्नों या शब्दों में समेटना आसान नहीं क्योंकि हर योजना, हर निर्णय, हर जन–आंदोलन अपने आप में एक महाकाव्य है। जिस तरह हर कविता की एक आत्मा होती है, ठीक वैसे ही 'नया भारत' की यह यात्रा भी एक राष्ट्रीय काव्य बन चुकी है– जिसे पढ़ने के लिए सिर्फ आँखें नहीं, बल्कि एक देशभक्त दिल चाहिए।

यह लेख बस उस महायात्रा की एक झलक मात्र है– एक संक्षिप्त परिचय, जिसका विस्तार आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ेंगी, गाएँगी और गर्व से कहेंगी:

"हम उस भारत के साक्षी हैं, जिसने इतिहास नहीं, भविष्य लिखा है।"

सांवले रंग के चलते मिली ठोकर, सुने ताने, कुत्ते ने भी किया रिप्लेस, अब ये हसीना बनी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे रॉयल बहू

फिल्म इंडस्ट्री का ग्लैमर जितना चमकदार नजर आता है, उसके पीछे का संघर्ष उतना ही कड़वा होता है। खासतौर पर अभिनेत्रियों के लिए, जिन्हें कभी रंग, कभी कद तो कभी शरीर की बनावट के आधार पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। बॉलीवुड और साउथ सिनेमा दोनों में हीरोइनों के लिए यही मापदंड हैं। ऐसे में हीरोइनों को कई असफलताओं के बाद सफलता हासिल हो पाती है। आज ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में आपको बताएंगे जो आज न सिर्फ नामी फिल्मी परिवार की बड़ी बहू हैं, बल्कि एक्टिंग के दम पर लोगों का दिल भी जीत रही हैं। जो सांवला रंग कभी उनके लिए अभिशाप से कम नहीं था आज वो उनकी ताकत बन गया है और उनकी रंगत की तारीफें करते लोग नहीं थकते हैं। कौन हैं ये हसीना चलिए आपको बताते हैं।

कैसे हुई बॉलीवुड में शुरुआत : यही कहानी है अभिनेत्री शोभिता धुलिपाला की, जो कभी अपने सांवले रंग की वजह से रिजेक्ट कर दी गई थीं, बल्कि एक बार तो एक विज्ञापन में उन्हें एक कुत्ते से तक रिप्लेस कर दिया गया था, लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि न सिर्फ उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई बल्कि आज वे साउथ इंडिया के सबसे प्रभावशाली फिल्मी घरानों में से एक अक्किनेनी खानदान की बड़ी बहू हैं और देशभर में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। शोभिता ने बॉलीवुड में अनुराग कश्यप की फिल्म 'रमन राघव 2.0' (2016) से कदम रखा। इसके बाद उन्होंने 'शेफ' (2017) में सैफ अली खान के साथ काम किया और 'बार्ड ऑफ ब्लड' जैसे प्रोजेक्ट्स से ओटीटी पर भी पहचान बनाई, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा चर्चा मिली प्राइम वीडियो की हिट वेब सीरीज 'मेड इन हेवन' से, जो साल 2019 में रिलीज हुई। इसमें उन्होंने तारा खन्ना का किरदार निभाया था।

जब रंग बना बाधाः फिल्मी बैकग्राउंड से न होने के चलते शोभिता को शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ा। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ऑडिशन के दौरान कई बार उन्हें सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि वो 'कम गोरी' थीं। यहां तक कि एक बार उन्हें एक कुत्ते से भी रिप्लेस कर दिया गया था, लेकिन इन सबके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि यदि फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनानी है तो पारंपरिक तरीकों से हटकर सोचना होगा। उन्होंने रचनात्मकता को अपनी ताकत बनाया और हर ऑडिशन में अपना 100 प्रतिशत देना जारी रखा।

हम चाहते थे ट्रांसजेंडर लोग अपनी कहानियां खुद कहें : इन ट्रांजिट निर्माता जोया अख्तर

नयी दिल्ली, (भाषा) फिल्म निर्माता जोया अख्तर और रीमा कागती को 'ट्रांसजेंडर' लोगों के जीवन के बारे में चार भागों वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज "इन ट्रांजिट" बनाने का विचार उनकी एक सीरिज "मेड इन हेवन" की वजह से आया था। "इन ट्रांजिट" सीरीज का निर्देशन आयशा सूद ने किया है जबकि अख्तर और कागती इसकी निर्माता हैं। शुक्रवार को प्राइम वीडियो पर सीरीज का प्रीमियर होगा। एलजीबीटीक्यू व्यक्तियों के जीवन को दिखाने के लिए "मेड इन हेवन" की काफी प्रशंसा हुई थी। पहले सीजन में अर्जुन माथुर ने करण नामक समलैंगिक वेडिंग प्लानर की भूमिका निभाई थी जबकि दूसरे सीजन में त्रिनेत्र हलधर गुम्माराजू ने ट्रांसजेडर मेहर का किरदार अदा किया था। जोया ने कहा कि उन्हें इस शो के माध्यम से "एलजीबीटी समुदाय से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली" क्योंकि समुदाय को लगा कि उन्हें प्रामाणिक तरीके से दिखाया गया है। उन्होंने डिजिटल माध्यम से 'पीटीआई–भाषा' को दिए साक्षात्कार में कहा, "जब हमने एक ट्रांस व्यक्ति के किरदार के बारे में लिखा, तो हमें एहसास हुआ कि हम बहुत कम जानते हैं... इसलिए, हमने लोगों का साक्षात्कार करना शुरू किया और जो लोग हमसे बात करते थे, वे बहुत ईमानदार थे। उन्होंने अपने सपनों समेत बहुत कुछ साझा किया। मेहर एक खास तरह का किरदार था, इसलिए यह कहानी ("इन ट्रांजिट" सीरीज) इन साक्षात्कारों से निकली।" जोया ने कहा, "हमने महसूस किया कि यह कुछ ऐसा है जिसे हमें एक अलग तरीके से विस्तारपूर्वक दिखाना चाहिए। उन्हें दर्शकों को उनकी कहानी बताने की जरूरत है और हमने इस बारे में अमेजन प्राइम से बात की, जिसने एक कॉल में झट से इसके लिए हामी भर दी, इसलिए हम भाग्यशाली हैं।" फिल्म निर्माता ने कहा कि उन्होंने सीरीज का निर्देशन करने के लिए सूद को लेने का फैसला किया क्योंकि इसके लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो सनसनीखेज तरीका अपनाए बिना महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने रखे, प्रामाणिक तरीके से सीरीज को आगे बढ़ा सके। फिल्म निर्माता, फोटोग्राफर और संपादक सूद ने कहा कि जब अख्तर और कागती ने उनके सामने यह विचार रखा तो वह थोड़ी उलझन में पड़ गईं, क्योंकि ट्रांसजेंडरों के अनुभव एक बहुत बड़ा विषय है। सूद ने कहा, "मैंने सोचा, 'आप ट्रांस लोगों की कहानी कैसे बताएंगे?' भारत में महिलाओं की तरह, यह विषय बहुत बड़ा है... भारत में एक महिला होने के विविध अनुभव होते हैं, उसी तरह, भारत में ट्रांस होना भी काफी अलग है और यह विशाल, अनोखा और जटिल है। हम इसे कहानियों में कैसे ला सकते हैं?" उन्होंने कहा, "भारत में ट्रांसजेंडर होने का विचार बहुत व्यापक है। इसलिए हम अलग–अलग लोगों से बात करके व्यापक समझ कायम करना चाहते थे। हम चाहते थे कि यह सीरीज भारत में ट्रांस व्यक्तियों के जीवन के इर्द–गिर्द रहे।" सूद ने कहा, "यह भी एक मुद्दा था कि कौन हमें अपनी कहानियां बता सकता है। हर किसी के लिए कैमरे पर आना आसान नहीं होता... ये कठिन होता है, इसलिए यह भी एक मुद्दा था कि वास्तव में कौन हमें ये कहानियां बता सकता है। हम चाहते थे कि लोग अपनी कहानियां खुद कहें।"

हाउसफुल फ्रेंचाइजी बनी सुपरहिट, कर डाली तगड़ी कमाई, छू लिया 963 करोड़ का मुकाम

'हाउसफुल 5' वैसे तो कमाई में गोली की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग्स के मामले में फिसड्डी साबित हुई है। 'हाउसफुल 5' में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, ऋतिश देशमुख, संजय दत्त, नाना पाटेकर, फरदीन खान, सोनम बाजवा और जैकलीन फर्नांडिस जैसी कास्ट मौजूद है। अब सवाल आता है कि फिल्म की कमाई क्यों हो रही है? एक वजह इसकी मल्टीस्टारर कास्ट है तो दूसरी फिल्म के दो अलग–अलग क्लाइमेक्स। दोनों में से किसका प्रभाव कितना ज्यादा है, ये मेकर्स ही बता सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है की 'हाउसफुल 5', हाउसफुल फ्रेंचाइजी की सबसे महंगी फिल्म है। गौर करने वाली बात ये है कि 'हाउसफुल 5' का बजट इतना ज्यादा है कि ये तीन हाउसफुल फिल्मों के बजट को भी पार कर गया है। अब आते हैं इस फिल्म की कमाई और पूरी फ्रेंचाइजी की कमाई पर, जो सैक्निक के आधार पर है।

क्या रहा हर हाउसफुल का बजट? : हाउसफुल 5 की अब तक की कमाई को देखते हुए हाउसफुल फ्रेंचाइजी की कमाई 995 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले साल 2010 में हाउसफुल रिलीज हुई, जिसका बजट 45 करोड़ रुपये का था। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड लगभग 119 करोड़ रुपये कमाए। इसके बाद हाउसफुल का अगला सीक्वल साल 2012 में रिलीज किया गया जिसका बजट मेकर्स ने बढ़ाकर 72 करोड़ कर दिया और फिल्म ने दुनिया भर में 188 करोड़ रुपये की कमाई की। साल 2016 में इस फिल्म का तीसरा पार्ट रिलीज किया गया, जिसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन लीड रोल प्ले करते दिखे। दिखे इस फिल्म का बजट था पूरे 85 करोड़ रुपये और फिल्म ने छापे 185 करोड़ यानी, सीधे तौर पर 100 करोड़ का मुनाफा।

कमाई के मामले में हर हाउसफुल पासः इसके बाद साल 2019 में इस फिल्म के चौथे पार्ट ने दस्तक दी। इस बार अभिषेक बच्चन को बॉबी देओल से रिप्लेस कर दिया गया और फिल्म का बजट रखा गया 175 करोड़ रुपये। फिल्म ने वर्ल्डवाइड लगभग 296 करोड़ रुपये कमाए। अगर हाउसफुल फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट तक के बजट को जोड़ा जाए तो टोटल होता है 202 करोड़ रुपये। सितारों से सजी महफिल वाली 'हाउसफुल 5' में एक्टर्स की भरमार है और यही वजह है कि इसका बजट भी बाकी फिल्मों की तुलना में आसमान छू रहा है। फिल्म का बजट 225 करोड़ रुपये के लमसम है, तीन पार्ट के कुल बजट से 23 करोड़ रुपये ज्यादा है। रिलीज के बाद से पांच दिनों में फिल्म ने वर्ल्डवाइड 175 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। इसके साथ ही पांचों पाट्र्स के बजट का टोटल होता है 602 करोड़ रुपये और कुल कमाई है 963 करोड़ रुपये।

'हाउसफुल 5' आने वाले दिनों में कितनी कमाई करती है यह देखने वाली बात होगी। वैसे इसी के साथ ही ये फिल्म इस साल की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है। बढ़ते आंकड़े के साथ इसमें तब्दीली भी देखने को मिल सकती है। अब तक फिल्म के सभी पाट्र्स ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है और इसकी भी शानदार शुरुआत के साथ यही उम्मीद की जा रही है।

मोदी को राहुल का पत्र, वंचित वर्गों के लिए छात्रवृत्ति और छात्रावासों की स्थिति सुधारने का आग्रह

नयी दिल्ली (भाषा) लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वंचित वर्गों के छात्रों को समय पर पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाए और उनके छात्रावासों की "दयनीय" हालात में सुधार किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ये मुद्दे हाशिए पर रहने वाले समुदायों से आने वाले 90 प्रतिशत छात्रों के लिए शिक्षा के अवसरों में बाधा पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री को लिखे 10 जून की तिथि वाले पत्र में राहुल गांधी ने कहा, "मैं आपसे दो महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने का अनुरोध करता हूं जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों से आने वाले 90 प्रतिशत छात्रों के लिए शिक्षा के अवसरों में बाधा डालते हैं।" उन्होंने कहा, "सबसे पहले तो दलित, एसटी, ईबीसी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए आवासीय छात्रावासों की स्थिति दयनीय है। हाल ही में बिहार के दरभंगा में आंबेडकर छात्रावास के दौरे के दौरान, छात्रों ने एकल कमरे के बारे में शिकायत की, जिसमें 6–7 छात्रों को रहने के लिए मजबूर किया गया था, अस्वच्छ शौचालय, असुरक्षित पेयजल, मेस सुविधाओं की कमी और पुस्तकालयों या इंटरनेट तक की उपलब्धता नहीं थी।" उन्होंने कहा कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्तियों में देरी हो रही हैं और इसमें विफलताएं भी हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, "उदाहरण के लिए, बिहार में, छात्रवृत्ति पोर्टल तीन वर्षों तक गैर–कार्यात्मक था, किसी भी छात्र को 2021–22 में छात्रवृत्ति नहीं मिली। इसके बाद, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले दलित छात्रों की संख्या वित्त वर्ष 2023 में 1.36 लाख से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 69 हजार हो गई। छात्र आगे शिकायत करते हैं कि छात्रवृत्ति राशि अपमानजनक रूप से कम है।" उन्होंने कहा, "हालाँकि मैंने बिहार का उदाहरण दिया है, लेकिन ये विफलताएँ पूरे देश में व्यापक स्तर पर हैं। मैं सरकार से इन विफलताओं को दूर करने के लिए तुरंत दो कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं।" राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि दलित, एसटी, ईबीसी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, भोजन और शैक्षणिक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक छात्रावास का ऑडिट कराएं और कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित करें। उन्होंने यह भी कहा, "पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति समय पर वितरित करें, छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाएं और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करके निष्पादन में सुधार करें।" कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, "मुझे यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि भारत तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के युवा प्रगति नहीं करते। मैं आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में हूं।"

उम्मीद है शांति और प्रगति के लिए प्रार्थनाएं स्वीकार होंगी: फारूक अब्दुल्ला

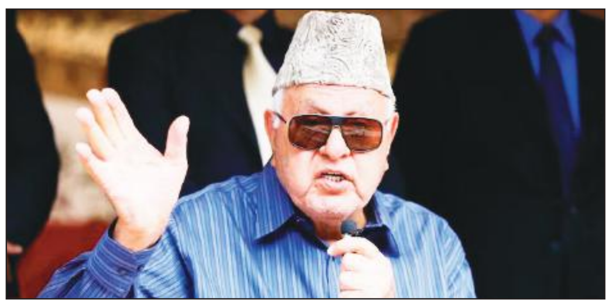

जम्मू/श्रीनगर (भाषा) नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद हाल में शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस से बुधवार को श्रीनगर लौट आए। पूर्व मुख्यमंत्री ने वापस लौटने पर संवाददाताओं से कहा, "बहुत अच्छे से दर्शन किए और मुझे उम्मीद है कि मंदिर में शांति, प्रगति और भाईचारे के लिए की गई हमारी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार होंगी ताकि हम आगे बढ़ सकें और हमारा देश भी आगे बढ़े तथा हम इसके विकास पथ का हिस्सा बन सकें।" सत्तासी वर्षीय अब्दुल्ला ने कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में मंगलवार को पहली बार यात्रा की और कटरा पहुंचे। वह रात भर मंदिर के गर्भगृह में रुके और मंदिर में विशेष प्रार्थना में हिस्सा लिया। उनके साथ उनके पोते जमीर और जाहिद, जम्मू–कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी और मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई विधायक भी थे। मंदिर में रात्रि विश्राम के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा, "मुझे बहुत खुशी हुई।" उन्होंने कहा, "मैं यहां ट्रेन से आया हूं और यह सेवा हमारे लिए एक नई शुरुआत है। इससे न केवल माता के दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि अमरनाथ गुफा मंदिर जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए भी यह फायदेमंद साबित होगा और वे भी बड़ी संख्या में आएंगे। इससे जम्मू–कश्मीर में पर्यटन को लाभ होगा।"

अब्दुल्ला ने कहा कि यह ट्रेन जम्मू–कश्मीर के लिए वरदान है, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, "सफर बहुत शानदार रहा। आप देख सकते हैं कि सैलानी भी आ रहे हैं। यह ट्रेन एक वरदान है। इससे पर्यटन और व्यापार बढ़ेगा। हमारे फल आसानी से बाहर जा सकेंगे और हमारे लोग अब भारत के किसी भी हिस्से में आराम से यात्रा कर सकेंगे।" पूर्व मुख्यमंत्री ने श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर संवाददाताओं से कहा, "यह एक सपना था जिसे मैंने अपने जीवन में साकार होते देखा है।" मंगलवार देर रात मंदिर में 'पीटीआई–भाषा' से बातचीत में मंत्री शर्मा ने कहा कि अब्दुल्ला ने तीन जून को गांदरबल में मेला खीर भवानी की अपनी यात्रा के दौरान वैष्णो देवी मंदिर जाने की इच्छा व्यक्त की थी।उन्होंने कहा, "इस पवित्र शहर (कटरा) पहुंचने के बाद हमने तीन बार दर्शन किए, जो हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है... अब्दुल्ला दरबार तक पहुंचने के लिए दो से तीन किलोमीटर पैदल चले और हमने जम्मू–कश्मीर के लिए प्रार्थना की कि वह अपना खोया हुआ गौरव वापस पा ले। जम्मू–कश्मीर भारत का मुकुट है और हम फिर से उस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं।" मंत्री ने कहा कि उन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत की प्रगति के लिए प्रार्थना की। शर्मा ने इस यात्रा को "ऐतिहासिक" बताया और कहा कि वे इसे जीवनपर्यंत याद रखेंगे। मंत्री ने कहा कि उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और पाकिस्तान की गोलाबारी के पीड़ितों के लिए भी प्रार्थना की। उन्होंने कहा, "वे (पाकिस्तानी) अपने नापाक मंसूबों में कभी सफल नहीं होंगे। आतंकवाद एक धंधा है, लेकिन हमारी बहादुर सेनाओं ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। अगर वे भविष्य में कोई शरारत करने की कोशिश करेंगे तो उनका यही हश्र होगा।" नेशनल कांफ्रेंस के क्षेत्रीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने कहा कि अब्दुल्ला की यात्रा से पूरे देश में सकारात्मक संदेश गया है और "हमें उम्मीद है कि पर्यटन उद्योग जल्द ही पटरी पर लौट आएगा जिसे पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद बड़ा झटका लगा है।"

पायलट के साथ संबंधों पर बोले गहलोत: 'हम लोग दूर कब थे'

जयपुर, (भाषा) राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के साथ अपने रिश्तों में किसी तरह की खटास की अटकलों को खारिज करते हुए बुधवार को कहा, "दूर कब थे हम लोग? हम कभी दूर थे ही नहीं।" उन्होंने यह भी कहा कि प्यार मोहब्बत हमेशा बनी रहती है... बनी रहेगी। गहलोत की इस टिप्पणी को कांग्रेस के इन दो दिग्गज नेताओं के रिश्तों पर वर्षों से जमी बर्फ पिघलने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल गहलोत बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर भड़ाना (दौसा) में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। इस अवसर पर संवाददाताओं के सवाल पर उन्होंने यह टिप्पणी की। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई और राजेश पायलट के योगदान से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पार्टी के कई सांसद और विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद थे। भीड़ भरे कार्यक्रम स्थल पर पत्रकारों ने गहलोत से पूछा कि दोनों नेताओं के फिर करीब आने के पीछे क्या संदेश है। गहलोत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "दूर कब थे हम लोग? आपको लगता है ... हम दूर कब थे? कभी दूर थे ही नहीं। प्रेम मोहब्बत हमेशा बनी रहती है। बनी रहेगी।" कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने जब यह टिप्पणी की तो पायलट के साथ–साथ पार्टी के दूसरे नेता भी वहीं थे। राजेश पायलट को याद करते हुए गहलोत ने कहा कि वह और पायलट संसद में साथ–साथ थे और किसानों व गरीबों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आज भी याद की जाती है। गहलोत ने कहा, "आज हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोगों का उत्साह देखिए। युवा भी आए हैं और बुजुर्ग भी। जिन्होंने उनके साथ काम किया है वे भी आए हैं। जिन्होंने उनके बारे में सुना है वे भी आए हैं। यह सभा अपने आप में संदेश देती है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। मैंने उनके साथ काम किया है और उस समय की यादें भी आज ताजा हो गई हैं।" इस अवसर पर सचिन पायलट ने कहा कि उनके पिता ने भारतीय वायुसेना और बाद में राजनीति में रहते हुए देश की सेवा की। उन्होंने कहा, "मुझे उनपर बड़ा फख्र है। उन्होंने फौज और फिर राजनीति में रहते हुए बड़े आयाम स्थापित किए। बड़े पदों पर बैठकर भी इंसान अपना दामन साफ रख सकता है। गरीब परिवार में पैदा होकर भी इंसान ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है।" उन्होंने कहा, "उन्हें हमसे जुदा हुए 25 साल हो गए लेकिन आज भी मुझे लगता है कि वह मेरे साथ ही हैं। उनका काम करने का तरीका और लगन हमारे लिए आदर्श है। मुझे उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से सबक लेगी।" उन्होंने कहा, "मैं गर्व से कह सकता हूं कि पायलट साहब लोगों को जोड़ने वाले नेता थे। उन्होंने लोगों को जोड़ा और दूरियां कम कीं। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से देश की सेवा की। आज हम सब उन्हें याद करते हैं।" प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान सचिन पायलट भी गहलोत के साथ थे। राजेश पायलट की 11 जून 2000 को दौसा में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस समय वह दौसा के सांसद थे। उनकी पुण्यतिथि पर सचिन पायलट की ओर से हर साल दौसा में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सचिन पायलट हाल ही में गहलोत को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने उनके आवास पर गए थे। उल्लेखनीय है कि गहलोत व पायलट में रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में सामान्य नहीं रहे हैं। दरअसल दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में कांग्रेस के सत्ता में आने पर गहलोत और सचिन पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए रस्साकशी शुरू हो गई थी। हालांकि इसमें गहलोत ने बाजी मार ली और वह तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। उस समय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे सचिन को उपमुख्यमंत्री बनाया गया। साल 2020 में पायलट ने कुछ कांग्रेस विधायकों के साथ मिलकर गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इससे राज्य में एक महीने तक सियासी संकट बना रहा जो पार्टी आलाकमान द्वारा पायलट द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। पायलट व 18 अन्य विधायकों के 'विद्रोह' के बाद गहलोत ने सचिन के लिए "गद्दार", "नकारा" और "निकम्मा" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और उन पर राज्य में कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश में भाजपा नेताओं के साथ शामिल होने का आरोप लगाया। इस सियासी संकट के दौरान ही पायलट को उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एक पंक्ति का प्रस्ताव पारित करते हुए पार्टी आलाकमान को राज्य नेतृत्व में बदलाव क बारे में निर्णय करने के लिए अधिकृत किया जाना था। उस समय गहलोत को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में माना जा रहा था। हालांकि, यह बैठक नहीं हो सकी। बल्कि तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर एक समानांतर बैठक हुई जिसमें कई कांग्रेस विधायकों ने पायलट को नया मुख्यमंत्री बनाने के पार्टी आलाकमान के किसी भी संभावित कदम के खिलाफ अपने इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिए। अप्रैल 2023 में पायलट ने तत्कालीन गहलोत सरकार के खिलाफ एक तरह से एक और मोर्चा खोलते हुए पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर उपवास रखा था।

हिमाचल: ऊना में ड्रोन–यूएवी परिचालन के लिए पंजीकरण जरूरी

ऊना (हिमाचल प्रदेश), (भाषा) हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) के परिचालन के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। ऊना के जिलाधिकारी जतिन लाल ने सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में आदेश जारी किये हैं। यहां एक प्रवक्ता ने बताया कि ड्रोन का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति, संगठन, संस्था और सरकारी एजेंसी को आगामी सात दिनों के भीतर संबंधित थाने से अपने ड्रोन परिचालन के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन को खरीदने के सात दिनों के भीतर उसका पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवना होगा। पंजीकरण करवाने के लिए ड्रोन का मॉडल, सीरियल नंबर (अगर कोई हो), उड़ान क्षमता, उपयोग का उद्देश्य (जैसे कृषि, निगरानी, फोटोग्राफी, आपातकालीन सेवाएं आदि), ऑपरेटर का नाम, पता और संपर्क जानकारी तथा रिमोट पायलट लाइसेंस की एक प्रति (यदि लागू हो) प्रदान करना अनिवार्य होगा।

भाजपा नीत केंद्र सरकार के 11 वर्षों के शासन में झारखंड के लोगों का संघर्ष बढ़ा: झामुमो

रांची, (भाषा) सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार के 11 साल के शासन में केवल झारखंड के लोगों का संघर्ष और उनके अनुत्तरित सवालों की फेहरिस्त बढ़ी है। झामुमो ने आरोप लगाया, ''मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को तथाकथित 'उपलब्धियों' को रेखांकित करने के लिए झारखंड भेजा है। लेकिन यहां जमीनी हकीकत जश्न जैसी नहीं है।" ईरानी ने मंगलवार को केंद्र सरकार की कई उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया था कि इस अवधि के दौरान 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। झामुमो प्रवक्ता और केंद्रीय समिति के सदस्य डॉ. तनुज खत्री ने आरोप लगाया कि झारखंड विधानसभा ने सरना धार्मिक संहिता को मान्यता देने की मांग करते हुए आम राय से प्रस्ताव पारित किया, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की है। खत्री ने कहा कि यह न केवल एक प्रशासनिक चूक है, बल्कि आदिवासी समुदायों की पहचान और उनके सम्मान को जानबूझकर नकारना है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में लंबे समय से जारी हिंसा, खास तौर पर महिलाओं के साथ होने वाली क्रूरता ने सरकार की उदासीनता को उजागर किया है। खत्री ने कहा, ''ऐसे गंभीर संवैधानिक संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुप्पी न केवल प्रशासनिक विफलता बल्कि नैतिक दिवालियापन को भी दर्शाती है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के हसदेव में पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के फैसले ने पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों से जुड़े सरकार के असली रुख को बेनकाब कर दिया है। खत्री ने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट), राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) और एसएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पेपर लीक होना आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि यह केवल भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों और प्रयासों के साथ विश्वासघात है।

खत्री ने कहा, ''नोटबंदी को ऐतिहासिक कदम बताया गया, लेकिन इसने छोटे व्यापारियों, श्रमिकों और आम जनता को तबाह कर दिया। 100 से अधिक लोगों की जान चली गई, नौकरियां चली गईं और आखिरकार पुरानी मुद्रा वापस आ गई। इसके बावजूद माफी मांगने के बजाय सरकार अब भी दावा कर रही है कि यह उसकी 'उपलब्धि' है।'' खत्री ने आरोप लगाया कि बिना बातचीत के तीन कृषि कानून (अब रद्द किये जा चुके) लाए गए, जिसके कारण बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन हुआ और 700 से अधिक किसानों की मौत हो गई। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक के पीछे की मंशा पर भी सवाल उठाए और इसे चुनाव से पहले का हथकंडा बताया। उन्होंने कहा, ''सरकार ने बड़ी घोषणा की लेकिन इस पर अमल को वर्ष 2029 तक के लिए टाल दिया जिससे यह महज बयानबाजी साबित हुई।'' खत्री ने आरोप लगाया कि महंगाई ने आम आदमी की क्रय शक्ति को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा, ''दाल, सब्जियां और दूध जैसी बुनियादी जरूरतें तेजी से महंगी होती जा रही हैं, जबकि सरकार तेज आर्थिक विकास का दावा करती रहती है।'' झामुमो ने भाजपा पर विपक्षियों को परेशान करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करने और संसद को चर्चा के बजाय आदेश देकर चलाने का आरोप लगाया।

ओडिशा में भाजपा सरकार का एक साल : मुख्यमंत्री माझी ने 'विकास वाहन' रवाना किया

भुवनेश्वर, (भाषा) ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बृहस्पतिवार को 'विकास वाहन' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन ओडिशा के लोगों को केंद्र और राज्य में भाजपा शासन द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगे। इस अवसर पर भुवनेश्वर के महात्मा गांधी मार्ग पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि 'विकास वाहन यात्रा' एक 10 दिवसीय कार्यक्रम है जो 12 जून से 21 जून तक आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि यह यात्रा ओडिशा के 314 प्रखंडों के सभी 6,794 ग्राम पंचायत मुख्यालयों, पांच नगर निगम क्षेत्रों और 115 शहरी स्थानीय निकायों से गुजरेगी। उन्होंने कहा कि पंचायती राज और पेयजल विभाग द्वारा शुरू किया गया यह अभियान सरकार की विकास योजनाओं की सफलता की कहानियां लोगों तक पहुंचाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं जैसे 'विकसित गांव विकसित ओडिशा','सुभद्रा योजना', 'अंत्योदय गृह योजना', आदिवासी और अनुसूचित जाति कल्याण, युवाओं के लिए कौशल विकास और विभिन्न खेलों को बढ़ावा देना, कृषि के लिए सब्सिडी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम नीति–2020, गोदावरीश मिश्र आदर्श विद्यालय योजना, शिशु वाटिका कार्यक्रम को रेखांकित किया। माझी ने कहा, ''लोगों से कहा जाएगा कि वे योजनाओं का लाभ उठाएं, जिसका उद्देश्य उनका जीवन बेहतर बनाना है।'' पंचायती राज एवं पेयजल मंत्री रवी नारायण नाइक ने कहा कि लोगों को योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए क्योंकि भाजपा सरकार का एकमात्र उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है।

कैंसर के जोखिम का प्रमुख कारण वह नहीं है जो आप सोचते हैं

वैंकूवर, (द कन्वरसेशन) अगर आप लोगों से पूछें कि कैंसर किस वजह से होता है, तो शायद अधिकतर अपने जवाब में धूम्रपान, शराब पीने, सूरज की किरणों और बालों को रंगने वाली डाई जैसी चीजों को गिनाएंगे। लेकिन कैंसर के लिए सबसे प्रमुख जोखिम वाला कारक कुछ और है और वह है उम्र बढ़ना या बुढ़ापा आना (एजिंग)। यह बात सही है, कैंसर से जुड़ा सबसे बड़ा कारक अपरिहार्य है और यह एक ऐसी स्थिति है जिसका हम सभी अनुभव करेंगे। यह क्यों महत्वपूर्ण है? कनाडा और दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती आबादी वृद्ध लोगों की है। 2068 तक, लगभग 29 प्रतिशत कनाडाई 65 वर्ष से अधिक आयु के होंगे। वृद्ध लोगों में कैंसर सबसे आम बीमारियों और कनाडा में सबसे आम बीमारियों में से एक है, इसका मतलब है कि हमें वृद्ध लोगों के लिए सबसे अच्छी कैंसर देखभाल प्रदान करने के बारे में सोचना होगा।

जनसांख्यिकीय बदलाव: तो अब तक हम किस तरह काम कर रहे हैं? जवाब है: बहुत अच्छा नहीं। यह आश्चर्यजनक हो सकता है, लेकिन हमारे पास कैंसर देखभाल में इस जनसांख्यिकीय बदलाव के लिए कुछ नया करने और तैयारी करने का एक शानदार अवसर भी है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लीनिकल ऑन्कोलॉजी के दिशानिर्देश समेत अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देश कहते हैं कि सभी वृद्ध लोगों को अपने कैंसर उपचार के बारे में निर्णय लेने से पहले बुढ़ापे का (जरिएट्रिक) मूल्यांकन करवाना चाहिए। किसी वृद्ध के लिए जेरियाट्रिसियन से परामर्श ऑन्कोलॉजिस्ट और वृद्ध को जानकारी के साथ कैंसर उपचार के बारे में बातचीत करने की अनुमति देता है। उपचार उनके संज्ञान, उनके कार्य, उनकी मौजूदा बीमारियों (जो कि अधिकांश वृद्ध लोगों में कैंसर का निदान होने पर होती हैं) और शेष जीवन के वर्षों को कैसे प्रभावित कर सकता है। महत्वपूर्ण रूप से,जेरियाट्रिसियन अपने मूल्यांकन को इस बात पर केंद्रित करते हैं कि रोगियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यह दृष्टिकोण वृद्ध लोगों की इच्छाओं और उनकी समर्थन प्रणाली के इर्द–गिर्द कैंसर के बारे में कोई भी निर्णय लेने में सहायक होता है। जब कैंसर का निदान किया जाता है, तो वयस्कों को कई परीक्षणों और उपायों से गुजरना पड़ता है, लेकिन साक्ष्य इस बात का समर्थन करते हैं कि उन समस्याओं की पहचान करने के लिए जेरियाट्रिक मूल्यांकन जितना सटीक नहीं हैं जो सतह के नीचे यानी अप्रकट हो सकती हैं।

कनाडा में देखभाल: कनाडा में, वर्तमान में केवल मुट्ठी भर विशेष जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी क्लीनिक हैं। सबसे पुराना क्लिनिक मॉन्ट्रियल में यहूदी जनरल अस्पताल में है, इसके बाद टोरंटो में प्रिंसेस मार्गरेट कैंसर सेंटर में ओल्डर एडल्ट विद कैंसर क्लीनिक है, जिसका नेतृत्व इस आलेख के लेखकों में शामिल शब्बीर अलीभाई करते हैं। शोधकर्ताओं के रूप में, हम ओंटारियो और अल्बर्टा के क्लीनिकों के संपर्क में हैं, जिन्होंने हमें बताया है कि उनके पास जेरिएट्रिक ऑन्कोलॉजी सेवाएं विकसित की जा रही हैं, इसलिए हमें जल्द ही नए कार्यक्रम देखने की उम्मीद है। ये क्लीनिक सिर्फ मरीजों के लिए ही अच्छे नहीं हैं। वास्तव में, शब्बीर अलीभाई के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में इन क्लीनिकों में देखे जाने वाले प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति के खर्च में लगभग 7,000 डॉलर की बचत होने का पता चला है। अगर हम इसे हर साल कनाडा में कैंसर से ग्रस्त पाए जाने वाले वृद्ध व्यक्तियों की संख्या से मिलाते हैं, तो यह हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक बड़ी लागत बचत को दर्शाता है। ब्रिटिश कोलंबिया में, वर्तमान में कैंसर से पीड़ित वृद्ध व्यक्तियों के लिए कोई विशेष सेवाएं नहीं हैं। पिछले पांच वर्षों में, क्रिस्टन हासे, जो लेख की लेखिका भी हैं – सहकर्मियों के साथ यह समझने के लिए काम कर रही हैं कि क्या इन सेवाओं की जरूरत है और वे बी.सी. में कैंसर से पीड़ित वृद्ध व्यक्तियों की कैसे मदद कर सकती हैं। अनुसंधान दल ने कैंसर का इलाज करवा रहे वृद्ध व्यक्तियों से बात की, जिन्हें कभी–कभी कैंसर के इलाज के लिए दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। शोध दल ने स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों से भी बात की जिनमें कैंसर रोग विशेषज्ञ, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे।

देखभाल में बाधाएं: तो अब हम कहां हैं और हमारे पास पूरे कनाडा में सेवाएं क्यों नहीं हैं? लागत भी स्पष्ट रूप से किसी भी स्वास्थ्य देखभाल सेवा के लिए एक बाधा है। ऑन्कोलॉजी में हमारी नैदानिक देखभाल मॉडल तीन दशकों से ज्यादा समय से बरकरार है। यह मुख्य रूप से एकल चिकित्सक द्वारा संचालित मॉडल है। हालांकि कैंसर के लिए आधुनिक उपचार बहुत तेजी से उभरे हैं और क्लीनिक में अपनाए गए हैं, लेकिन देखभाल के मॉडल को बदलना बहुत कठिन है, खासकर रणनीतिक रूप से।

(क्रिस्टन हासे, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया और शब्बीर अलीभाई)

श्रीलंका में इस वर्ष पांच जून तक आये पर्यटकों में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक

कोलंबो, (भाषा) श्रीलंका में इस वर्ष के पांच जून तक आये कुल पर्यटकों में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक रही। यह जानकारी श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण के बुधवार को जारी नवीनतम आंकड़े से मिली। श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण (एसएलटीडीए) के आंकड़े के अनुसार, अप्रैल के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अप्रैल 2025 से श्रीलंका 10,51,096 पर्यटक आए जिनमें 2,10,074 पर्यटक भारत से, 1,10,818 रूस से और 98,158 ब्रिटेन से आए। समाचार पोर्टल अदादेराना ने कहा कि इस वर्ष मई में कुल 1,32,919 विदेशी नागरिकों ने देश की यात्रा की, जो मई 2024 के आंकड़े की तुलना में 18.5 प्रतिशत की वृद्धि है। आंकड़े के अनुसार जून के पहले पांच दिनों में आने वाले पर्यटकों की संख्या 21,293 है और इसमें भी भारत 6,014 पर्यटकों के साथ सूची में शीर्ष पर रहा, जो 28.2 प्रतिशत है।

भारत, यूरोपीय संघ के एफटीए में गैर–शुल्क बाधाएं भी शामिल हों: स्वीडिश मंत्री

स्टॉकहोम, (भाषा) यूरोपीय संघ के सदस्य देश स्वीडन ने बुधवार को कहा कि भारत के साथ एक ऐसे 'मुक्त व्यापार समझौते' (एफटीए) की दिशा में काम करना चाहिए जो शुल्क एवं गैर–शुल्क बाधाओं को संबोधित करता हो। स्वीडन के अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग एवं विदेशी व्यापार मंत्री बेंजामिन दोउसा ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) दोनों ही क्षेत्र वर्तमान में 'थोड़ा अधिक विनियमित' हैं लिहाजा शुल्क एवं गैर–शुल्क बाधाएं माल के सुचारू सीमापार प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोउसा ने भारत और स्वीडन के व्यापारिक दिग्गजों को संबोधित करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ और भारत को प्रस्तावित एफटीए के लागू होने से काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा, ''यूरोपीय संघ और भारत दोनों के लिए सबसे अच्छा एक ऐसा एफटीए होगा जो न केवल शुल्क के बारे में हो बल्कि उसमें गैर–शुल्क बाधाएं भी शामिल हों। मुझे लगता है कि यूरोपीय संघ और भारत दोनों ही क्षेत्रों में हम अभी थोड़े अधिक विनियमित हैं।'' उन्होंने कहा कि अगर भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करना जारी रख सकता है तो वह एक विश्वसनीय विनिर्माण केंद्र बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वीडन भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस अवसर पर दोउसा ने कहा कि स्वीडन की दिग्गज फर्नीचर विक्रेता कंपनी आइकिया भारत से अपनी सोर्सिंग को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की योजना बना रही है। आइकिया फिलहाल भारत से कपड़ा, प्लास्टिक और धातु जैसे उत्पाद खरीदती है और उसकी भविष्य में और भी उत्पाद जोड़ने की मंशा है। फिलहाल यूरोप आइकिया के उत्पादों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस कार्यक्रम में कहा कि भारत और 27 यूरोपीय देशों के समूह के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते में गैर–शुल्क बाधाएं भी चर्चा का हिस्सा हैं। वह स्वीडन के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा के लिए दो–दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। गोयल ने कहा कि भारत में निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिए सरकार बुनियादी ढांचे में सालाना करीब 125 अरब डॉलर का निवेश करने जैसे कई कदम उठा रही है।

भारत और ब्रिटेन ने उत्तरी अरब सागर में किया नौसैन्य अभ्यास

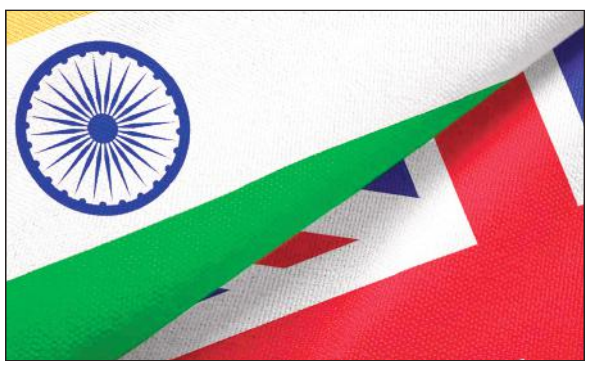

नयी दिल्ली, (भाषा) भारतीय नौसेना की इकाइयों और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के 'कैरियर स्ट्राइक ग्रुप' ने उत्तरी अरब सागर में 'पैसेज' अभ्यास (पासेक्स) में हिस्सा लिया जो समुद्री सुरक्षा और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आधिकारिक प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि यह अभ्यास नौ और 10 जून को आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट 'आईएनएस तबर', पनडुब्बी और पी8आई विमान ने भाग लिया। प्रवक्ता ने कहा, ''यह अभ्यास 'यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप' के साथ आयोजित किया गया, जिसमें 'एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स' और 'एचएमएस रिचमंड' पोत शामिल थे।'' बहुआयामी नौसैन्य अभ्यास में एकीकृत हेलीकॉप्टरों का नियंत्रण, सामरिक युद्ध कौशल, समन्वित पनडुब्बी विध्वंसक अभियान और अधिकारियों के बीच पेशेवर आदान–प्रदान शामिल था। प्रवक्ता ने कहा कि यह संयुक्त अभ्यास भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच बढ़ते सहयोग तथा समुद्री सुरक्षा और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

टाटा पावर–डीडीएल ने द्विजदास बसाक को सीईओ नियुक्त किया

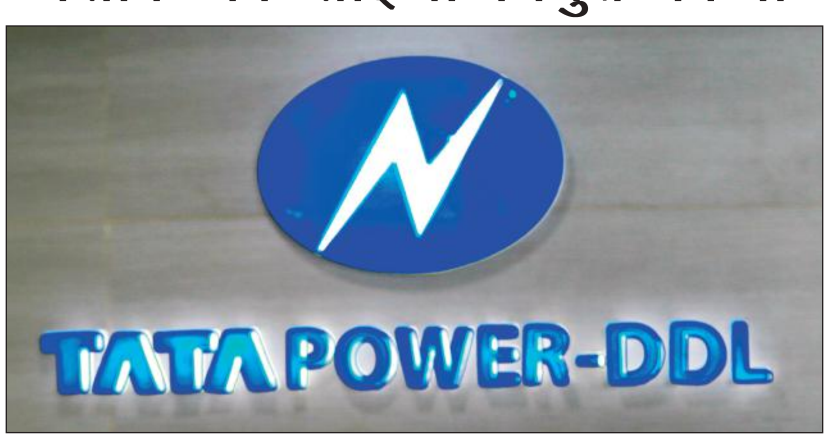

नयी दिल्ली, (भाषा) बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर–डीडीएल ने द्विजदास बसाक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की मंगलवार को घोषणा की। कंपनी के बयान के अनुसार, बसाक की नियुक्ति नौ जून 2025 से प्रभावी हो गई। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक डॉ प्रवीर सिन्हा ने नियुक्ति पर कहा, '' मैं टाटा पावर–डीडीएल के नए सीईओ के रूप में द्विजदास बसाक का स्वागत करता हूं। बिजली वितरण क्षेत्र में उनका शानदार रिकॉर्ड है...मुझे विश्वास है कि वह टाटा पावर–डीडीएल को परिवर्तनकारी विकास के अगले चरण में ले जाएंगे।

नवोन्मेष तथा परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देंगे और ग्राहक केंद्रितता को नई ऊंचाइयों पर ले पहुंचाएंगे।'' टाटा पावर–डीडीएल से पहले बसाक टीपी नॉर्दर्न ओडिशा डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीएनओडीएल) के सीईओ और ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस प्रमुख रह चुके हैं। बसाक ने कहा, '' मैं बतौर सीईओ टाटा पावर–डीडीएल से जुड़कर बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह संगठन बिजली वितरण क्षेत्र में एक मानक के रूप में खड़ा है। मुझे विश्वास है कि हम अपने ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करते हुए इस क्षेत्र में प्रदर्शन के नए मानक स्थापित करेंगे।'' टाटा पावर–डीडीएल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और टाटा पावर के बीच संयुक्त उद्यम है। कंपनी उत्तरी दिल्ली की करीब 90 लाख की आबादी को बिजली आपूर्ति करती है।

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए 2028 से और भारतीयों को मिलेगी रोड्स छात्रवृत्ति

नयी दिल्ली, (भाषा) ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले रोड्स स्कॉलरशिप ट्रस्ट ने 2028 से भारतीयों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या को देश की जनसंख्या के अनुरूप बढ़ाने की योजना बनाई है। यह जानकारी ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सर रिचर्ड ट्रेनर ने दी। अगले साल से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदनों की घोषणा से पहले, भारत आए ट्रेनर ने 'पीटीआई–भाषा' को दिए साक्षात्कार में बताया कि वर्तमान में भारतीय अभ्यर्थियों को सालाना छह छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।ट्रेनर ने कहा, ''अब प्राथमिकता उन स्थानों के लिए कुछ अतिरिक्त छात्रवृत्तियां प्रदान करने की है, जहां जनसंख्या के अनुपात में विद्वानों की संख्या अधिक हो सकती है और भारत उन देशों में से एक है। इसलिए, हमारे पास भारत के लिए प्रति वर्ष छह छात्रवृत्तियां हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इस देश में डेढ़ अरब लोग हैं, इसलिए अधिक छात्रवृत्तियां होनी चाहिए।'' रोड्स हाउस के अंतरिम 'वॉर्डन' ने कहा, ''हम अतिरिक्त छात्रवृत्तियों के लिए धन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की फीस का भुगतान करने तथा छात्रों के जीवन–यापन के व्यय का भुगतान करने के लिए निधि में धन की आवश्यकता है।'' छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने के लिए चीन और अफ्रीका जैसे अन्य देश भी प्राथमिकता में हैं। वर्तमान में चीन से चार और अफ्रीका से 21 अभ्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। ट्रेनर ने कहा, ''हम छात्रवृत्ति योजना की 125वीं वर्षगांठ, जो कि 2028 है, तक इन तीनों क्षेत्रों में कुछ अतिरिक्त विद्वानों को शामिल करना चाहेंगे। हम अभी से लेकर 125वीं वर्षगांठ तक धन जुटाने पर बड़ा जोर देने जा रहे हैं।'' ट्रेनर स्वयं 1970 में रोड्स छात्रवृत्ति के लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर रोड्स छात्रवृत्ति से अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताते हैं। रोड्स छात्रवृत्ति उन प्रतिभाशाली छात्रों को दी जाती है, जिन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दो से तीन साल की पढ़ाई करनी होती है। 18–23 वर्ष (विशेष परिस्थितियों में 27 वर्ष तक) के छात्र आवेदन करने के पात्र हैं। रोड्स छात्रवृत्ति विश्व की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुरानी स्नातक पाठ्यक्रम के लिए दी जाने वाल छात्रवृत्तियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1903 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में की गई थी। अगले साल के शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया तीन जून को शुरू हुई और अभ्यर्थी 23 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।

सेबी ने एनएसई को–लोकेशन मामले में ओपीजी सिक्योरिटीज, अन्य को 5.35 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा

नयी दिल्ली, (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने शेयर ब्रोकर ओपीजी सिक्योरिटीज और उसके निदेशकों को नोटिस भेजकर एनएसई को–लोकेशन मामले में शेयर बाजार के सर्वर तक अनुचित पहुंच के मामले में 5.35 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में नाकाम रहने पर इनकी संपत्ति के साथ बैंक खातों को भी कुर्क करने की चेतावनी दी है। बाजार नियामक ने अप्रैल, 2025 में लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में इन संस्थाओं के विफल रहने के बाद मांग नोटिस जारी किया है। सोमवार को जारी तीन अलग–अलग नोटिसों में नियामक ने ओपीजी सिक्योरिटीज और उसके निदेशकों– संजय गुप्ता, संगीता गुप्ता एवं ओम प्रकाश गुप्ता को 15 दिनों के भीतर कुल 5.35 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके पहले अप्रैल में पारित अपने आदेश में सेबी ने अनुचित कारोबारी तरीके अपनाने पर ओपीजी सिक्योरिटीज और उसके निदेशकों पर संयुक्त रूप से पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

जापान की राजकुमारी काको ब्राजील में पदक से सम्मानित की गईं

साओ पाउलो (ब्राजील), (एपी) जापान की राजकुमारी 'काको ऑफ अकिशिनो' को ब्राजील के साओ पाउलो के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। राजकुमारी काको नैशिन्नो वर्तमान में दक्षिण अमेरिकी देश की 11 दिवसीय यात्रा पर हैं। जापान और ब्राजील के बीच राजनयिक संबंधों की 130वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजकुमारी काको यह यात्रा कर रही है। जापान के सम्राट नारुहितो की भतीजी और युवराज फूमिहितो यानि अकिशिनो की छोटी बेटी राजकुमारी काको बृहस्पतिवार को साओ पाउलो पहुंचीं। उन्होंने शुक्रवार को जापानी समुदाय के सदस्यों के साथ मुलाकात की और राज्य सरकार के महल में गवर्नर टार्सिसियो डी फ्रीटास के साथ रात्रिभोज किया। उन्हें एक समारोह में 'ऑर्डर ऑफ द इपिरंगा' से सम्मानित किया गया। राजकुमारी काको रियो डी जेनेरियो और राजधानी ब्रासीलिया सहित सात अन्य शहरों की यात्रा करेंगी, जहां वह राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा से संभवतः मुलाकात करेंगी। सम्राट नारुहितो को कोई पुत्र नहीं है, जिसके कारण उनके भाई अकिशिनो सम्राट बनने के पहले उत्तराधिकारी हैं। जापान में महिलाओं को सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं है।

मेरिकी पिज्जा ब्रांड लिटिल सीजर्स भारत में करेगा प्रवेश

नयी दिल्ली, (भाषा) अमेरिका स्थित दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पिज्जा श्रृंखला लिटिल सीजर्स भारतीय बाजार में प्रवेश कर रही है। सबसे तेजी से बढ़ते त्वरित सेवा रेस्तरां बाजारों में से एक भारत, लिटिल सीजर्स के लिए 30वां बाजार होगा। लिटिल सीजर्स दुनिया की सबसे बड़ी पारिवारिक स्वामित्व वाली पिज्जा श्रृंखला है, जिसके लिए इसने अपने फ्रैंचाइजी साझेदार के रूप में हार्नेसिंग हार्वेस्ट को शामिल किया है। कंपनी के एक बयान के अनुसार, उसकी इस महीने दिल्ली–एनसीआर में अपना पहला रेस्तरां खोलने की योजना है। इसके बाद अन्य स्थानों पर भी इसकी योजना है। लिटिल सीज़र्स पिज़्ज़ा की अध्यक्ष (वैश्विक खुदरा) पॉला विसिंग ने कहा, "भारत में पेश होना लिटिल सीज़र्स के लिए एक रोमांचक मील का पत्थर है, क्योंकि हम अपने 30वें देश में विस्तार कर रहे हैं। अपने स्वादिष्ट पिज़्ज़ा और बेजोड़ मूल्य के साथ, हम एक अनूठा मेनू (खान–पान की सूची) पेश करने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि यह भारत को आकर्षित करेगा।"

सरकार ने आरबीआई के डीजी टी रबी शंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य बनाया

नयी दिल्ली, (भाषा) वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य बनाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि एक पूर्णकालिक सदस्य पूर्व वित्त सचिव अजय नारायण झा के व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देने के चलते यह नियुक्ति की गई। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''राष्ट्रपति ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया है।'' शंकर कार्यभार संभालने की तारीख से लेकर आयोग के अपनी रिपोर्ट सौंपने तक या 31 अक्टूबर, 2025 तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बने रहेंगे। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाले इस आयोग में चार सदस्य हैं और सचिव ऋत्विक पांडेय, दो संयुक्त सचिव और एक आर्थिक सलाहकार उसकी सहायता करते हैं।

Piyush Goyal concludes successful visit to Switzerland, reinforces momentum for India–Switzerland partnership under EFTA TEPA

New Delhi, Focus News: Union Commerce and Industry Minister, Shri Piyush Goyal, concluded a successful two-day official visit to Switzerland from June 9–10, 2025, and commenced his official engagements in Sweden today. The Switzerland leg of the visit focused on advancing India–Switzerland economic cooperation and operationalising the Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) signed earlier this year between India and the European Free Trade Association (EFTA). During the visit, Shri Goyal held productive meetings with top leadership from the Swiss government and industry, aimed at reinforcing strategic synergies and unlocking new avenues for trade, investment, and innovation-led growth. He met with Federal Councillor Guy Parmelin, Head of the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research (EAER), and State Secretary Helene Budliger Artieda to chart a forward-looking roadmap for TEPA implementation. Discussions focused on regulatory cooperation, skills development, innovation partnerships, and mechanisms to facilitate faster investment decision-making. The Minister engaged extensively with Swiss industry leaders across sectors including biotech and pharma, healthcare, precision engineering, defence, and emerging technologies. In his sectoral roundtables and bilateral meetings, Shri Goyal highlighted India's growing economic strength, policy stability, and the government's commitment to creating a conducive and facilitative ecosystem for global investors. Companies welcomed India's ambitious infrastructure expansion, technology-driven governance, and expanding domestic consumption base, viewing India as both a growth destination and a global manufacturing hub.

A major highlight of the visit was Shri Goyal's participation in the 18th Swissmem Industry Day held in Zurich on June 10. He was warmly received by delegates and senior members of Swissmem, the apex association representing Switzerland's Mechanical, Electrical, and Metal (MEM) industries. The event, attended by over 1,000 participants from across Europe, featured discussions on industrial innovation, sustainability, and global competitiveness—areas where India and Switzerland are seen as natural partners. In his keynote address, Shri Goyal invited Swiss companies, including SMEs and deep-tech innovators, to scale up investments in India by leveraging the new trade architecture offered by TEPA. He spoke about India's demographic dividend, globally recognised engineering talent, and robust supply chains, encouraging Swiss industry to anchor R&D, establish local manufacturing bases, and co-create technologies for the Global South. Referring to TEPA as a "Trust and Efficiency Partnership Agreement," he emphasized the spirit of complementarity between India and Switzerland and the unique value they can jointly offer to global markets.

An immediate standout outcome of this was the swift resolution of a facilitation request by Endress+Hauser, a global process automation company with a growing presence in India. During discussions, the company raised the issue of land parcel availability near their existing facility in Maharashtra.. Within hours, the matter was resolved through coordinated efforts by Shri Goyal and Indian authorities, demonstrating the Government of India's commitment to fast-tracking investor concerns and ensuring a seamless business environment. The resolution was hailed by industry members as a model for responsive governance. Goyal also held several one-on-one meetings with Swiss companies expressing interest in India. These included discussions on expansion strategies, setting up new R&D centres, deepening localisation, talent development, and building robust MSME linkages. Many companies conveyed their intent to use India not only as a domestic market but also as a global manufacturing and export base. Interest was particularly strong in sectors such as advanced manufacturing, industrial automation, clean technology, and healthcare innovation. Throughout his engagements, the Minister was accompanied by a high-level delegation from Indian industry associations—ASSOCHAM, CII, and FICCI—further underscoring India's whole-of-government and whole-of-industry approach to economic diplomacy. In his meeting with members of the Switzerland Chapter of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Shri Goyal appreciated their contributions to building India's global reputation for financial excellence and professional standards. The visit concluded on a note of shared optimism and mutual commitment to scale up the India–Switzerland partnership. Swiss stakeholders across sectors reaffirmed their confidence in India's rise as a global economic powerhouse and welcomed the Government of India's collaborative and reform-oriented approach.

India Hosts ITU FG-AINN Meeting to Advance AI-Native Telecom Networks

New Delhi, Focus News: As part of the ongoing efforts to explore the integration of artificial intelligence (AI) native in telecommunication network, the third meeting of the International Telecommunication Union (ITU-T) Focus Group on Artificial Intelligence Native for Telecommunication Networks (FG-AINN) was inaugurated in New Delhi today. This ITU event is being organized by the Telecommunication Engineering Centre (TEC), technical arm of Department of Telecommunications (DoT). Addressing at the inaugural session of the three-day event, Mr. Sanjeev Bidwai, Member (T), DCC, emphasized that AI-Native Networks (AI-NN) represent a fundamental shift in telecom design. He noted the growing role of AI in Third Generation Partnership Project (3GPP) standards, enabling intelligent orchestration across domains. Mr. Bidwai highlighted India's ongoing efforts in this space, including national initiatives like 'Bharat Gen'-India's first indigenously developed, government-funded, AI-based Multimodal Large Language Model (LLM) for Indian languages, as well as other projects led by IITs and CDOT in AI-based network automation and digital twins. He also emphasized the importance of deploying AI in an ethical, inclusive, and secure manner, highlighting the need for explainability, digital sovereignty, and the evolution of regulatory frameworks. In a video address, Mr. Seizo Onoe, Director of the Telecommunication Standardization Bureau, ITU, underscored the potential of AI-native networks to deliver next-generation performance through intelligent automation, self-management, and real-time optimization.

Ms. Atsuo Okuda, ITU Regional Director for Asia-Pacific, highlighted the region's pivotal role as a digital innovation hub, emphasizing that AI-native networks are essential to building smart, secure, and responsive communication systems. She drew attention to the need for collaborative frameworks to bridge the digital divide and power emerging use cases in smart cities, healthcare, and education. During the event, India sought support of ITU members for its bid to host the ITU Plenipotentiary Conference 2030 (PP-30), continued membership in the forthcoming ITU Council (2027-2031) and for Indian Nominee, Ms. M. Revathi, as the first woman and first Regional candidate for Director of the ITU Radiocommunication Bureau (2027–30). The event witnessed participation of Mr. Niraj Verma, Administrator (DBN), Mr. Rudra Narayan Palai, Member (Designate), DoT, Mr. Deb Kumar Chakrabarty, Member (Designate), DoT, Mr. Shubhendu Tiwari, Advisor (Technology), Dr. Rajkumar Upadhyay, CEO, C-DOT, Ms. Tripti Saxena, Senior DDG, TEC and other senior officers of DoT, academicians, technologists, and industry representatives from India and abroad. This event marks a significant milestone in shaping the future of AI-native telecommunication networks, with the potential to revolutionize the global communications landscape. As AI continues to evolve, the work done by the Focus Group will be instrumental in laying the groundwork for more intelligent, adaptive, and efficient networks.

Established by ITU-T Study Group 13 in July 2024, the Focus Group on AI-Native for Telecommunication Networks (FG-AINN) aims at exploring and defining the fundamental changes needed in network architecture to fully harness the potential of AI. The group's goal is to understand the necessary changes in design to fully leverage AI technologies, with an emphasis on the unique challenges and opportunities AI-native networks bring to global communications. The Focus Group is working to redefine telecom networks by embedding Artificial Intelligence at their core. This shift will lead to self-optimizing, resilient networks capable of delivering seamless connectivity, fewer call drops, faster mobile data, and real-time adaptability—benefiting users in cities and remote regions alike. By exploring next-generation applications like smart public services, connected transport, and disaster-aware communication systems, the group is laying the foundation for networks that are not only technically advanced but deeply responsive to public needs.

The sessions at the FG-AINN Meeting & Build-a-Thon (June 11–13, 2025) will cover a wide range of cutting-edge topics focused on the application of Artificial Intelligence and Machine Learning in future communication networks. Key themes include federated learning for telecom, AI/ML models for next-gen wireless systems, AI in 6G use cases, autonomous AI agents, and facial recognition-based SIM verification. In addition to expert talks, the event features technical review sessions, interactive discussions, and collaborative Build-a-Thon activities aimed at developing practical AI-driven solutions. The expected outcome is to strengthen international cooperation, advance AI-native network research, and shape future standards in intelligent telecom systems. The FG-AINN Build-a-thon 2025, a crowdsourced coding event is set for June 13, 2025. This initiative will bring together experts from academia, industry, and startups to co-create practical demonstrations of AI-native concepts through interactive mentoring and collaborative sessions.

11 Years of Modi Government: Labour Ministry Drives Transformation in Social Security and Welfare

New Delhi, Focus News: As the Government of India marks 11 years of inclusive and reform-driven governance under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry of Labour and Employment highlights its key achievements in labour welfare, social security, and public healthcare. Three premier institutions in Hyderabad exemplify this transformation. The EPFO Regional Office, Barkatpura, has set new standards in service delivery through digital innovations, speedy claim settlements, and effective grievance redressal. With over 27 lakh accounts managed and 98% of Pension on Higher Wages claims implemented, it stands as a national model of efficiency. At Sanath Nagar, the ESIC Medical College and Super Specialty Hospital has emerged as a leader in public healthcare and medical education. Equipped with over 1,000 beds and advanced diagnostics, the campus serves more than 72 lakh beneficiaries with IT-enabled, patient-centric services. Meanwhile, the Directorate General of Labour Welfare (DGLW) continues to uplift over 50 lakh unorganised workers through educational scholarships, healthcare assistance, and social protection, particularly in the Beedi, Cine, and mining sectors. To provide an in-depth, ground-level understanding of these success stories, the Ministry is organising a Press Tour to Hyderabad from 11th – 14th June 2025. Journalists will have the opportunity to interact directly with officials, beneficiaries, and frontline service providers. Through guided walkthroughs, live demonstrations, and presentations, media representatives will witness how 11 years of focused governance have resulted in tangible, people-centric outcomes in the labour sector.

ICG Intensifies Operations as Burning Container Vessel Drifts Off Kerala Coast

New Delhi, Focus News: The Indian Coast Guard (ICG) on June 11, 2025, winched five salvage team members and an aircrew diver onto the burning Singaporean-container vessel MV Wan Hai 503 to facilitate towing operations. The vessel, which caught fire off the Kerala coast on June 09, 2025, continues to drift south-east within India's Exclusive Economic Zone (EEZ), approximately 42 nautical miles from Beypore, Kerala. The vessel is carrying 1.2 lakh metric tons of fuel and hundreds of containers, including hazardous cargo, posing a serious risk to the marine environment and regional shipping routes. Intensive firefighting efforts by ICG have significantly reduced visible flames, with only smoke now seen across the cargo holds and bays. However, the fire remains active in the inner decks and near fuel tanks. Five ICG ships, two Dornier aircraft, and a helicopter are engaged in the ongoing firefighting mission, supported by two vessels from the Directorate General of Shipping. A salvage team appointed by the ship's owners is working in coordination with ICG, and the Indian Air Force has been requested for additional aerial support. With the fire yet to be fully extinguished, efforts to establish a towline and pull the vessel away from the coast are underway to prevent a potential ecological disaster. The situation remains critical and is being monitored continuously.

Centre reduces Basic Custom duty (BCD) on major imported Crude edible Oils from 20% to 10%

New Delhi, Focus News: Centre has reduced the Basic Customs Duty (BCD) on crude edible oils namely crude sunflower, soybean, and palm oils has been reduced from 20% to 10% resulting in the import duty differential between crude and refined edible oils from 8.75% to 19.25%. This adjustment aims to address the escalating edible oil prices resulting from the September 2024 duty hike and concurrent increases in international market prices. An advisory has been issued to edible oil associations and industry stakeholders to ensure that the full benefit of the reduced duty is passed on to consumers. 19.25% duty differential between crude and refined oils helps to encourage domestic refining capacity utilization and reduce imports of refined oils. Import duty on edible oils is one of the important factors that impacted landed cost of edible oils and thereby domestic prices. By lowering the import duty on crude oils, the government aims to reduce the landed cost and retail prices of edible oils, providing relief to consumers and helping to cool overall inflation. The reduced duty will also encourage domestic refining and maintain fair compensation for farmers. The revised duty structure will discourage the import of refined Palmolein and redirect demand towards Crude Edible Oils Especially Crude Palm Oil, thereby strengthening and revitalizing the domestic refining sector. This significant policy intervention not only ensures a level playing field for domestic refiners but also contributes to the stabilization of edible oil prices for Indian consumers. A meeting with leading Edible Oil Industry Associations and industry was held under the Chairmanship of Secretary, Department of Food and Public Distribution, Government of India, and advisory was issued to them to pass on the benefits from this duty reduction on to consumers. Industry stakeholders are expected to adjust the Price to Distributors (PTD) and the Maximum Retail Price (MRP) in accordance with the lower landed costs with immediate effect. The Associations have been requested to advise their members to implement immediate price reductions and share the updated brand-wise MRP sheets with the Department on a weekly basis. DFPD shared the format with edible oil industry for sharing the reduced MRP and PTD data. The timely transmission of this benefit to the supply chain is imperative to ensure that consumers experience a corresponding decrease in retail prices. This decision comes after a detailed review of the sharp rise in edible oil prices following last year's duty hike. The increase led to significant inflationary pressure on consumers, with retail edible oil prices soaring and contributing to rising food inflation.

15-Day 'Viksit Krishi Sankalp Abhiyan' Successfully Reaches Its Final Phase

New Delhi, Focus News: As part of the ongoing Viksit Krishi Sankalp Abhiyan, Union Minister of Agriculture and Farmers' Welfare, Shri Shivraj Singh Chouhan, visited Tigipur village on the outskirts of Delhi. He was accompanied by Dr. M. L. Jat, Secretary (DARE) and Director General (ICAR), along with other senior officials and agricultural scientists. This visit marked a significant initiative aimed at understanding farmers' concerns, fostering direct engagement between farmers and scientists, and accelerating the adoption of modern agricultural technologies. Chouhan began the visit by participating in a Kisan Chaupal, where he interacted with farmers on key topics including seed production, polyhouse farming, strawberry cultivation, and the growing of other high-value crops. Commending the innovative approaches adopted by several farmers, he noted that such progressive individuals are at the forefront of transforming Indian agriculture. The Minister also witnessed a live demonstration of drone technology, showcasing advanced techniques for spraying pesticides and nutrients. He spoke with the scientists regarding the cost-efficiency, scalability, and field-level application of these technologies. Later, he conducted a walk-through of a local nursery, interacting further with farmers and gaining insights into their practices. Addressing the gathering, Shri Chouhan stated that the agricultural research will no longer remain confined to closed rooms. It will take place in the fields, in close collaboration with farmers. The feedback collected from villages by scientists will form the bedrock of future agricultural policy."

He said that in the past 15 days alone, 2,170 ICAR teams have engaged with the farmers nationwide, spreading awareness about research and new technologies. Based on this feedback, several challenges faced by farmers have already been addressed, with ongoing efforts focused on more comprehensive solutions. Expressing concern over declining soil fertility, he urged farmers to get the soil tested and select crops based on the Soil Health Card. This is the foundation of sustainable agriculture, he added" Highlighting the government's priorities, Shri Chouhan emphasized a renewed focus on crop diversification, market-oriented farming, and horticulture-based models. He accentuated that areas like Delhi, with their strong market linkages, hold great potential to become horticulture hubs. **He further stressed:** "In today's competitive environment, farming cannot thrive without technology. Whether in cultivation or marketing, farmers must adopt technological solutions. The Central Government is fully committed to supporting them at every stage." Chouhan also acknowledged that Delhi's farmers had long remained outside the ambit of several central agricultural schemes, but assured that this situation is set to change.

Efforts of Modi Government Pave Way for Historic Expansion in Social Protection Coverage in India in Last 11 years

New Delhi, Focus News: Guided by the vision of Prime Minister Shri Narendra Modi of achieving 'Sabka Saath, Sabka Vikas', India has achieved a historic milestone in the realm of social protection coverage, recording one of the most significant expansions globally. According to the latest data from the International Labour Organization's (ILO) ILOSTAT database, India's social security coverage has increased from 19% in 2015 to 64.3% in 2025, an unprecedented 45 percentage point surge over the past decade. While holding a bilateral discussion with the Director General, ILO, Mr. Gilbert F. Houngbo on the sidelines of the International Labour Conference (ILC), Union Minister of Labour & Employment and Youth Affairs & Sports, Dr. Mansukh Mandaviya highlighted the pro-poor and labour welfare schemes undertaken by the Modi Government over the past 11 years. Union Minister also apprised DG ILO about the national-level Social Protection Data Pooling Exercise that has been carried out by the Government in collaboration with the International Labour Organisation. Recognising these efforts, ILO acknowledged India's achievement and officially published on its dashboard that 64.3% of India's population, i.e. over 94 crore people, are now covered under at least one social protection benefit. In 2015, this figure was just 19%. In terms of beneficiary count, India now ranks second in the world, providing social protection to around 94 crore citizens. DG ILO praised India's focused welfare policies for the poor and labour class under Prime Minister Narendra Modi's leadership.

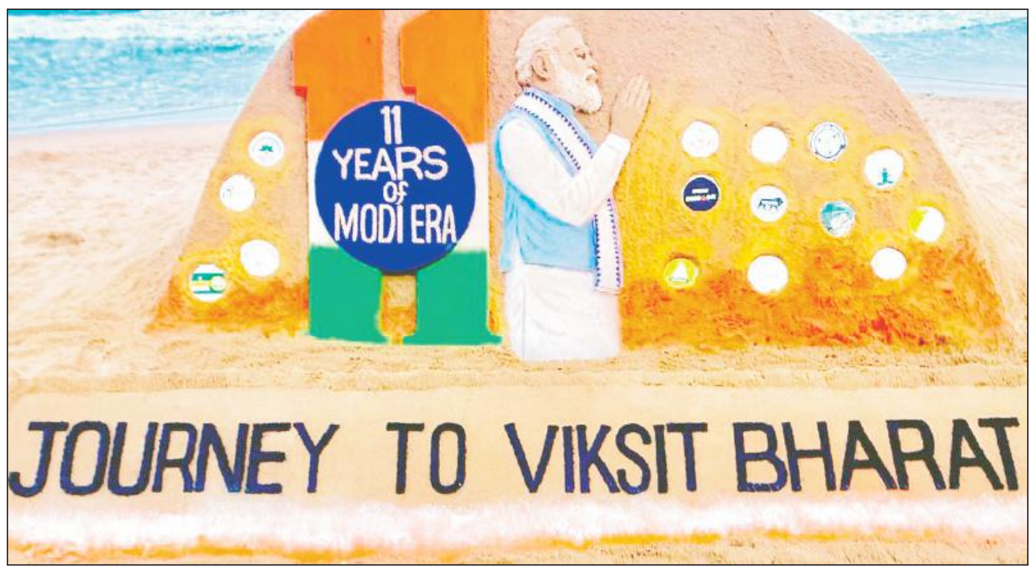

ILO's Criteria for Scheme Consideration for each country include that the scheme should be legislatively backed, in cash and be active, and verified time series data of last three years has to be provided. Speaking from Geneva, Dr. Mandaviya said, "This remarkable achievement stands as a testament to the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and the relentless efforts of the Government in building an inclusive and rights-based social protection ecosystem. The increase marks the fastest expansion in social protection coverage worldwide, reflecting the Government's unwavering commitment to "Antyodaya" i.e., empowering the last mile and fulfilling the promise of leaving no one behind". It is important to note that the present figure reflects only Phase I of the data pooling exercise. This phase focused on beneficiary data of Central sector schemes and women-centric schemes in selected 8 States. With Phase II and further consolidation underway, it is expected that India's total social protection coverage will soon surpass the 100-crore mark upon verification of additional schemes by the ILO. India is also the first country globally to update its 2025 social protection coverage data in the ILOSTAT database, reinforcing its leadership in digital governance and transparency in welfare systems. Moreover, the increase in Social Protection Coverage will further strengthen India's global engagements, particularly in finalising Social Security Agreements (SSAs) with developed nations. These agreements will ensure the portability of social protection benefits for Indian professionals working overseas, while offering partner countries the transparency required for mutual recognition frameworks. This will further bolster India's position in trade and labour mobility negotiations by showcasing a credible and robust social protection regime.

Service Beyond Files & Courtrooms: The Department of Legal Affairs Donates Blood To Mark World Blood Donor Day

New Delhi, Focus News: In a meaningful initiative, the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, in collaboration with the Indian Red Cross Society, organised a Blood Donation Camp today at Shastri Bhawan, New Delhi, to commemorate World Blood Donor Day 2025. The camp was held in the esteemed presence of Dr. Anju Rathi Rana, Law Secretary, who encouraged voluntary blood donation as an enduring expression of compassion and community welfare.

Officers and staff members of the Department, including lady officers and senior officials, joined hands in contributing to this life-saving cause by actively participating as blood donors. The initiative resonated with this year's global theme: "Give Blood, Give Hope: Together We Save Lives." It highlighted the critical role of regular, voluntary and unpaid blood donations in ensuring a safe and sufficient blood supply for those in need. Observed globally on 14th June, World Blood Donor Day honours the invaluable contributions of voluntary blood donors whose selfless acts save countless lives and strengthen public health systems. Through this initiative, the Department of Legal Affairs reinforced its commitment to civic responsibility, public welfare and humanitarian service. The Department didn't just donate blood—it pumped life into its promise of public service.

1st Meeting of Task Force on Textiles Exports held under the Chairmanship of Commerce Secretary Sunil Barthwal

New Delhi, Focus News: The first meeting of the Task Force on Textiles Exports was held under the Chairmanship of Commerce Secretary, Shri Sunil Barthwal, at Vanijya Bhawan in Delhi on 10th June 2025 to discuss issues & strategies for enhancing textiles exports from India. The primary objective of setting up the Textiles Task Force is to create a unified platform for addressing critical issues concerning the textile sector by involving all relevant stakeholders. It would lead to active collaboration amongst all stakeholders to help resolve issues and formulate strategies for enhancing India's share of Textile exports in Global markets. The discussions during the meeting covered matters and issues pertaining to the entire textile value chain. This included issues related to the upgradation of ESG infrastructure in garment manufacturing units, use of renewable energy, European Union Deforestation Regulation (EUDR), strengthening of e-commerce for export growth and simplifying regulatory framework, labour, cost competitiveness for productivity enhancement, skilling, Branding, suggestions regarding Interest Subvention Schemes, assistance for Certification & Testing, collateral Support for export Credit for MSME Exporters, RoDTEP / RoSCTL / Duty Drawback, PM MITRA Parks, Development of new Jute Diversified Products (JDPs), Separate HS codes for GI Products, productivity enhancement of natural fibres such as jute and matters pertaining to the Export Promotion Mission being set up by Department of Commerce apart from other textiles export related issues. The meeting was attended by Special Secretary, Department of Commerce, Shri Rajesh Agrawal, Special Secretary, Department of Commerce, Shri L Satya Srinivas, Special Secretary & Financial Advisor, Department of Commerce Ms Arti Bhatnagar, Additional Secretary and Director General, DGFT, Shri Ajay Bhadoo, Additional Secretary Ministry of Textiles, Shri Rohit Kansal along with officials from related Departments & Ministries, Export Promotion Councils, Industry Associations and Exporters. Representatives of the various Textiles Export Promotion Councils and Industry Associations and their Exporter members provided their views and suggestions on the issues discussed. As an outcome of the deliberation, it was decided by the Chair that relevant sub-task forces would be formed on the issues. The sub-task force shall be led by the concerned Ministry along with participants from Export Promotion councils and the Industry to work on and provide actionable recommendations to the Task Force.

एस जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात की

पेरिस, फोकस न्यूज, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन के फ्रांस के मजबूत संदेश के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की भारत की नीति को रेखांकित करने के लिए यूरोप की यात्रा पर हैं। यह यात्रा गत 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में हो रही है। जयशंकर ने मुलाकात के बाद 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अभिवादन उन्हें प्रेषित किया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन के फ्रांस के मजबूत संदेश के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।" उन्होंने कहा, "हमारी चर्चाओं में हमारी रणनीतिक साझेदारी के प्रति विश्वास, सहजता और महत्वाकांक्षा की झलक मिली।" जयशंकर बुधवार को ब्रसेल्स में थे, जहां उन्होंने यूरोपीय संघ (ईयू) के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और ईयू–भारत रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद भारत ने 6–7 मई की रात को पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचों पर सटीक हमले किए।

भारत, यूरोपीय संघ व्यापार समझौते के लिए गैर–टैरिफ बाधाओं को दूर करना महत्वपूर्णः गोयल

स्टॉकहोम (स्वीडन), फोकस न्यूज, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए गैर–शुल्क बाधाओं का समाधान ढूंढना महत्वपूर्ण है और दोनों पक्ष इन मुद्दों के समाधान के लिए सक्रियता से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता को अंतिम रूप देने के ''काफी'' करीब हैं। गोयल ने यहां पत्रकारों से कहा, '' महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आधे से अधिक खंड तैयार हैं। विषय–वस्तु के संदर्भ में, मैं कहूंगा कि हम बाजार पहुंच के लिए करीब 90 प्रतिशत तैयार हैं। जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिया जाना है, वे हैं.. गैर–शुल्क बाधाएं और यूरोपीय संघ तथा भारत के बीच व्यापार को कैसे सहज, आसान व बेहतर बनाया जाए।'' उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ दोनों पक्षों की कंपनियों के लिए कारोबार को सुचारू बनाने के समाधान ढूंढने के लिए सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। मंत्री ने कहा, '' देश जब तक यह नहीं समझते कि व्यापार में अत्यधिक विनियमन एवं बाधाओं का जवाब, जवाबी कार्रवाई से दिया जाएगा तब तक सभी को नुकसान होगा। हम विनियमन को समाप्त करने, विनियमन की उच्च लागत, इन विनियमों के कारण उत्पन्न होने वाली गैर–शुल्क बाधाओं और मुक्त व्यापार में आने वाली बाधाओं का समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस समस्या का बहुत मजबूत समाधान खोज लेंगे।'' गोयल, स्वीडन की अपनी आधिकारिक यात्रा पर यहां पहुंचे है। इस यात्रा के दौरान वह दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्वीडन के अपने समकक्ष तथा कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। स्वीडन 27 देशों वाले यूरोपीय संघ का सदस्य है।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने दो लाख साइबर हमलों को विफल कियाः मनोहर लाल

श्रीनगर, फोकस न्यूज, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक सप्ताह में भारत की बुनियादी ऊर्जा अवसंरचना को निशाना बनाकर किए गए लगभग दो लाख साइबर हमलों को देश ने विफल कर दिया। मनोहर लाल ने यहां पत्रकारों से कहा, ''प्रौद्योगिकी में प्रगति के बाद से यहां– साइबर हमले या साइबर अपराध–जैसे नये खतरे सामने आए हैं। इनमें वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार ने इसपर काम किया है और हमारी साइबर सुरक्षा ने ऐसे सभी खतरों को लगभग रोक दिया है।'' वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)–नीत केंद्र सरकार के 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा, ''देश पर कई साइबर हमले हुए हैं। जहां तक ऊर्जा विभाग का सवाल है, करीब दो लाख साइबर हमलों का प्रयास किया गया, लेकिन हमारे साइबर विभाग ने उनमें से प्रत्येक को विफल कर दिया और कोई नुकसान नहीं हुआ।'' मनोहर ने कहा कि ये प्रयास ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के लगभग आठ से 10 दिनों के भीतर किए गए थे। यह पूछे जाने पर कि क्या ये हमले देश के भीतर से किए गए या फिर देश की सीमा से बाहर से किए गए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये हमले दुनिया के किसी भी कोने से हो सकते हैं। उन्होंने कहा, ''यह पूरी दुनिया को पता है कि हमारे खिलाफ लोग इस तरह की चीजें करेंगे, लेकिन... हमने ऐसे हमलों को रोक दिया है। हमारी प्रणाली सक्षम है और भविष्य में भी हम ऐसे सभी हमलों को विफल कर देंगे।''

बुनियादी ढांचे में 2030 तक 2200 अरब डॉलर के निवेश से सीमेंट उद्योग को काफी लाभ होगाः करण अदाणी

नयी दिल्ली, फोकस न्यूज, एसीसी के चेयरमैन करण अदाणी ने कहा कि 2030 तक बुनियादी ढांचे में अनुमानित 2200 अरब डॉलर के निवेश से सीमेंट उद्योग को काफी लाभ होने की उम्मीद है। अदाणी समूह के सीमेंट कारोबार का हिस्सा एसीसी सीमेंट ने अप्रैल 2025 में 10 करोड़ टन प्रति वर्ष क्षमता की उपलब्धि हासिल की है। करण अदाणी ने नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि एसीसी सीमेंट उज्जवल कल के लिए एक मजबूत, टिकाऊ नींव रखकर भारत के विकास में योगदान दे रही है। शेयरधारकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, '' भारत की 2030 तक आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्र में करीब 2200 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की जरूरत है। बुनियादी ढांचे के विकास के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में सीमेंट उद्योग को इन निवेशों से काफी लाभ होगा।'' उन्होंने कहा कि सीमेंट क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार की संभावना है और इसकी रणनीतिक प्राथमिकताएं इस क्षमता का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए तैयार की गई हैं। एसीसी, अंबुजा सीमेंट का हिस्सा है जो उद्योगपति गौतम अदाणी नीत अदाणी समूह के सीमेंट कारोबार का नेतृत्व करती है। करण अदाणी ने कहा, '' हमने अप्रैल 2025 में 10 करोड़ टन प्रति वर्ष सीमेंट क्षमता की उपलब्धि हासिल की जो हमें वित्त वर्ष 2027–28 तक हमारे 14 करोड़ टन प्रति वर्ष के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के करीब पहुंचाता है। भारत के सबसे तेजी से बढ़ते सीमेंट व्यवसाय के रूप में, हम एक उज्जवल कल के लिए एक मजबूत, टिकाऊ नींव रखकर इसके विकास में योगदान दे रहे हैं।'' वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय सीमेंट क्षेत्र में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद जाहिर की गई है जो सालाना आधार पर छह से सात प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2025–26 तक 47.5–48 करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंच सकता है।?

यूपीआई लेनदेन पर कोई एमडीआर शुल्क नहीं लिया जाएगाः वित्त मंत्रालय

नयी दिल्ली, (भाषा) वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) मंच के जरिये लेनदेन पर कोई 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' (एमडीआर) नहीं लेने की जानकारी दी है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा, '' यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर वसूले जाने की अटकलें और दावे पूरी तरह से झूठे, निराधार एवं भ्रामक हैं। इस तरह की निराधार और सनसनी फैलाने वाली अटकलें हमारे नागरिकों के बीच अनावश्यक अनिश्चितता, भय व संदेह उत्पन्न करती हैं। सरकार यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।'' एमडीआर वह लागत है जो व्यापारी द्वारा बैंक को अपने ग्राहकों से डिजिटल माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए चुकाई जाती है। व्यापारी छूट दर लेनदेन राशि के प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण उन खबरों के बाद आया है, जिनमें दावा किया गया था कि सरकार बड़े यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाने की योजना बना रही है। इस बीच, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मई में यूपीआई के माध्यम से लेनदेन 25.14 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले महीने की तुलना में पांच प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

उप्र सरकार 12 से 19 जून तक मनायेगी 'बाल श्रम निषेध सप्ताह'

लखनऊ, (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार 12 से 19 जून तक प्रदेश में 'बाल श्रम निषेध सप्ताह' मनायेगी।उम्मीद है कि 'यूनिसेफ' के सहयोग से मनाये जाने वाले कार्यक्रम से प्रदेश में बाल श्रम के समूल उन्मूलन की आवश्यकता एवं प्रयासों को बल मिलेगा। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर के हवाले से राज्य सरकार द्वारा बृहस्पतिवार को यहां जारी एक बयान के मुताबिक, सरकार आज से ही 'बाल श्रम निषेध सप्ताह' मनायेगी। इस अभियान का समापन 19 जून को लखनऊ में होगा। उन्होंने बताया कि इससे उत्तर प्रदेश में बाल श्रम के समूल उन्मूलन की आवश्यकता और प्रयासों को बल मिलेगा। एक सप्ताह के इस अभियान में यूनिसेफ उत्तर प्रदेश सरकार का भागीदार होगा। बयान के अनुसार, श्रम मंत्री राजभर ने स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) में बाल श्रम पर आयोजित एक महत्वपूर्ण सत्र में भाग लिया। राजभर ने कहा, " प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' के विजन से प्रेरित होकर भारत ने पिछले 11 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है।" उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज की ऐतिहासिक वृद्धि को मान्यता दी है और यह वर्ष 2015 में मात्र 19 प्रतिशत थी जो 2025 में बढ़कर 64.3 प्रतिशत हो गई है। मंत्री ने कहा कि भारत अब 94 करोड़ से अधिक नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान कर विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत में सामाजिक सुरक्षा का यह विस्तार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों, श्रमिकों एवं असंगठित क्षेत्र के हितों पर केंद्रित नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है।